[2016] 3 एस. सी. आर. 579

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और ओ. आर. एस.ध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं. 4060,2009)

02 मई, 2016

[अनिल आर. डेव, ए. के. सिकरी, आर. के. अग्रवाल, आदर्श कुमार गोएल और आर. भानुमती, जे. जे.]

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश) का विनियम अवाम शुल्क का निर्माण) अधिनियम, 2007-एस. एस. 3 (घ), 4,5,6,7,8,9,12,13-मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा और दंत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2009-आर। 9 - भारत का संविधान-कला। 19 (1) (छ) और 19 (6):

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की वैधता/अधिकार -

अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई-निजी गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल और डेंटल कॉलेज-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश, शुल्क निर्धारण, सीटों के आरक्षण, कला का उल्लंघन करने के आधार पर प्रवेश के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गई। 19 (1) (छ) राज्य विधानमंडल की क्षमता के आधार पर भी क्योंकि विषय वस्तु विशेष रूप से संसद के लिए आरक्षित थी-आयोजित: अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी यू/आर्ट द्वारा दी गई है। 19 (1) (छ)-अधिनियम अपीलार्थियों को दिए गए अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है, इस प्रकार, यू/आर्ट को संरक्षित किया गया। 19 (6) - अधिनियम और नियमों में शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधान कला का उल्लंघन नहीं करते हैं। 19 (1) (छ) निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण।

कला के साथ सामंजस्य। 15 (5) - राज्य के नियंत्रण में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करना स्वायत्तता को बाधित नहीं करता है ऐसे संस्थानों का-इसके अलावा, विवादित विधान राज्य की विधायी क्षमता से परे नहीं है-इस प्रकार, अधिनियम और नियम संवैधानिक रूप से वैध हैं-उच्च न्यायालय ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की वैधता को सही ठहराया।

शुल्क निर्धारण से संबंधित अधिनियम और नियमों में प्रावधान -

चुनौती-आयोजित: एस में निर्धारित मापदंड। 9 शुल्क तय करते समय ध्यान में रखना होगा-शुल्क लेने का सुझाव देना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं उक्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा-समिति को स्वयं को संतुष्ट करना है कि प्रभारित शुल्क मुनाफाखोरी के बराबर नहीं था या

शिक्षा का व्यावसायीकरण और यह बोधगम्य कारकों पर आधारित था

एस में उल्लिखित है। 9 (1) – यह केवल एक विनियामक उपाय है और यह अपने स्वयं के शुल्क तय करने के लिए शैक्षणिक संस्थान की शक्तियों को नहीं छीनता है इसलिए, यह देखने के लिए एक समिति का गठन करके शुल्क निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान कि संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले रहे हैं जो कैपिटेशन या मुनाफाखोरी के बराबर है, उचित प्रतिबंध हैं और किसी भी संवैधानिक बुराई से पीड़ित नहीं हैं।

साझा प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.) आयोजित करने की राज्य की शक्ति -

चुनौती-आयोजित: सी. ई. टी. योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता बढ़ाने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्रों के व्यापक हित और कल्याण में है। राज्य के नियंत्रण में सी. ई. टी. का होना इस स्वायत्तता को बाधित नहीं करता है-प्रवेश अभी भी इन संस्थानों के हाथों में है।

शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से योग्यता पर आधारित हैं।

विनियामक तंत्र-2007 के अधिनियम के तहत विनियम

रखने की आवश्यकता: 2007 के अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य है -

व्यापक लोक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश-उद्देश्य

राज्य के लिए संस्थानों की स्थापना शैक्षिक मानकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी कार्य है-लाभ का उद्देश्य

निजी संस्थानों द्वारा अपनाए जाने से बड़ी मात्रा में गोपनीयता और भ्रष्टाचार होता है-इस प्रकार, विवादित कानूनों के तहत विनियमों का तंत्र कानूनी, संवैधानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी है और योग्यता के प्राथमिक मानदंडों को बनाए रखता है-विनियम शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं और उन्हें वैध के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

भारत का संविधान।

कला. 19 (1) (छ) और 19 (6)-निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार-आयोजित:

इस अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता। 19 (1) (छ)-चार विशिष्ट अधिकार जो व्यवसाय के अधिकार को शामिल करते हैं, वे हैं-अधिकार छात्रों को प्रवेश देना; एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार; कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार (शिक्षण और गैर-शिक्षण); और किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही होने पर कार्रवाई करने का अधिकार-क्योंकि, आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य

शिक्षा को 'कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं' के आधार पर एक महान 'व्यवसाय' के रूप में माना जाता है, जो शिक्षा की स्थापना और प्रबंधन कर रहे हैं।

संस्थानों से इस महान गतिविधि में मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है। प्रवेश के अधिकार के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों को नहीं दिया गया

छात्रों और शुल्क का निर्धारण-यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है ये नियामक उपाय हैं जिन्हें ऐसे संस्थानों के संबंध में राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है। कला. 15 (5) , 19 (1) (छ), 19 (6), 30 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को चुनौती दी गई और

अन्य पिछड़े वर्ग-आयोजित: चूंकि इस न्यायालय ने पी. ए. इनामदार मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य द्वारा आरक्षण या सीटों के विनियोग का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए आरक्षण जो आरक्षण को अलग करता है,

अनुमति नहीं होगी-यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान राज्य कोटा स्थापित करने की उन्नी कृष्णन प्रणाली को वापस लाने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार, एससी/एसटी और ओ. बी. सी. के लिए सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 15 (5) के साथ।

कला. 254 सूची I प्रविष्टि 66, सूची III प्रविष्टि 25-विधायी

2007 के अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य की क्षमता-आयोजित: प्रविष्टि 66 सूची I मानकों के निर्धारण और समन्वय से संबंधित थी, और सूची II की मूल प्रविष्टि 11 ने राज्यों को शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की।

जिसे बाद में हटा दिया गया और प्रविष्टि 25, सूची III में संशोधन करके प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की गईं, सिवाय इसके कि प्रविष्टि 63 में विशेष रूप से शामिल किया गया था। सूची 1 के 66 तक-जब शिक्षा से संबंधित दो प्रविष्टियाँ, एक संघ सूची में और दूसरी समवर्ती सूची में, सह-मौजूद होती हैं, तो वे

यह स्पष्ट हो जाता है कि जब समन्वय और बिछाने की बात आती है उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक में मानकों को कम करना

और तकनीकी संस्थानों, राज्य विधानमंडलों को बाहर करने की शक्ति संघ/संसद के पास है-हालाँकि, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के शासन के संबंध में, यहां तक कि

राज्य विधानमंडलों को प्रविष्टि 25 के आधार पर शक्ति दी गई है-इस प्रकार, शिक्षा की स्वायत्तता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था

सी. ई. टी. में संस्थान जो राज्य या किसी एजेंसी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं

राज्य द्वारा नामित या शुल्क निर्धारित करने में-ऐसा करने का राज्य का अधिकार [2016] 3 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय कानून के अधीन-एम. पी. निजी व्यवसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियम अवाम शुल्क का निर्माण) अधिनियम, 2007

मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2009।

सिद्धांत: आनुपातिकताक सिद्धान्त। स्पष्टीकरण और अनुप्रयोग-आयोजित: यह जांच करते हुए कि क्या क़ानून और नियमों के विवादित प्रावधान उचित प्रतिबंधों के बराबर हैं,

और आम जनता के हित में हैं, आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया जाता है-यह जारी रखने के मौलिक अधिकार का संतुलन है

किसी कानून द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को सीमित करने के लिए पर्याप्त शर्तें जो संवैधानिक रूप से अनुमत हों - दो तथ्यों के बीच संतुलन-उन पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ

यह एक कानून द्वारा, 'आनुपातिकता' की अवधारणा, एक उचित मानदंड है - विवादित प्रावधान जो 'अपने' व्यवसाय 'को जारी रखने के लिए संस्था के अधिकार पर प्रतिबंध' के बराबर हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से 'उचित' हैं और आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट करते हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: पर सीकरी, जे. (अपने लिए, डेव जे., अग्रवाल जे., गोयल जे., और भानुमति जे.)

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार। न्यायालय ने चार विशिष्ट अधिकारों का वर्णन किया जिसमें कब्ज़ा करने का अधिकार शामिल है। (i) छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार; (ii) उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार; (iii) कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार (शिक्षण)

और गैर-शिक्षण); और (iv) कार्रवाई करने का अधिकार यदि कोई है किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य का निष्कासन। छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार की उक्त मान्यता और व्यवसाय के हिस्से के रूप में एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के अधिकार को देखते हुए

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त। [पारस 32,33] [627-सी, एफ-जी।

1.2 शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के रूप में मानते हुए।

मध्य प्रदेश राज्य

एक 'व्यवसाय' के रूप में, न्यायालय स्पष्ट था कि इस गतिविधि को 'व्यवसाय' या 'व्यवसाय' के रूप में नहीं माना जा सकता है। शिक्षा के समान व्यवसाय को जारी रखने के इस अधिकार को अन्य व्यवसायों या व्यावसायिक गतिविधियों या यहां तक कि अन्य पेशेवर व्यवसायों के बराबर नहीं रखा गया है।

सत्र। यह एक अलग श्रेणी है जिसे इस न्यायालय द्वारा टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में बनाया गया था। एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं था ऐसा करना। शिक्षा को 'लाभ नहीं, हानि नहीं' के आधार पर एक महान 'व्यवसाय' के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, जो लोग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन कर रहे हैं, उनसे मुनाफाखोरी में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है

इस महान गतिविधि को बढ़ावा देना या उसका व्यावसायीकरण करना। इस उद्देश्य को बनाए रखना

यह ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय ने छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार और शुल्क निर्धारण के संबंध में भी शैक्षणिक संस्थानों को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी। जहां तक छात्रों के प्रवेश का संबंध है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रवेश उच्च शिक्षा, विशेष रूप से व्यावसायिक संस्थानों में योग्यता के आधार पर होने चाहिए। [पैरा 34] [628-ए-डी]

1.3 यह देखने के लिए कि योग्यता को उपयुक्त और उचित माना जाता है

उचित रूप से, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि विज्ञापन मिशन के लिए प्रक्रिया इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी होने के तिहरे परीक्षण को संतुष्ट करे। ऐसी योग्यता होनी चाहिए।

यह या तो उन अंकों से निर्धारित किया जाएगा जो छात्रों ने क्वालीफाइंग परीक्षा में या संस्थानों द्वारा आयोजित सी. ई. टी. में या पेशेवर कॉलेजों के मामले में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए थे। [पैरा 36] [628-एच; 629-ए-बी]

1.4 यह निवेदन कि विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके, राज्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने के कार्य को हड़प नहीं सकता है; और

कि इसका मतलब केवल यह था कि इस तरह की सी. ई. टी. का संचालन स्वयं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाना है और सरकार कर सकती है

केवल ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को विनियमित करने के लिए विनियम बनाएँ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित किया जा सकता है और सी. ई. टी. आयोजित करने के कार्य को कुछ मानदंडों के संबंध में पी. ए. इनामदार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट और स्पष्ट व्याख्या को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में। [पारस 38,39] [630-सी-डी]

1.5 यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य यह साबित करने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकता है कि योग्यता से समझौता किया गया था या कैपिटेशन शुल्क लगाया जा रहा था

आरोप लगाया। लेखापरीक्षा के बाद के उपाय नियामक री [2016] 3 एस. सी. आर. को पूरा नहीं करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माँगें। प्रारंभिक चरण में ही नियंत्रण की आवश्यकता थी। यद्यपि 'व्यवसाय' एक मौलिक अधिकार है, जो शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है, साथ ही, ऐसे अधिकारों के दायरे को विच्छेदित किया गया है और इन अधिकारों पर सीमाओं की प्रकृति को समझाते हुए उक्त निर्णयों द्वारा उन पर सीमाएं लगाई गई हैं।

[पैरा 43] [632-जी-एच; 633-ए]

1.6 विवादित कानून और नियम कुछ सख्ती लागू करते हैं। टी. एम. ए. पाई में घोषणा को ध्यान में रखते हुए

फाउंडेशन, पी. ए. इनामदार में इस न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ, यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक इस तरह के विनियामक उपायों का संबंध है, इसे राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों के संबंध में भी अपनाया जा सकता है। [पारस

44 , 48] [633 - बी; 636-II; 637-ए]

1.7 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

खंड (6) के अधीन। कथित उल्लंघन किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए

प्रतिबंध, प्रतिबंध की सीमा और अन्य प्रासंगिक कारक। इन कारकों को लागू करने में, कोई भी निर्देश की दृष्टि नहीं खो सकता है

राज्य नीति के सिद्धांत। न्यायालय को मौलिक अधिकारों और व्यापक हित के बीच एक उचित संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। समाज से। न्यायालय एक क़ानून में हस्तक्षेप करता है यदि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि विधानमंडल लोगों की जरूरतों को समझता है। द कॉन

व्यवस्था मुख्य रूप से आम आदमी के लिए है। योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार, शुल्क और प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय की बड़ी रुचि और कल्याण को निश्चित रूप से विनियमित किया जा सकता है। [पैरा 50] [637-सी-ई]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2002 (3) पूरक। एससीआर 587: (2002) 8 एससीसी 481 -

समझाया और भरोसा किया।

पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एससीसी 537-निर्भर

पर।

सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1991 (3) पूरक। एससीआर 121: (1992) 1 एससीसी 558-प्रतिष्ठित।

उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। वी.

आंध्र प्रदेश राज्य आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य

& ओआरएस। 1993 (1) एससीआर 594: (1993) 1 एस. सी. सी. 645; बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला और अनर: 1957 एससीआर 874 ; इस्लामी अकादमी या शिक्षा और अनर। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2003 (2) पूरक। एससीआर 474: (2003) 6

एस. सी. सी. 697-संदर्भित।

आनुपातिकता का सिद्धांत:

2.1 राज्य को इससे संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार है -

किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यताएँ।

नेस। इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या क़ानून और नियमों के विवादित प्रावधान उचित प्रतिबंधों के बराबर हैं और आम जनता के हित में लाए गए हैं, एक ओर व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार और दूसरी ओर लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन करना आवश्यक है। इसी को 'आनुपातिकता का सिद्धांत' कहा जाता है। न्यायशास्त्रीय रूप से, 'आनुपातिकता' को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार की सीमा के लिए आवश्यक और उपयुक्त शर्तों को निर्धारित करने वाले नियमों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

किसी कानून द्वारा संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय होना। [पैरा 53] [638-डी-एफ]

2.2 दोनों तथ्यों के बीच उचित संतुलन के लिए। एक कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकारों और सीमाओं की अवधारणा

' आनुपातिकता ', जो एक उचित मानदंड है। सटीक शब्दों में कहें तो जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक होती है यदि वह आनुपातिक हो। प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत हैं।

उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और ऐसे उपाय आवश्यक हैं। द. इसलिए, जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए है जो

एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक और इस तरह के अभ्यास में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन शामिल है, और

अंतत: आनुपातिकता अर्थात विभिन्न हितों के संतुलन पर आधारित मूल्यांकन। [पैरा 56,57] [640-एफ-जी; 641-एफ]

2.3 आनुपातिकता का सिद्धांत, अनुच्छेद में निहित है

19 स्वयं खंड (1) में उसके खंड (6) के साथ। यह परिभाषित करते हुए कि एक उचित प्रतिबंध क्या है, यह माना गया है कि 'उचित प्रतिबंध' अभिव्यक्ति किसी भी उप द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है।

*

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 19 के खंड (1) के खंड और खंड (2) से (6) में से किसी द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण। यह माना जाता है कि 'उचित' अभिव्यक्ति का अर्थ है कि अधिकार के आनंद में किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा मनमाना या मनमाना नहीं होनी चाहिए।

अत्यधिक प्रकृति जनता के हित में आवश्यकता से परे है। इसके अलावा, उचित होने के लिए, प्रतिबंध का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है, और उस उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, किसी प्रतिबंध की तर्कसंगतता को वस्तुनिष्ठ तरीके से और आम जनता के हितों के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं या अमूर्त पर।

विचार करें। [पैरा 58] [641-जी-एच; 642-ए-बी] 2.4 टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में यह आयोजित किया गया था कि इस तरह के सी. ई. टी. के संचालन की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया जा सकता है।

पी. ए. इनामदार में संतुलन न केवल उल्लेखनीय रूप से हासिल किया गया था सी. ई. टी. को रोकने के लिए इसे समय से पहले देना लेकिन यह आगे चला गया

मान लीजिए कि सी. ई. टी. का संचालन करने वाली एजेंसी वह होनी चाहिए जिसे इस मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता प्राप्त हो। पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति और उस उद्देश्य के लिए इसने राज्य को निष्पक्ष और योग्यता आधारित सुरक्षा के हित में सी. ई. टी. आयोजित करने की प्रक्रिया प्रदान करने की अनुमति दी।

प्रवेश और कुप्रशासन को रोकना। [पैरा 60] [643-EF]

2.5 व्यापक लोकहित इस तरह के उपाय की गारंटी देता है। सी. ई. टी. में देखे गए कदाचारों को ध्यान में रखते हुए

स्वयं ऐसे निजी संस्थानों द्वारा संचालित, जिनके लिए

बहुत सारी सामग्री का उत्पादन किया जाता है, यह निस्संदेह, छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण में योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता बढ़ाने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए है। प्रतिबंध की सीमा को इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए और इसलिए, विवादित प्रावधान जो प्रतिबंधों के बराबर हो सकते हैं। अपीलार्थियों का अपना 'व्यवसाय' जारी रखने का अधिकार स्पष्ट रूप से 'उचित' है और आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट करता है। [पैरा 61] [643

जी-एच; 644-ए]

2.6 संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि

भारी शुल्क लेकर प्रवेश लेने में शोषण की तस्वीर कैपिटेशन शुल्क और योग्यता से समझौता।

यह सभी आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v पर लागू नहीं हो सकता है।

मध्य प्रदेश राज्य

संस्थाएं लेकिन अगर विधानमंडल जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाया गया है जो आम तौर पर प्रचलित है, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी भी नियामक उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अधिनियम अपने वातावरण में एक जीव है। कानून अवधारणाओं का अधिष्ठान नहीं है, बल्कि जरूरतों, हितों और मूल्यों का रोजमर्रा का जीवन है, जिसे एक निश्चित समय में समाज साकार करना चाहता है। कानून एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य समाज में मनुष्य की समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। [पैरा 62] [644-बी-सी]

2.7 उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्लेषण किया है कि

अधिनियम के प्रावधानों और पाया कि योग्यता आधारित प्रवेश और शुल्क निर्धारण के लिए प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ

निजी संस्थानों का प्रवेश कराने और शुल्क तय करने का मौलिक अधिकार। उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है और यह माना जाता है कि अधिनियम और नियमों में निहित प्रवेश से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के खिलाफ नहीं हैं। [पैरा 63] [644-डी-ई]

आर. वी. ओक्स (1986) 1 एससीआर 103; पी. पी. उद्यम और अन्य।

वी. भारत संघ और अन्य। 1982 (3) एससीआर 510: (1982) 2 एस. सी. सी. 33; हनीफ कुरेशी मोहम्मद। वी. बिहार राज्य 1959

एससीआर 629; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम इंस्पेक्टर केरल सरकार। 1998 (2) पूरक। एससीआर 632: (1998) 8 एससीसी 227; टी. एम. ए. पाई

फाउंडेशन और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2002 (3) पूरक। एससीआर 587: (2002) 8 एस. सी. सी. 481; इस्लामी अकादमी या शिक्षा और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2003 (2) पूरक। एससीआर 474: (2003) 6 एससीसी 697; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 2005

(2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एस. सी. सी. 537;-संदर्भित।

आनुपातिकता: संवैधानिक अधिकार और उनके

अहरोन बराक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस 2012 द्वारा सीमा; न्यायमूर्ति फ्रैंकफ्युटर: ' वैधानिक निर्माण पर एक परिचर्चा: फॉरवर्ड ', 3, वांड एल. रेव. 365,367 (1950)

- संदर्भित किया गया।

शुल्क निर्धारण से संबंधित अधिनियम नियमों में प्रावधान हैं:

असंवैधानिक होना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है?

3.1 अधिनियम, 2007 की धारा 9 को देखने पर यह पाया जाता है [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि शुल्क निर्धारित करते समय जिन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे वास्तव में वही हैं जो इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित किए गए हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति, अर्थात् प्रवेश और शुल्क नियामक समिति, केवल नियामक कार्यों का निर्वहन कर रही है। वह शुल्क जो एक विशेष

शैक्षणिक संस्थान जो अपने छात्रों से शुल्क लेना चाहता है, उसे उक्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही सुझाव दिया जाना चाहिए। द.

समिति को इस उद्देश्य से अधिकार दिया गया है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था और यह इस पर आधारित था -

अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित बोधगम्य कारक। इसलिए, यह केवल एक नियामक उपाय है और अपने स्वयं के शुल्क तय करने के लिए शैक्षणिक संस्थान की शक्तियों को नहीं छीनता है। [पैरा

74] [650 - बी-डी] 3.2 राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली सरकारी परीक्षा के माध्यम से छात्रों के प्रवेश से संबंधित प्रावधान और यह देखने के लिए एक समिति का गठन करके शुल्क निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान कि संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले रहे हैं जो कैपिटेशन या मुनाफाखोरी के बराबर है, उचित प्रतिबंध हैं और किसी भी संवैधानिक बुराई से पीड़ित नहीं हैं। इसलिए अधिनियम और नियमों का प्रावधान पी. ए. इनामदार में निहित भावनाओं और निर्देशों के अनुरूप है। विचाराधीन अधिनियम किसी भी मौजूदा केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं है। जहाँ तक ए की शुरुआत की बात है

राष्ट्रीय स्तर पर सी. ई. टी. का संबंध है, इसे राज्य क़ानून के संचालन की अवधि के दौरान लागू नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में, इन संस्थानों के शुल्क के निर्धारण या निर्धारण के संबंध में कोई नियम नहीं होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं देते हैं, राज्य विधानमंडल उसी के संबंध में प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। [पैरा 74,75] 652-बी-डी]

3.3 जब समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और जब ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थान राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं महत्वाकांक्षी संवैधानिक वादों को लागू करने की चुनौती का सामना करने के लिए प्रबंधित शैक्षणिक संस्थान, मामले की जांच एक अलग रंग में की जानी है। यह वह आत्मा है जिसमें रखा जाता है।

इन शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को संतुलित करते हुए ध्यान रखें

एक ओर उन्हें अनुच्छेद 19 (1) (जी) और दूसरी ओर आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v के तहत दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य

विवादित विधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता। प्रवेश का अधिकार या इन अपीलार्थियों को गारंटीकृत शुल्क तय करने का अधिकार पूरी तरह से नहीं लिया गया है, जैसा कि आशंका है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन ऐसे संस्थानों को स्वायत्तता देता है जो बरकरार रहते हैं। सी. ई. टी. को राज्य के नियंत्रण में रखना इस स्वायत्तता को बाधित नहीं करता है। प्रवेश अभी भी इन संस्थानों के हाथों में है। एक बार जब अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है कि छात्रों के प्रवेश में 'ट्रिपल टेस्ट' पूरा किया जाना है, तो विवादित कानून का उद्देश्य यही है। आखिरकार, सीईटी आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य योग्यता का निर्णय लेना और यह सुनिश्चित करना है कि

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होते हैं। यह फिर से व्यापक जनहित सुनिश्चित करने के लिए है। यह समझ से परे है कि केवल शक्ति ग्रहण करके

क्योंकि वे छात्र जो अन्यथा मेधावी हैं लेकिन कैपिटेशन शुल्क आदि की अनुचित मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, वे प्रवेश प्राप्त करने से वंचित नहीं हैं। इसलिए, विवादित प्रावधानों का उद्देश्य व्यापक जनता में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना है ब्याज। कानून स्थिर नहीं है, इसे बदलते समय और बदलती सामाजिक/सामाजिक स्थितियों के साथ बदलना पड़ता है। [पैरा 84] [655-एच; 656 ए-ई]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और ओआरएस। 2002 (3) पूरक। एससीआर 587: (2002) 8 एससीसी 481; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एस. सी. सी. 537; उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और

ओआरएस। 1993 (1) एससीआर 594: (1993) 1 एस. सी. सी. 645 1 इस्लामी अकादमी या शिक्षा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2003 (2) पूरक। एससीआर 474: (2003) 6 एस. सी. सी. 697; मॉडर्न स्कूल बनाम। भारत संघ 2004 (1) पूरक। एससीआर

668 : (2004) 5 एस. सी. सी. 583-संदर्भित।

विनियामक तंत्र की आवश्यकता:

4.1 इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यह संवैधानिक [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लक्षय महत्वपूर्ण बना हुआ है जो इसे उद्देश्य के रूप में अन्य आर्थिक गतिविधियों के विपरीत विशिष्ट और विशिष्ट बनाता है।

शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना है और इस प्रकार एक बेहतर समाज बनाना है क्योंकि इसका उद्देश्य बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना है जो राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में योगदान देगा। समाज के कल्याण की अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूती से लागू होगी। अन्यथा भी, क्योंकि

अर्थशास्त्री, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में शिक्षा, कृषि जैसी अन्य आर्थिक चिंताओं की तुलना में अनुकूल

और उद्योग का अपना निवेश और उत्पादन होता है और इस प्रकार इसका विश्लेषण वापसी के नियमों जैसे बुनियादी आर्थिक उपकरणों के संदर्भ में किया जाता है।

समतुल्य उपयोगिता और सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत। इन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, राज्य को शिक्षा में उस बिंदु तक निवेश करना चाहिए जहां शिक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ अन्य राज्य के खर्चों के बराबर हो, जबकि व्यक्ति को एक प्रकार की शिक्षा के लिए भुगतान करने के अपने निर्णय में उसे प्राप्य लाभ की संभावना से निर्देशित किया जाता है। ये सभी विचार

एक स्थिर नियामक तंत्र की स्थापना के लिए एक मामला बनाएँ।

[पैरा 83] [655-डी-जी]

4.2 निजी महाविद्यालय संघ अपने आयोजन करने में विफल रहा

निजी कार्यों के मामले में किया गया है। तुलनात्मक दक्षता पर भी यह स्पष्ट है कि राज्य की प्रक्रिया तैयार की गई प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष है निजी महाविद्यालयों द्वारा जिनके पास किसी भी नियंत्रण और संतुलन का कोई तंत्र नहीं है। राज्य की एजेंसियां सूचना का अधिकार अधिनियम, लेखा परीक्षा, राज्य विधानमंडल, भ्रष्टाचार-रोधी के अधीन हैं।

अभिकरण, लोकायुक्ता आदि। [पैरा 88] [658-सी-ई] 4.3 राज्य के लिए संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ही एक कल्याणकारी कार्य है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

मानक। दूसरी ओर, निजी के लिए प्राथमिक प्रेरणा पार्टियाँ लाभ का उद्देश्य या परोपकार हैं। जब संस्थानों के लिए प्राथमिक प्रेरणा लाभ का उद्देश्य है, तो यह स्वाभाविक है कि कई

इसे प्राप्त करने का साधन निजी द्वारा अपनाया जाएगा

पी.

(आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य

संस्थान जो बड़ी मात्रा में गोपनीयता की ओर ले जाते हैं और भ्रष्टाचार। इस प्रकार, विवादित कानूनों के तहत परिकल्पित विनियमों का तंत्र कानूनी, संवैधानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी है और योग्यता के प्राथमिक मानदंडों को बनाए रखता है। यह शिक्षा की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

संस्थाओं और इस तरह के रूप में वैध के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए। [पैरा 89] [658 एफ-जी]

4.4 शिक्षा के व्यवसाय को अन्य आर्थिक गतिविधियों के बराबर नहीं माना जा सकता है। इस क्षेत्र में, राज्य मूक दर्शक नहीं रह सकता है और निजी क्षेत्र द्वारा शोषण, निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाना होगा। यहां तक कि उन आर्थिक गतिविधियों के संबंध में जो निजी क्षेत्र द्वारा अनिवार्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं (और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है), जबकि इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को निजी क्षेत्र के हाथों में देते हुए, राज्य ने विनियामक व्यवस्था भी शुरू की है।

संबंधित कानूनों के तहत विनियम। [पैरा 78] [653-एफ-जी]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और

ओआरएस। 2002 (3) पूरक। एससीआर 587: (2002) 8 एस. सी. सी. 481-पर निर्भर।

III. री. : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण

5. चूंकि पी. ए. इनामदार में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य द्वारा आरक्षण का कोई निर्धारण या सीटों का विनियोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए आरक्षण जो कोटा को अलग करता है, अनुमति है। यह निवेदन कि प्रावधान राज्य कोटा स्थापित करने की उन्नीकृष्णन प्रणाली को वापस लाने का प्रयास करते हैं जो

संविधान में, नियम, 2008 के नियम 4 (2), 7 और 15 के साथ पठित धारा 8 को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी गई थी। वास्तव में, अपीलार्थियों के वकील ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनौती नहीं दी थी 93 अनुच्छेद 15 (5) को संविधान में शामिल करते हुए संविधान का पहला संशोधन किया गया। किसी भी मामले में, शायद ही कोई है

उक्त संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का आधार, जिसे पहले ही [2016] 3 एस. सी. आर. में संविधान पीठ के फैसले द्वारा बरकरार रखा जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रमती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का मामला। दूसरा निवेदन कि नियम 7 में आरक्षण प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि उक्त प्रतिशत का पता लगाना मुश्किल होगा

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्नातकोत्तर में सीटों की संख्या ने विभिन्न विशेष विषयों में दंत चिकित्सा और चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शामिल किया

कम ही हैं। उच्च न्यायालय ने आरोपों के माध्यम से उचित रूप से प्रदर्शित करते हुए इस तर्क को सफलतापूर्वक निपटाया कि न केवल विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण की सीमा का पता लगाना संभव था, बल्कि पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध थीं।

सामान्य श्रेणियों के लिए भी। इस प्रकार, चाल में कोई योग्यता नहीं है।

एस. सी./एस. टी. और ओ. बी. सी. आदि के लिए सीटों के आरक्षण जो अनुच्छेद 15 (5) के अनुरूप है। [पैरा 87] [657-एफ-एच; 658-ए बी]

प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (पंजीकृत) और

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। 2014 (11) एससीआर 712:

(2014) 8 एस. सी. सी. 1-फॉलो किया गया।
पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एस. सी. सी. 537; उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और

ओआरएस। 1993 (1) एससीआर 594: (1993) 1 एससीसी 645-संदर्भित

को।

क्या विवादित कानून मध्य प्रदेश राज्य की विधायी क्षमता से परे है?

6.1 सूची I में प्रविष्टि 66 एक बहुत ही विशिष्ट प्रविष्टि है।

और सीमित दायरे में। यह उच्च शिक्षा या अनुसंधान के साथ-साथ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण से संबंधित है। 'समन्वय और मानकों का निर्धारण' शब्दों का अर्थ होगा उक्त मानकों को निर्धारित करना। इस प्रकार, जब उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों के लिए मानकों को निर्धारित करने की बात आती है, तो संघ को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। हालाँकि, इसमें संचालन शामिल नहीं होगा

परीक्षा आदि और ऐसे संस्थानों में छात्रों का प्रवेश

या उच्च शिक्षा के इन संस्थानों में शुल्क निर्धारित करना,

आदि। वास्तव में, जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है, इस तरह के समन्वय और मानकों के निर्धारण को प्राप्त किया जाता है

भारतीय चिकित्सा परिषद के रूप में संसदीय कानून

अधिनियम, 1956 और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसे वैधानिक निकाय का निर्माण करके। एम. सी. आई. को सौंपे गए कार्यों में आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v शामिल हैं।

मध्य प्रदेश राज्य

एक चिकित्सा संस्थान में मानकों का व्यापक निर्धारण साथ ही मानकों और शैक्षणिक संस्थानों का समन्वय। जब इस तरह की 'शिक्षा' को विनियमित करने की बात आती है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं (जो

उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं), जो सूची III की प्रविष्टि 25 में निर्धारित है, जिससे संघ के साथ-साथ राज्यों दोनों को समवर्ती शक्तियां मिल रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों सहित पूर्व शिक्षा, सूची II में प्रविष्टि 11 का विषय था। इस प्रकार, इस हद तक शक्ति राज्य विधानमंडलों को दी गई थी। हालाँकि, इस प्रविष्टि को संविधान द्वारा हटा दिया गया था (बयालीस संशोधन) अधिनियम, 1976 3 जुलाई, 1977 से प्रभावी हुआ और उसी समय सूची II में प्रविष्टि 25 में संशोधन किया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय की शिक्षा सहित शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।

और इस प्रक्रिया में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को भी जोड़ा गया। इस प्रकार, यदि अपीलार्थियों का निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह प्रविष्टि 25 को पूरी तरह से अनुचित बना सकता है। जब दो प्रविष्टियाँ संबंधित हों

शिक्षा, एक संघ सूची में और दूसरी समवर्ती सूची में, सह-अस्तित्व में है, उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस तरीके से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानकों को निर्धारित करने की बात आती है, तो शक्ति टिकी रहती है

संघ/संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के बहिष्करण के साथ। हालांकि, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा के अन्य पहलुओं के साथ-साथ

विश्वविद्यालयों का संबंध है, यहां तक कि राज्य विधानसभाओं को भी दिया जाता है प्रविष्टि 25 के आधार पर शक्ति। प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया गया क्षेत्र

सूची III काफी व्यापक है और सीमित सीमा तक सीमित है। यह सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के अधीन है। [पैरा 93] [659-जी; 660-ए-जी]

6.2 स्वायत्तता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था

सी. ई. टी. में शैक्षणिक संस्थान राज्य या राज्य द्वारा नामित एजेंसी या शुल्क तय करने में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा करने का राज्य का अधिकार केंद्रीय कानून के अधीन है। एक बार सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय कानूनों के तहत अधिसूचनाओं को 'एनईईटी' कहा जाता है प्रभावी होने पर, राज्यों और संघ के बीच एक मामला होगा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 254 की कसौटी पर सुलझाया जाएगा। [पैरा 98] [663-ए-बी]

भारती विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय) और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्र. 2004 (2) एससीआर 775:

एस. सी. सी. 755-आंशिक रूप से खारिज।
गुजरात विश्वविद्यालय और अन्र. वी. श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य। 1964 ( ) 1 एस. सी. आर. 112; डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्र। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। 1999 (1) पूरक। एससीआर 249: (1999) 7 एस. सी. सी. 120; आर. चित्रलेखा बनाम राज्य

मैसूर (1964) 6 एस. सी. आर. 368; टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य वी. अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य।

1995 (2) एससीआर 1075: (1995) 4 एस. सी. सी. 104; राज्य

महाराष्ट्र बनाम. संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र
महाविदालय और अन्य। 2006 (3) एससीआर 638: (2006) 9 एस. सी. सी. 1; मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन और

ओआरएस। 1982 (1) एससीआर 759: (1981) 4 एस. सी. सी. 296; अजय कुमार सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1994) 4 एससीसी

401 - संदर्भित किया गया।

7.1 इस न्यायालय ने पहले सभी राज्यों में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समितियों की नियुक्ति की थी।

जब तक उपयुक्त कानून नहीं बनाया जाता और एक बार प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती एक वैधानिक कानून के तहत नियामक के उचित कामकाज के विषय पर सभी संबंधितों की शिकायतें लागू हो जाती हैं।

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और सिफारिशें करना। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुधारों का सुझाव दिया चिकित्सा द्वारा चिकित्सा पेशे का नियामक निरीक्षण

परिषद। समिति ने एम. सी. आई. की जांच की। यह देखा गया कि एमसीआई को बार-बार अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में कमी पाई गई। एमसीआई में भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए यह था

उन्होंने सिफारिश की कि कानून में संशोधन करने और एक नया कानून बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली असंतोषजनक पाई गई। [पारस 99,100] [663 ई-एफ; 664-ए, एच]

7.2 उपयुक्त कार्यपालिका में विचाराधीन या

विधायिका स्तर पर, एक निगरानी समिति स्थापित करने की आवश्यकता है एम. सी. आई. के कामकाज और संसदीय समिति द्वारा विचार किए गए अन्य सभी मामलों की देखरेख के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है।

निर्देश आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v हैं। मध्य प्रदेश राज्य

एक निरीक्षण समिति के गठन के लिए जारी किया गया। ने कहा कि

समिति के पास सभी वैधानिक कार्यों की देखरेख करने का अधिकार होगा।

एमसीआई अधिनियम के तहत। एम. सी. आई. के सभी नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होगी।

उचित उपचारात्मक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र। समिति ने जब तक केंद्र सरकार कोई अन्य व्यवस्था नहीं करती, तब तक काम करेगी।

विशेषज्ञ के उचित विचार के बाद उपयुक्त तंत्र

समिति की रिपोर्ट। [पारस 102,103,105] [669-सी-डी, जी-एच]

टी. देवदासन बनाम भारत संघ और एएनआर: (1964) 4 एससीआर 680; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महारास और ओआरएस का राज्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एससीसी 537; एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। (1993) सप. 1 एस. सी. आर. 439; अशोक कुमार ठाकुर बनाम संघ का

भारत और ओआरएस। 2007 (4) एससीआर 493: (2007) 4 एस. सी. सी. 361; भारतीय चिकित्सा संघ बनाम। भारत संघ और अन्य।
2011 (6) एससीआर 599: (2011) 7 एस. सी. सी. 17 9; बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला और अमर। 1957 एससीआर 874; आर. वी. ओक्स (1986) 1 एससीआर 103; पी. पी. उद्यम और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। 1982 (3) एससीआर

510: (1982) 2 एस. सी. सी. 33; हनीफ कुरेशी मोहम्मद। वी. बिहार राज्य 1959 एससीआर 629; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम इंस्पेक्टर केरल सरकार। 1998 (2) पूरक। एससीआर 632: (1998) 8 एस. सी. सी. 227 संदर्भित है।

प्रति भानुमति, जे। (पूरक):

अधिनियम 2007 को लागू करने के लिए राज्य की विधायी क्षमता का अभाव

जैसा कि संघ सूची की प्रविष्टि 66 द्वारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है:

1.1 संघ सूची की प्रविष्टि 66 में 'समन्वय' और 'उच्च शिक्षा में मानकों का निर्धारण' शब्द हैं -

संसद का संरक्षण। 'समन्वय' शब्द का अर्थ है

समन्वित कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से सामंजस्य। 'उच्चतर संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण' शब्द

· 'शिक्षा' समन्वय के उद्देश्य से है

देश भर में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थान।

शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वर्तमान वितरण को देखते हुए, उस राज्य की शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, जिसमें शामिल हैं -

तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय " संघ के समान। हालाँकि, ऐसी शक्ति विषय [2016] 3 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ सूची की प्रविष्टियाँ 63,64,65 और 66, जैसा कि प्रविष्टि में निर्धारित किया गया है

25 समवर्ती सूची। यह केंद्र की जिम्मेदारी है।

उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए सरकार और इसे किसी विशेष राज्य के हाथों कम नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 16] [680-डी-एफ]

1.2 सूची I के तहत, संघ की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों के निर्माण और समन्वय के संबंध में है। " उच्च शिक्षा में मानक का निर्धारण "

इसका तात्पर्य यह है कि संसद को उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऐसे मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है। द.

अभिव्यक्ति में समन्वय और मानकों का निर्धारण

'उच्च शिक्षा' का अर्थ है कि यह संसद को लेना है। मानकों को बनाए रखने की दिशा में ठोस कार्रवाई। इसका कारण।

प्रविष्टि 66 के साथ केंद्रीय विधानमंडल को सशक्त बनाने के लिए

- यह सुनिश्चित करना कि उच्च शिक्षा के मानकों को किसी विशेष राज्य के हाथों राष्ट्रीय प्रगति के नुकसान के लिए कम नहीं किया गया था और राज्य द्वारा प्रयोग की गई शक्ति सीधे तौर पर कम नहीं हुई थी।

संघ प्रविष्टि 66 की शक्ति का अतिक्रमण करना। [पैरा 18] [682-ए-सी]

1.3 संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत संघ की शक्ति है

उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने तक सीमित

शिक्षा के स्तर में एकरूपता के बारे में

देश को। इस प्रकार, प्रविष्टि 66 का दायरा सीमित माना जाना चाहिए। उच्च स्तर के मानकों को निर्धारित करने के अपने वास्तविक अर्थ में

शिक्षा 'और प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने की नहीं। किसी भी मामले में नहीं।

क्या राज्य को 25 की प्रविष्टि के तहत कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित किया गया है

सूची III. अधिक तो, में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित

उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय। [पैरा 29] [692-एच; 693

ए]

: :

1.4 विवादित कानून के अधिकार जो सशक्त बनाते हैं

राज्य सरकार में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए

राज्य के भीतर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को बरकरार रखा जाता है। वास्तव में, राज्य के लोगों के कल्याण और विकास के लिए जिम्मेदार होने के कारण, राज्य को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अपने छात्र समुदाय का कल्याण। 'उच्च शिक्षा' का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो विकास को सीधे प्रभावित करता है और

राज्य का विकास, ऐसे कदम उठाना राज्य का विशेषाधिकार बन जाता है जो लोगों के कल्याण को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में, राज्य प्रक्रिया निर्धारित करने वाली एकमात्र इकाई सरकार होनी चाहिए।

" '

मैं

!

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य

में चल रहे संस्थानों को नियंत्रित करने वाले प्रवेश और शुल्क आदि के लिए

आई. आई. टी., एन. आई. टी. आदि जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को छोड़कर वह विशेष राज्य क्योंकि किसी विशेष राज्य के लोगों की आवश्यकताओं और अवसर में असमानताओं का उस राज्य से बेहतर न्यायकर्ता कोई नहीं हो सकता है। केवल राज्य का कानून ही आने वाले छात्रों के लिए समान स्तर का अवसर पैदा कर सकता है

राज्य बोर्ड और अन्य धाराओं से बाहर। [पैरा 30] [693-बी-ई]

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्र। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। 1999 (1) पूरक। एससीआर 249: (1999) 7 एस. सी. सी. 120; गुजरात विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. वी. श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर

& ओआरएस। 1963 ( ) 1 एस. सी. आर. 112; आर. चित्रलेखा और अन्र।

वी. मैसूर राज्य और अन्य। (1964) 6 एससीआर 368;

शैक्षिक समाज और अन्य। 2003 (5) पूरक। एससीआर 408: (2004) 1 एससीसी 86; टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य वी. अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य। 1995 (2)
एससीआर 1075: (1995) 4 एस. सी. सी. 104; विश्वेश्वरैया

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. वी. कृष्णेन्दु हलदर

& ओआरएस। 2011 (2) एससीआर 1007: (2011) 4 एस. सी. सी. 606; अंबेश कुमार (डॉ.) बनाम। प्राचार्य, L.L.R.M. मेडिकल कॉलेज,

मेरठ और ओआरएस। 1987 एससीआर 661: (1986) पूरक एस. सी. सी. 543;

टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य वी. एस. वी. ब्रतीप (नाबालिग) और अन्य। 2004 (2) एससीआर 1218: (2004) 4 एस. सी. सी. 513-संदर्भित।

ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश 7 वीं संस्करण। ; काले का कानून
शब्दकोश 10 वीं संस्करण। ; संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश 10 वीं संस्करण, संशोधित; रामनाथ अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकन 3 जी संस्करण। - संदर्भित किया गया।

क्या विवादित कानून उचित है

अनुच्छेद 19 (6) के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत "व्यवसाय":

2.1 पूर्ण 'कब्जे के अधिकार' का दावा जो

अपीलकर्ताओं ने टी. एम. ए. पाई, पी. ए. इनामदार के आधार पर मुद्दा उठाया है।

मामले टिकाऊ नहीं हैं। टी. एम. ए. पाई और पी. ए. इनामदार में, नहीं निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा को निर्बाध अधिकार दिया गया था

सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित वैधानिक विनियमों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना व्यापार और व्यवसाय करने के लिए संस्थान।

एक शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

मौलिक अधिकार नियंत्रण के बिना नहीं है और यह होगा

हमेशा उचित प्रतिबंधों के अधीन रहें जो राज्य व्यापक सार्वजनिक हित में लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। [पैरा 34] [694-जी

एच; 695-ए]

2.2 एम. पी. अधिनियम 2007 "निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और शुल्क निर्धारण के विनियमन" के लिए अधिनियमित किया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना। इस प्रकार अधिनियम, 2007 उन पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए है।

प्रवेश में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य

मेधावी उम्मीदवार जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं शिक्षा. अधिनियम, 2007 राज्य को सामान्य संचालन करने में सक्षम बनाता है।

उच्च मानकों को प्राप्त करने के हित में प्रवेश परीक्षा

चिकित्सा शिक्षा ताकि गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा सके राष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति। [पैरा 35] [695-डी-ई]

2.3 पी. ए. इनामदार में, राज्य सरकारों को उप-क्षेत्रों पर एक विस्तृत सुविचारित कानून बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

एक और अवलोकन के साथ जेक्ट कि द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय

· समितियाँ और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रहेगा।

ऐसी अधिकारिता के प्रयोग के लिए। विवादित कानून

इस प्रकार अधिनियम 2007 निर्देश के अनुपालन में अधिनियमित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा टी. एम. ए. पाई, इस्लामी अकादमी और

पी. ए. इनामदार में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से

प्रवेश प्रक्रिया। [पैरा 44] [702-ई-एफ]।

श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स एंड ओआरएस। v, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। 1983 (3) एससीआर 843: (1983) 4 एस. सी. सी. 353; नरेंद्र कुमार और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर 1960 एस. सी 430: 1960 एससीआर 375; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम

निरीक्षक, केरल सरकार और अन्य। 1998 (2) पूरक। एससीआर 632: (1998) 8 एस. सी. सी. 227; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो एयर 1952 एस. सी. 196: 1952 एससीआर 597; के. के. कोचुनी बनाम मद्रास राज्य और केरल ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1080

संदर्भित किया गया।

सामान्य प्रवेश परीक्षा-एकल खिड़की प्रणाली जो इसे नियंत्रित करती है

गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश

उन लोगों के मौलिक अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है संस्थान:

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य

3.1 मध्य प्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रचलित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने अपने विवेक में यह विचार रखा है कि योग्यता आधारित प्रवेश केवल इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। एक सामान्य प्रवेश परीक्षा जिसके बाद राज्य द्वारा या राज्य द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा केंद्रीकृत परामर्श दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए इच्छुक आवेदकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, विधायिका द्वारा

विवादित कानून ने पारदर्शी आधार पर योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.) की प्रणाली शुरू की। यदि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हैं

अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने का निरंकुश अधिकार दिए जाने पर, यह ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां यह उन छात्रों के "समानता के अधिकार" पर अतिक्रमण करेगा जो प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं।

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा सभी मेधावी और उपयुक्त उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करेगी और मेधावी उम्मीदवारों की पहचान अध्ययन के पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या और अन्य के आधार पर विभिन्न संस्थानों में आवंटित किए जाने के लिए की जा सकती है।

प्रासंगिक कारक। यह जुड़वां वस्तुओं को सुनिश्चित करेगा: - (i) निष्पक्षता और पारदर्शिता और (ii) भ्रष्टाचार को रोकने के अलावा योग्यता प्रशासन। इस प्रकार, योग्यता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुराचारों पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, राज्य को केंद्रीकृत और एकल खिड़की प्रक्रिया प्रदान करके प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति होगी। इस तरह के सी. ई. टी. का आयोजन करने के बाद

केंद्रीकृत परामर्श या एकल खिड़की प्रणाली विनियमन प्रवेश से संस्थान के संचालन में संस्थानों के मौलिक अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है। जबकि निजी

शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में शिक्षण संस्थानों को 'व्यवसाय का अधिकार' है, उतनी ही उनकी भी जिम्मेदारी है उत्कृष्टता के साथ पेशेवरों को लाने के लिए मेधावी और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना। निजी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को समुदाय के व्यापक हित के लिए स्वीकार करना होगा।

[पैरा 48] [704-सी-एच; 705-ए-बी]

3.2 सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करके और मेधावी उम्मीदवारों की पहचान करके, राज्य केवल निष्पक्ष सामान्य परीक्षा के आधार पर तैयार की गई उम्मीदवारों की योग्यता सूची प्रदान कर रहा है।

प्रवेश परीक्षा। यदि जांच परीक्षा योग्यता के आधार पर आयोजित की जाती है, [2016] 3 एस. सी. आर.

निजी शिक्षण संस्थानों को कोई नुकसान नहीं होगा। संस्थानों के स्वीकृत प्रवेश में छात्रों के प्रवेश पर न तो प्रतिबंध है और न ही छात्रों से शुल्क लेने के उनके अधिकार पर। निजी शैक्षणिक संस्थानों की संस्था स्थापित करने और चलाने, शिक्षा प्रदान करने, कर्मचारियों की भर्ती

करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, छात्रों को प्रवेश देने, शुल्क निर्धारण में भाग लेने की स्वतंत्रता को किसी भी तरह से विवादित कानून द्वारा कम नहीं किया जा रहा है; यह बरकरार है। [पैरा 49] [705-बी-डी]

गुमन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 452; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। ,

1984 (3) एससीआर 942: (1984) 3 एससीसी 654; मृदुल धर मामला 2005 (1) एससीआर 380: (2005) 2 एससीसी 65-संदर्भित

को।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश 11 वां संस्करण; पी. रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश 3 रा संस्करण। – संदर्भित
को।

प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करते समय, न्यायालय को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा:

4.1 किसी भी क़ानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता तय करने या किसी भी मौलिक अधिकार के प्रयोग पर कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करने के लिए, अदालत

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। एक कानून या उपाय जिसे बढ़ावा देने या प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है निर्देशात्मक सिद्धांतों को आगे बढ़ाना अपने आप में उचित और जनहित में है। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव को अधिक से अधिक जनता या लोगों के खिलाफ संतुलित करे।

सामाजिक हित। [पैरा 50] [705-ई-एफ]

4.2 संविधान के तहत यह राज्य का दायित्व है कि वह अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्माण सुनिश्चित करे

बुनियादी उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य के प्रावधानों सहित

स्वस्थ जीवन और काम करने की स्थितियों की सेवाएं और आश्वासन। संविधान के अनुच्छेद 39 (ई), 39 (एफ) और 42 के तहत, श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दायित्व डाला गया है।

पुरुष और महिलाएँ; सुनिश्चित करें कि बच्चों को अवसर दिए जाएं और

एक स्वस्थ तरीके से विकसित करने और काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए सुविधाएं। संविधान का अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।

एफ. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य

राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। हालाँकि, स्वास्थ्य का अधिकार अब संविधान के भाग IV के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का रखरखाव और सुधार और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और

चिकित्सा सेवाएँ राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, राज्य के पास होना चाहिए

पेशेवर उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता वाले डॉक्टर जो बड़े पैमाने पर जनता को चिकित्सा सलाह और सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। राज्य अपने संवैधानिक दायित्व का संतोषजनक निर्वहन तभी कर सकता है जब इच्छुक छात्र योग्यता के आधार पर पेशे में प्रवेश करें। इन उच्च आदर्शों में से कोई भी अच्छे और प्रतिबद्ध चिकित्सा पेशेवरों के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। [पारस 51,52] [706 ई-जी; 707-बी-सी]

बॉम्बे और अन्र राज्य। वी. एफ. एन. बलसारा (1951) एस. सी. आर. 682; गुजरात राज्य बनाम। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब

जमात और ओआरएस। 2005 (4) पूरक। एससीआर 582: (2005) 8 एससीसी

बीमा निगम। 1996 (1) एससीआर 884: (1996) 2 एस. सी. सी. 682; राजस्थान प्रदेश वैद्य समिति, सरदारशहर और
एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 2010 (7) एससीआर 252: (2010) 12 एस. सी. सी. 609; सार्वजनिक हित केंद्र

मुकदमेबाजी v. भारत संघ (2013) 9 एससीआर 1103

संदर्भित किया गया।

निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के मौलिक अधिकार

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित और छात्रों के अधिकारों के प्रति झुकना चाहिए:

5. निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने और एक के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार

गैर-मनमाना, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों का एक मौलिक अधिकार है। कोई भी कानून जो निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों और अन्य संस्थानों के बीच एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाता है और इसमें असमानता पैदा करता है

प्रवेश का मामला जिसके तहत एक मेधावी छात्र को निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश से केवल इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि ऐसे संस्थान को एक निरंकुश अधिकार है।

एक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन किए बिना अपने छात्रों का चयन करना अधिकारों का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत इच्छुक छात्रों के लिए। निजी गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने का छात्रों का अधिकार है

अवसर में समानता का अधिकार। कई मौकों पर, इसने [2016] 3 एस. सी. आर. का नेतृत्व किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक ओर निजी शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकारों और दूसरी ओर छात्रों और बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों के बीच संघर्ष। ऐसे मामलों में जहां दो पक्षों के मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होता है, केवल वही अधिकार प्रबल होगा जो सार्वजनिक नैतिकता या सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएगा जब कोई मौलिक अधिकार समाज के व्यापक हित के साथ टकराव करता है, तो उसे बाद वाले को देना चाहिए। नागरिकों या समुदाय के वर्ग का हित, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो, बड़े पैमाने पर राष्ट्र की जनता के हित और छात्रों के योग्यता-आधारित व्यावसायिक प्रवेश के अवसर का लाभ उठाने के अधिकार के लिए गौण है।

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जनहित को आगे बढ़ाएंगे

और इस प्रकार छात्रों के अधिकार निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर हावी होंगे। [पैरा 53] [707-डी-एच; 708-ए-बी]

शारदा बनाम. धर्मपाल 2003 (3) एससीआर 106: (2003) 4 एस. सी. सी. 493; कुरैशी कसाब जमात और अन्य। 2005 (4) पूरक।

एससीआर 582: (2005) 8 एस. सी. सी. 534-संदर्भित।

यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर

शैक्षणिक संस्थान तीन परीक्षणों-निष्पक्षता, पारदर्शिता और गैर-शोषण में विफल रहे:

6. शिकायतों और मुकदमों की संख्या को देखते हुए,

ऐसी सामग्री, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया को अपने हाथ में लेना राज्य के लिए उचित नहीं होगा। यह इंगित करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों ने पी. ए. इनामदार में निर्धारित ट्रिपल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ऐसा नहीं है। राज्य की ओर से 2007 के अधिनियम के साथ आना अनुचित लगता है जो सामान्य संचालन के लिए एक तंत्र निर्धारित करता है।

योग्यता आधारित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश परीक्षा निजी संस्थान। [पारस 55,56] [709-बी-सी; 710-बी-सी]

प्रिया गुप्ता बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य। 2012 (5) एससीआर 768: (2012) 7 एस. सी. सी. 433-संदर्भित।

क्या शुल्क निर्धारण के संबंध में अधिनियम 2007 के प्रावधान निजी शिक्षा के 'व्यवसाय के अधिकार' का उल्लंघन करते हैं

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य

संस्थान:

7.1 यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि उनके "अधिकार" का प्रयोग करते हुए

निजी संस्थान छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से, अधिनियम प्राधिकरण को शुल्क निर्धारित करने की बेलगाम शक्ति नहीं देता है। शुल्क का निर्धारण

अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित कारकों पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम में अपील करने का अवसर भी प्रदान किया गया है

दुखी हैं। महाविद्यालयों के अपने प्रशासन को चलाने के मौलिक अधिकारों में शुल्क का निर्धारण शामिल है। हालाँकि, इस तरह के अधिकार को छात्रों के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, ताकि

वे मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन नहीं हैं। [पैरा 69] [717-सी-डी]

7.2 राज्य के पास आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए विवादित कानून-2007 अधिनियम को लागू करने की विधायी क्षमता है व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और शुल्क निर्धारित करने के लिए और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से बरकरार रखा है

विवादित विधान की वैधता। आम लोगों द्वारा प्रवेश पर विवादित कानून द्वारा लागू किए जाने वाले विनियम

राज्य द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा और शुल्क का निर्धारण टी. एम. ए. के निर्देशों और टिप्पणियों के अनुपालन में किया जाता है। पाई, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन और पी. ए. इनामदार। प्रवेश प्रक्रिया पर नियम व्यापक जनहित और छात्र समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक हैं ताकि प्रवेश में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और योग्यता और योग्यता को बढ़ावा दिया जा सके।

उत्कृष्टता। शुल्क निर्धारण पर विनियमन मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन हुए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। विवादित कानून की वैधता बरकरार है और उचित निर्णय लिया गया है उच्च न्यायालय की पुष्टि की जाती है। [पैरा 70] [717-ई-जी]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2002 (3) पूरक। एससीआर 587: (2002) 8 एस. सी. सी. 481; इस्लामी अकादमी या शिक्षा और अन्र। वी. की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। 2003 (2) पूरक। एससीआर 474: (2003) 6 एससीसी 697; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 603: (2005) 6 एससीसी 537 -

पर भरोसा किया।

मॉडर्न स्कूल वी। भारत संघ 2004 (1) पूरक।

एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

668 : (2004) 5 एस. सी. सी. 583 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

सीकरी का बचाव, जे।

(1964) 4 एससीआर 680

संदर्भित किया गया है

(1993) सप. 1 एससीआर 439

संदर्भित किया गया है

2007 (4) एससीआर 493

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

1993 (1) एससीआर 594

2003 (2) पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2011 (6) एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

2004 (1) पूरक। एससीआर 668

1957 एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

2002 (3) पूरक। एससीआर 587

और समझाएँ

उस पर भरोसा करें

2005 (2) पूरक। एससीआर 603

1991 (3) पूरक। एससीआर 121

विशिष्टता

(1986) 1 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

1982 (3) एससीआर 510

उस पर भरोसा करें

1959 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

1998 (2) पूरक। एससीआर 632

पीछा किया।

2014 (11) एससीआर 712

1964 ( ) 1 एस. सी. आर. 112

संदर्भित किया गया है

1999 (1) पूरक। एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

(1964) 6 एससीआर 368

संदर्भित किया गया है

1995 (2) एससीआर 1075

जी. ई. और अनुसंधान केंद्र आध्या प्रदेश को संदर्भित किया गया

संदर्भित किया गया है

पैरा 96

पैरा 96

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 96

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा 97

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 34.

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

पैरा

53 [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2012 (5) एससीआर 768

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

2004 (1) पूरक। एससीआर 668

उस पर भरोसा करें

2002 (3) पूरक। एससीआर 587

पैरा 70

उस पर भरोसा करें

2003 (2) पूरक। एससीआर 474

पैरा 70

उस पर भरोसा करें

पैरा 70

2005 (2) पूरक। एससीआर 603

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 4060

2009 .

उच्च न्यायालय के 15.05.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2009 की लिखित याचिका संख्या 2732 में

के साथ

सी. ए. सं. 4061 , 4062 , 4063 , 4064 , & 4065 2009 से।

के. के. वेणुगोपाल, डॉ. राजीव धवन वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत जैन, मनु

माहेश्वरी, सुश्री अंकिता गुप्ता, छाया कीर्ति, अपूर्व तरण जैन, कबीर घोष (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), सुश्री प्रगति नीखरा, अमलपुष्प श्रोती, रोहित भट, आर. प्रभाकरण, एस. बेनो बेंसिगर, सुश्री माया कृष्णन (सुश्री मंजू जेटली के लिए), जसबीर सिंह मलिक (सुश्री उषा नंदिनी वी के लिए), बी. के. सतीजा, पुनीत जैन (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), मैसर्स। एपी एंड जे चैम्बर्स, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., विकास सिंह, सुश्री विभा दत्ता मखीजा,

पी. एन. मिश्रा, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। सी. डी. सिंह (ए. जी.), अजय शर्मा, आर. एस. नगर, सुश्री रेखा पांडे, सुश्री सुनीता शर्मा, अमित शर्मा, आर. के. राठौर, एस.

एस. रावत, अजय कुमार सिंह, एम. पी. गुप्ता, करण सेठ, संचित कुमार, ऋषभ जैन, आर. आर. राजेश (डी. एस. माहरा के लिए), गौरव शर्मा, सुश्री दीपिका कालिया, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री अमनदीप कौर, कपीश सेठ, वारा गौर, मिश्रा सौरभ, अंकित कुमार लाल, सुश्री दिशा वैश, आर. सी. कोहली, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अभिषेक कुमार

सिंह, अभिषेक कुमार, सुश्री साक्षी कक्कड़, सुश्री सिलोना महापात्रा, एस. एस. शमशेरी, अमित शर्मा (सुश्री रुचि कोहली के लिए), वी. जी. प्रगसम, प्रभु रामसुब्रमण्यन, सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा (तारा के लिए) चंद्र शर्मा), कृष्ण श्रीनिवासन, ई. आर. कुमार, सुश्री गीथी आरा, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, अनुराग त्रिपाठी (मेसर्स के लिए)। पी. एच. पारेख), एल. आर. सिंह, राकेश के. शर्मा, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अर्पित राय, संजय के. अग्रवाल, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सुनील कुमार जैन,

अभिनव मुखर्जी, हरीश पांडे, अमित कुमार, पवनश्री अग्रवाल, आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य

सुश्री पूनम कुमारी, प्रेम सुंदर झा, सी. के. सुचरिता, सुश्री चारू माथुर, राजीव रंजन द्विवेदी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अनिल कुमार मिश्रा-आई, के. के. मणि, रमेश बाबू एम. आर., रवींद्र केशवराव अदसुरे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

ए. के., सिकरी, जे. 1. इन सभी अपीलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की प्रधान पीठ द्वारा पारित 15 मई, 2009 के सामान्य निर्णय की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। इन अपीलों में अपीलकर्ताओं ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के प्रावधानों की वैधता/अधिकार को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिसे 'निजिवासायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियम अवाम शुल्क का निर्माण) अधिनियम, 2007' (इसके बाद) के रूप में जाना जाता है।

'अधिनियम, 2007' के रूप में संदर्भित)। अपीलकर्ताओं ने प्रवेश नियम, 2008 (संक्षेप में, 'नियम, 2008') और मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार को भी चुनौती दी।

परीक्षा नियम, 2009 (संक्षेप में, 'नियम, 2009') जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 2007 की धारा 12 के माध्यम से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम और नियम

निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश को मुख्य रूप से विनियमित करना और प्रावधान भी हैं शुल्क निर्धारित करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा, उक्त अधिनियम और नियमों में सीटों के आरक्षण के प्रावधान भी हैं। सभी अपीलार्थी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं जो गैर-सहायता प्राप्त हैं, यानी उन्हें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है।

सरकारी सहायता और स्व-वित्तपोषित संस्थान हैं जो अपने स्वयं के कोष से चल रहे हैं।

2. विवादित फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि

अपीलार्थियों द्वारा अधिनियम और नियमों के उन प्रावधानों को चार आधारों पर चुनौती दी गई थी। वही नीचे दिए गए हैं:

((i) प्रवेश से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देना;
((ख) शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देना।

((ग) आरक्षण के प्रावधानों को चुनौती देना; और

((iv) प्रवेश के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधानों को चुनौती।

3. जहां तक प्रवेश, प्रवेश के लिए पात्रता और शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह था कि ये मेडिकल और डेंटल कॉलेज निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनका मौलिक अधिकार है कि वे प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करें और छात्रों के साथ-साथ उनकी फीस भी तय करें। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। ' , यह तर्क दिया गया कि शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के अधिकार को एक 'व्यवसाय' के रूप में मान्यता दी गई है और इस प्रकार,

अनुच्छेद 19 (1) (जी) में निर्धारित इस तरह के व्यवसाय को जारी रखने का एक मौलिक अधिकार है। अपीलार्थियों के अनुसार, उपरोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधान इन संस्थानों को निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं -

संविधान और इसलिए, उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं। जहाँ तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का संबंध है, अपीलकर्ताओं का दो गुना जोर था: सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि निजी शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने के दायित्व के साथ लागू नहीं किया जा सकता है, जो कि राज्य का दायित्व था। दूसरा, अधिनियम, 2007 के प्रावधानों ने अत्यधिक आरक्षण दिया जिससे अनारक्षित श्रेणियों के लिए शायद ही कोई सीट बची हो, जो कि नहीं है।

टी. देवदासन बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अनुज्ञेय। भारत संघ और Anr.[2] और बाद के निर्णयों में इस आदेश को दोहराया गया

जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर हमले का आधार वही है। इसके अतिरिक्त, हालांकि, उक्त अधिनियम और नियमों के लिए चुनौती है राज्य विधानमंडल की क्षमता के आधार पर भी हमारे सामने रखा गया है, क्योंकि अपीलार्थियों के अनुसार, विषय वस्तु में आता है

ऐसा क्षेत्र जो विशेष रूप से संसद के लिए आरक्षित हो। 4. उच्च न्यायालय ने पहले तीन मामलों में चुनौती को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय, जैसा कि में समझाया गया है।

पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और Ors.[3], सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश के साथ-साथ शुल्क को विनियमित करने की अनुमति देता है और यह कि विवादित प्रावधान हैं: संविधान के अनुच्छेद 19 (6) द्वारा सुरक्षित किया गया है क्योंकि वे प्रवेश और शुल्क के निर्धारण के अधिकार पर लगाए गए 'उचित प्रतिबंधों' के बराबर हैं, जो अन्यथा अपीलार्थियों के पास निहित हैं।

1 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 2 (1964) 4 एस. सी. आर. 680 3 3 (2005) 6 एस. सी. सी. 537 आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

5. इससे पहले कि हम अपने समक्ष पेश की गई अपीलार्थियों की दलीलों का विस्तार से विज्ञापन करें, अधिनियम, 2007 के साथ-साथ नियम, 2008 और नियम, 2009 के प्रावधानों का सार देना उचित होगा और यह भी कि उच्च न्यायालय ने किस तरह से मुद्दों से निपटा है।

अधिनियम, 2007:

6. अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि इसका प्रावधान करना है -

मध्य प्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और शुल्क निर्धारण का विनियमन और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना। इस प्रकार, जहां तक प्रस्तावना का संबंध है, यह निर्धारित करता है कि प्रवेश के विनियमन और शुल्क के निर्धारण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम में सभी विषयों के निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं और यह चिकित्सा और दंत चिकित्सा व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है। हालांकि, उपरोक्त अधिनियम के खिलाफ शिकायत केवल चिकित्सा और दंत चिकित्सा द्वारा दायर की गई थी

शैक्षणिक संस्थान। अन्य प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान दुखी नहीं हुए हैं।

7. जो भी हो, प्रवेश और निर्धारण को विनियमित करने के लिए

अधिनियम की धारा 4 के तहत शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए 'प्रवेश और शुल्क नियामक समिति' (इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित) के रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन किया जाता है।

और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से शुल्क निर्धारित करने के लिए

किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश। यह खंड

इसके अलावा समिति के गठन, अयोग्यता और कार्यों का प्रावधान है।

8. अध्याय III जिसमें धारा 5 से 8 शामिल हैं -

' प्रवेश '। धारा 5 के अनुसार, इस तरह के प्रवेश के लिए पात्रता

संस्थान ऐसे होंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए।

ये पात्रता शर्तें नियम, 2008 में प्रदान की गई हैं। धारा 6

'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (संक्षेप में, 'सी. ई. टी.') निर्धारित करता है जिसके आधार पर प्रवेश किए जाएंगे और यह नीचे दिया गया है:

" 6. सामान्य प्रवेश परीक्षा-निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर में
शैक्षणिक संस्थान, स्वीकृत प्रवेश में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर इस तरह से होगा जो हो सके

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "।

सी. ई. टी. को अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी) में परिभाषित किया गया है और यह इस प्रकार है:

" (घ) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" का अर्थ है एक प्रवेश परीक्षा, जो उम्मीदवारों की योग्यता के निर्धारण के लिए आयोजित की जाती है, जिसके बाद राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा एकल खिड़की प्रक्रिया के माध्यम से पेशेवर कॉलेजों या संस्थानों में योग्यता आधारित प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीकृत परामर्श दिया जाता है।

धारा 7 के अनुसार, अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के विपरीत की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को अमान्य माना जाना चाहिए। धारा 8 'सीटों के आरक्षण' से संबंधित है।

9. जहाँ तक शुल्क निर्धारण का संबंध है, शुल्क निर्धारित करते समय जिन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे धारा 9 में दिए गए हैं।

जो अधिनियम के अध्याय IV के तहत है और निम्नानुसार है:

" 9. कारक-(1) ध्यान में रखते हुए -

(i) निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक का स्थान

संस्था;

((ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

((ग) भूमि और भवन की लागत;

((iv) उपलब्ध आधारभूत संरचना, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और

उपकरण;

((v) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय;

(vi) विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष

व्यावसायिक संस्थान; और

(vii) कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य, समिति निर्धारित तरीके से, किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करेगी।

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान।

(2) समिति संस्थान को एक अवसर देगी -

कोई भी शुल्क तय करने से पहले सुना जाना:

बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क, जो समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं होगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकार ने नियम, 2009 बनाए हैं।

शुल्क के निर्धारण के लिए विस्तृत प्रावधान बनाना, जिसके लिए हम होंगे

उचित स्तर पर उल्लेख करना।

10. एक अन्य प्रावधान जिसका इस स्तर पर उल्लेख करने की आवश्यकता है, वह है -

धारा 10. इस प्रावधान में ऐसी अपील का प्रावधान है जिसे आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा दायर किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

के आदेश से व्यथित व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था समिति। ऐसी अपील उक्त प्रावधान के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। धारा 12 के तहत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। धारा 13 राज्य सरकार को अधिनियम और बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार देती है।

इसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पेशेवर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश के तरीके और सीटों के आवंटन से संबंधित, जिसमें सीटों का आरक्षण भी शामिल है, साथ ही साथ पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण के तरीके या मानदंड और पेशेवर द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से संबंधित है।

शैक्षणिक संस्थान। 11. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 28 फरवरी, 2009 और 15 मार्च, 2009 को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 2007 की धारा 6 के तहत परिपत्र/अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, भोपाल (जिसे व्यपम के रूप में जाना जाता है) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

निजी चिकित्सा और दंत विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा और स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा

क्रमशः।

द इम्प्यूज्ड जजमेंट

प्रवेश से संबंधित प्रावधान का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी) के साथ पठित धारा 6 के प्रावधान, जो यह प्रदान करते हैं कि स्वीकृत प्रवेश के लिए प्रवेश सी. ई. टी. के आधार पर होगा, जिसके बाद राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा केंद्रीकृत परामर्श दिया जाएगा, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं। इनामदार। उच्च न्यायालय ने टी. एम. ए. के पैराग्राफ 58 और 59 को पुनः प्रस्तुत किया।

पाई फाउंडेशन, जिसमें इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाना है, जो आमतौर पर या तो योग्यता परीक्षा या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के चरण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के बाद साक्षात्कार या संस्थान द्वारा आयोजित सीईटी या पेशेवर कॉलेजों के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एजेंसियां। इससे, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि योग्यता को प्रमुख विचार और मान्यता प्राप्त तरीकों में से एक होना चाहिए।

योग्यता का निर्धारण सी. ई. टी. के माध्यम से और पेशेवर कॉलेजों [2016] 3 एस. सी. आर. के रूप में किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित हैं, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन ने स्वयं सरकारी एजेंसियों द्वारा इस तरह के सी. ई. टी. के संचालन की अनुमति दी थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था विवादित प्रावधान। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के पैराग्राफ 67 और 68 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित को तैयार करने की अनुमति दी थी -

राज्य द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटों के हिस्से को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को पी. ए. इनामदार में अनुच्छेद 133 से 138 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि प्रवेश में उत्कृष्टता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए, राज्य राष्ट्रीय हित में कदम उठा सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। इस निर्णय ने इस शक्ति को मान्यता दी

निजी शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में भी ऐसे सी. ई. टी. आयोजित करने के लिए राज्य सरकार। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने दर्दनाक टिप्पणी की कि निजी संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और गैर-शोषण की तिहरी कसौटी को पूरा करने में विफल रही है, जिससे राज्य को इसे प्रतिस्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा: प्रत्यर्थियों द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रिया और पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि अधिनियम, 2007 के अधिनियमन से पहले, निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में कदाचार की कई शिकायतें थीं जिन्हें पाया गया था

सच है।

संक्षेप में, उच्च न्यायालय ने यह राय ली कि छात्र समुदाय के कल्याण के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ावा दिया जाए

योग्यता, उत्कृष्टता प्राप्त करना, कदाचार पर अंकुश लगाना और योग्यता का अनुदान प्राप्त करना।

पारदर्शी तरीके से प्रवेश के आधार पर, विधानमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रचलित शर्तों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन अधिनियम को अपने विवेक से पारित किया था। इस प्रकार, इसने इस पहलू पर निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), 6 और 7 को जारी रखने के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करती है।

' व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का व्यवसाय संस्थाएं।

13. निर्धारण से संबंधित प्रावधानों की चुनौती से निपटना

शुल्क का, अर्थात। विचाराधीन अधिनियम की धारा 4 (1), 4 (8) और 9, उच्च आधुनिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य (ए. के. सिकरी, जे.)

अदालत ने इन शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को मान्यता दी, जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में पाया गया है, कि शुल्क लेने का निर्णय निजी शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना है। इसके बावजूद, वही निर्णय राज्य को शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने की शक्ति देता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुनाफाखोरी न हो और अधिनियम, 2007 की धारा 4 और 9 का उद्देश्य उस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

यह अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था। न्यायालय ने नोट किया कि ये कारक जिनका उल्लेख धारा में किया गया था 9 (1) शुल्क के निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक थे क्योंकि उन्होंने इस तरह के शुल्क का निर्धारण सुनिश्चित किया जो पेशेवरों की प्रकृति को ध्यान में रखेगा।

पाठ्यक्रम, भूमि और भवन की लागत, उपलब्ध बुनियादी ढांचा, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और उपकरण, प्रशासन पर खर्च और रखरखाव के साथ-साथ व्यावसायिक संस्थानों के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष। ठीक यही बात थी

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन का आदेश। 14. आरक्षण से संबंधित अधिनियम, 2007 के प्रावधानों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्धारित उक्ति पर चर्चा की

एम. आर. बालाजी और अन्य में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। + जिसमें इस न्यायालय की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) की व्याख्या करते हुए कहा कि उक्त प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर समाज के हित को कम करने के लिए किया गया था और इस प्रकार, यह राज्य को ऐसे कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है। एकमात्र अपवाद यह था कि ऐसा विशेष

राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रावधान को समाज के बाकी हिस्सों को पूरी तरह से बाहर नहीं करना चाहिए और उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, इस तरह का प्रावधान करते समय, राज्य को अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से और तर्कसंगत तरीके से करना था और उसे मदद करने के लिए उचित और उदार कदम भी उठाने होते हैं।

कमजोर तत्वों की प्रगति; बड़े पैमाने पर समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक सूत्र विकसित किया जाना चाहिए जो कई प्रासंगिक विचारों के बीच एक उचित

संतुलन बनाए। इसी तरह, संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड (5) को शामिल करने के बाद, राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नति के लिए कानून द्वारा कोई भी विशेष प्रावधान करने का अधिकार देने वाला एक और सक्षम प्रावधान पेश किया गया था।

(1993) सप.

1

एससीआर 439 [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिकों के पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के लिए जहां तक ऐसा विशेष प्रावधान निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के संदर्भ में, राज्य को आरक्षण प्रदान करने का अधिकार था -

अल्पसंख्यक संस्थानों सहित गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में भी ऐसे कमजोर वर्ग। उस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने

विभिन्न विषयों या विषयों में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए नियम, 2009 के नियम 7 के तहत निर्धारित की गई सीटों का अंकगणित और उस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन श्रेणियों में सीटों का वितरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनारक्षित के लिए भी पर्याप्त संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं

15. नियम, 2009 का नियम 10 स्नातकोत्तर चिकित्सा में प्रवेश के लिए सीईटी लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है। मध्य प्रदेश राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम। नियम 10 (2) (iii) में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों में से एक यह है कि एक योग्य उम्मीदवार को 30 अप्रैल, 2009 को या उससे पहले मध्य प्रदेश मेडिकल/डेंटल काउंसिल (और/या एमसीआई/डीसीआई) द्वारा स्थायी रूप से पंजीकृत होना चाहिए। इस नियम की वैधता को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी।

रिट याचिकाकर्ताओं के लिए इस आधार पर कि यह नियम उन उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करता है जो अन्य राज्य चिकित्सा/दंत परिषदों में स्थायी रूप से पंजीकृत हैं

सीईटी लेने से। रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को नियम, 2009 के नियम 10 (2) (iii) को अधिकार से बाहर घोषित करते हुए स्वीकार कर लिया गया है। इस पहलू पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अंतिम हो गया है क्योंकि

राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

16. संक्षेप में, तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित आधार पर है:

((i) री। : प्रवेश-अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी) के साथ धारा 6 को पढ़ना, जो सी. ई. टी. से संबंधित है, यह माना जाता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्य से सी. ई. टी. निर्धारित करने वाले प्रावधान हैं:

संवैधानिक और वैध क्योंकि ये टी. एम. ए. के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के आदेश के अनुरूप हैं।

पाई फाउंडेशन, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 58 और 59 में विशेष रूप से निर्धारित कानून के अनुसार। उच्च न्यायालय ने उस तरीके की ओर इशारा किया है जिसमें टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के कथन को समझाया गया है

पी. ए. इनामदार के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले और उसी को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

रिट याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के लिए क्योंकि प्रावधानों ने संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत स्वीकार किए गए और इसलिए सहेजे गए उचित प्रतिबंधों का गठन किया। पी. ए. इनामदार के अनुच्छेद 136 और 137 का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 2007 की धारा 6 के तहत निर्धारित सी. ई. टी. यह सुनिश्चित करेगा कि योग्यता बनी रहे। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री जो रिकॉर्ड पर रखी गई थी कि अधिनियम, 2007 के अधिनियमन से पहले स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2007 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के साथ पढ़े गए नियम, 2008 के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।

((ii) री। : शुल्क विनियमन-अनुभागों को चुनौती देने के संबंध में

4 (1) , 4 (8) और नियम, 2008 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम, 2007 के 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शुल्क नियामक समिति की शक्ति

प्रावधान केवल 'विनियामक' थे और जिसका उद्देश्य समिति को यह संतुष्ट करने के लिए सशक्त बनाना था कि निजी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था और यह अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित समझदार कारकों पर आधारित था जो एक संरेखित शक्ति प्रदान करता था।

निजी पेशेवर संस्थानों के अपने स्वयं के शुल्क लेने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं था।

((iii) री। : आरक्षण-आरक्षण से संबंधित अधिनियम, 2007 की धारा 8 और नियम, 2008 के नियम 4 और 7 को चुनौती गंभीर नहीं थी।

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन), 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन, जिसके द्वारा खंड (5) जोड़ा गया था, को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दबाव डाला गया। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधानों की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न विषयों और विषयों में अनारक्षित श्रेणी के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें आवंटित की गई थीं और अनारक्षित श्रेणी के अधिकारों के बीच एक उचित संतुलन बनाया गया था

उम्मीदवार और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार।

17. जैसा कि हमने वर्णित किया है, उपरोक्त पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम, 2007 की संवैधानिक वैधता पर हमला नियम, 2008 और नियम, 2009 के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित [2016] 3 एस. सी. आर. को छुआ गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीन पहलू:

(i) विवादित प्रावधान शिक्षा के अधिकारों को हड़प लेते हैं।

संस्थान परीक्षा आयोजित करें और छात्रों को प्रवेश दें। यह तर्क दिया जाता है कि इस अधिकार को विशेष रूप से टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में मान्यता दी गई है, जिसे पी. ए. इनामदार में कानूनी स्थिति में दोहराया गया है। इसलिए, इन संस्थानों द्वारा गैर-सहायता प्राप्त मान्यता

प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया जाना है। भले ही इस उद्देश्य के लिए सी. ई. टी. आयोजित की जानी हो, लेकिन ये संस्थान ही हैं जो एक साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। एकमात्र

गैर-शोषणकारी। राज्य प्रवेश की प्रक्रिया में कदम रख सकता है और उसकी देखरेख/पर्यवेक्षण कर सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से शैक्षणिक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-प्रवेश परीक्षा की उपरोक्त ट्रिपल परीक्षा हो। शोषणकारी चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य को दी गई शक्ति केवल नियामक प्रकृति की होगी और इसकी आड़ में होगी

इस शक्ति से राज्य उन छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को नहीं छीन सकता है जो शैक्षणिक संस्थानों में निहित हैं। संक्षेप में, प्रस्तुतिकरण

यह है कि अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा सी. ई. टी. का आयोजन, जिसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाता है,

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अपीलार्थियों का मौलिक अधिकार, जिसे अब इन अधिकारों के बराबर लाया गया है -

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को ऐसी संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। यह आगे तर्क दिया गया था कि जबकि की शक्ति

राज्य की ओर से पर्यवेक्षण उचित प्रतिबंध के बराबर हो सकता है और इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करेगा, लेकिन सीईटी आयोजित करके और यहां तक कि परामर्श द्वारा प्रवेश की शक्ति को पूरी तरह से छीनना अनुच्छेद 19 (6) के तहत गारंटीकृत व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

संविधान और ऐसे प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत नहीं बचाया जा सकता है और साथ ही वे आनुपातिकता के सिद्धांत को बाधित करते हैं। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि राज्य का हस्तक्षेप, यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल सहमति की व्यवस्था के साथ हो सकता है और अन्यथा नहीं।

(ii) इसी तरह, अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के एक पहलू के रूप में, शुल्क निर्धारित करने का अधिकार इन शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया गया है जो गैर-सहायता प्राप्त हैं और इसलिए, राज्य ऐसा नहीं कर सकता है।

उस शक्ति को स्वयं ग्रहण करें। यहाँ फिर से, राज्य की शक्ति 'पुलिसिंग' तक सीमित थी।, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क 'मुनाफाखोरी' के बराबर न हो और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होता है।

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v के अनुसार। मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

अपीलार्थी, यह सुनिश्चित करने के लिए, एकमात्र तंत्र जो प्रदान किया जा सकता है वह है 'शिकायत तंत्र' जिसके तहत शैक्षणिक संस्थान द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद और यदि छात्रों या माता-पिता या यहां तक कि अधिकारियों की भी इसके खिलाफ शिकायत है तो यह देखने के लिए उपयुक्त समिति (इस उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली) द्वारा जांच की जा सकती है कि निर्धारित शुल्क अत्यधिक नहीं है और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। यह स्वीकार किया गया कि ऐसा करते समय राज्य एक प्रहरी के रूप में यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके विपरीत

उपरोक्त मामले में, तत्काल मामले में, अधिनियम, 2007 के प्रावधान, जिसके तहत नियम पढ़े जाते हैं, सरकार द्वारा गठित समिति को शुल्क तय करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिससे संस्थानों को उनके अधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जाता है, जो शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के अपने 'व्यवसाय' को जारी रखने के लिए शैक्षणिक संस्थान के अधिकार के लिए अभिशाप है।

मौलिक अधिकार।

(iii) तीसरी चुनौती आरक्षण से संबंधित अधिनियम, 2007 की धारा 8 और नियम, 2008 के नियम 4 और 7 के प्रावधान के लिए है।

18. कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल ने अपने सामान्य उत्साह, उत्साह और निपुणता के साथ विवादित फैसले पर हमले का नेतृत्व किया। डॉ. राजीव धवन एक अन्य वरिष्ठ वकील थे जिन्होंने जुनून के साथ कानूनी कौशल के मिश्रण के साथ अपनी विस्तृत दलीलें दीं, जिससे हमला और बढ़ गया। उनके साथ श्री रावल, श्री अजीत कुमार सिन्हा और श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील शामिल हुए, जिन्होंने उनका काफी समर्थन किया। उनके जोरदार हमले का बहादुरी से सामना किया गया और उनका बचाव किया गया सुश्री विभा दत्ता मखीजा द्वारा, विद्वान वरिष्ठ वकील जो मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुईं। अन्य, जिन्होंने अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों का मुकाबला करने में उनका समर्थन किया, इस

प्रक्रिया में दूसरे पक्ष को कठोर जमीनी वास्तविकताओं के संक्षिप्त और चतुर एफोरिज्म के साथ चित्रित किया, वे सुश्री थीं।

पिंकी आनंद, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सी. डी. सिंह, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता। क्या बचाव पक्ष अपीलार्थियों के हमले को विफल करने में सक्षम रहा है और अपने प्रयास में सफल रहा है, यह निर्णय के अंतिम चरण में पता चलेगा जब इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

19. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की दलीलों का केंद्रीय विषय यह था कि राज्य विवादित कानून द्वारा

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपीलकर्ता संस्थानों के पास उपलब्ध विकल्प को मिटा दें।

[2016] 3 एस सी आर।

उनकी अपनी प्रवेश प्रक्रिया और धारा 3 (डी) के साथ पठित धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश केवल राज्य सरकार या किसी एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सी. ई. टी. के आधार पर किया जाना चाहिए। उसके द्वारा नियुक्त। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन (यानी राज्य सरकार द्वारा आयोजित सी. ई. टी. द्वारा उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी के अलावा किसी अन्य तरीके से) अमान्य होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 9 में अधिनियम की धारा 3 (सी) के तहत परिभाषित समिति के लिए अपीलार्थियों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को 'और' तय 'करने का प्रावधान है और इस तरह शुल्क निर्धारित करने और शुल्क लेने के अपीलार्थियों के अधिकारों को पूरी तरह से रौंद दिया जाता है। यह समिति एक स्वतंत्र समिति नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित है और इसलिए प्रभावी रूप से राज्य सरकार ने उक्त समिति का खाका तैयार किया है।

20. यह उनका निवेदन है कि अपीलकर्ता संस्थानों के लिए उपलब्ध अधिकार अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करना है, इस शर्त के अधीन कि इस तरह से तैयार की गई प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी होनी चाहिए। इस प्रकार, संस्थानों को उपलब्ध अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत छात्रों को निष्पक्ष आधार पर प्रवेश देने का अधिकार शामिल

है और इस तरह अपीलकर्ता एक साथ आने वाले संस्थानों के संघ द्वारा आयोजित सीईटी के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का विकल्प चुन सकते हैं।

पी. ए. इनामदार) या राज्य द्वारा आयोजित एक में प्रदान किया गया है और विकल्प में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सी. ई. टी. के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार भी शामिल है। चुनने का अधिकार वह अधिकार है जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अलग-अलग संस्थानों के लिए उपलब्ध है और विवादित कानून जो उक्त अधिकार को निरस्त करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के खिलाफ है।

21. अपीलार्थियों के वकील ने उन्नी कृष्णन, जे. पी. एंड ओ. आर. एस. में फैसले का उल्लेख करके न्यायिक यात्रा के इतिहास का पता लगाया। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। 6 उस मामले में, इस न्यायालय ने उन शर्तों और विनियमों पर विचार किया, जिन्हें राज्य पेशेवर पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त या संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में लागू कर सकता है। ऐसी संस्थाओं द्वारा किस हद तक शुल्क लिया जा सकता है और किस तरह से

3 (2007) 4 एस. सी. सी. 361

" (1993) 1 एस. सी. सी. 645 आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

प्रवेश देने पर भी विचार किया जा सकता था। इसके बाद न्यायालय ने

मुफ्त सीटों या राज्य कोटा सीटों और भुगतान सीटों या प्रबंधन कोटा सीटों की एक योजना तैयार की, जिसके तहत अधिक शुल्क लिया जा सकता है। प्रवेश लेने वाले छात्रों से भुगतान 'सीटों' और कम शुल्क के बदले शुल्क लिया जाएगा। मुफ्त सीटों पर बैठने वाले छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भुगतान सीटों के लिए समान पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन यह कि ऐसा शुल्क राज्य द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त/संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में, न्यायालय ने प्रवेश और शुल्क के मामलों के साथ-साथ शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तों जैसे मामलों में नियम और विनियम बनाने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।

कर्मचारी। 22 , विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उपरोक्त नियंत्रण तंत्र विफल हो गया और इस न्यायालय द्वारा टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में स्थिति को ठीक किया गया। इसने अभिनिर्धारित किया कि यदि संस्थान पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित हैं,

राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और हस्तक्षेप केवल शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, यह माना गया कि कॉलेजों को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अदालत ने माना है कि

संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत राज्य द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों का दायरा और यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त शक्ति राज्य को उन संस्थानों के मामलों का नियंत्रण लेने के लिए प्रदान नहीं करती है जिन्हें उचित प्रतिबंध माना गया है। अपीलार्थियों ने पैराग्राफ 54 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया

जोर देना:

" 54. एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार हो सकता है -

विनियमित; लेकिन ऐसे नियामक उपाय, सामान्य रूप से, उचित शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए,

वातावरण और अवसंरचना (योग्य कर्मचारियों सहित) और प्रभारी लोगों द्वारा कुप्रशासन की रोकथाम

प्रबंधन। एक कठोर शुल्क संरचना का निर्धारण, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्देशित करना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।

यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने उन्नी कृष्णन को दरकिनार करते हुए निजी शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता और महत्व को मान्यता दी है

और उन्हें उनके [2016] 3 एस. सी. आर. में अपेक्षित स्वायत्तता देने की आवश्यकता।

कार्य, प्रबंधन और प्रशासन। 23. निवेदन यह था कि इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निम्नलिखित सिद्धांतों और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थानों द्वारा प्राप्त अधिकारों के दायरे को निर्धारित किया:

(क) कि संस्थानों को व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का मौलिक अधिकार है और अधिकार अनुच्छेद से प्रवाहित होते हैं।

30 (1) अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में और अनुच्छेद 19 (1) (जी) अल्पसंख्यक के साथ-साथ गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में;

(ख) जो निजी संस्थान राज्य निधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है और स्वायत्तता में शामिल हैं:

((i) छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार;

((ii) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार;

किसी भी कर्मचारी से।

और

और नियुक्ति के लिए कर्मचारी या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत संरक्षित नहीं होंगे। 24. न्यायिक घोषणा के कथन को जारी रखते हुए, अपीलार्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त टिप्पणियों और निर्धारित कानून के बावजूद

इस न्यायालय द्वारा टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के दायरे को परिभाषित करते हुए

पेशेवर महाविद्यालयों को चलाने और प्रबंधित करने का निजी संस्थानों का अधिकार, कुछ राज्यों ने इसका पालन नहीं किया और उक्त निर्णय के पैराग्राफ 68 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर सरकारी आदेश जारी किए। उक्त आदेशों को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसका फैसला इस्लामिक अकादमी या शिक्षा और अन्र के मामले में किया गया था। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। ' , जो कुछ व्यापक रूप से निर्धारित करता है

प्रवेश को विनियमित करने के लिए तौर-तरीके और समितियों का निर्माण

प्रक्रिया और शुल्क संरचना। यह प्रस्तुत किया गया था कि कुछ राज्य

7 (2003) 6 एस. सी. सी. 697 डर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v. मध्य प्रदेश राज्य
[ए. के. सिकरी, जे.]

एड कानून जो फिर से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे

इसलिए, इन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। बात यह है एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया, जिसने संदर्भ में जवाब दिया

पी. ए. इनामदार का, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 132. पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि न तो की नीति

आरक्षण राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है और न ही कोई कोटा या

प्रवेश के प्रतिशत को विनियोजित किया जा सकता है

राज्य द्वारा अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक

संस्था। अल्पसंख्यक संस्थान अपने छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।

गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों सहित अपनी पसंद के अन्य राज्यों से अपने स्वयं के समुदाय के सदस्य, दोनों को

केवल सीमित सीमा तक और इस तरह से और इस हद तक नहीं कि

उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा खो गया है। अगर वे ऐसा करते हैं,

वे अनुच्छेद 30 (1) का संरक्षण खो देते हैं।

" एक के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है।

समान या समान शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का समूह। इस तरह

एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में स्थित संस्थान

एक साथ शामिल हों और एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करें।

XX

XX

XX

141. प्रश्न 3 का हमारा उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्थान

अपनी खुद की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन वही हो सकता है मुनाफाखोरी रोकने के हित में विनियमित। कोई कैपिटेशन नहीं

शुल्क लिया जा सकता है।

XX

XX

XX

144. प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो समितियाँ

और इस्लामी निर्णय में शुल्क संरचना का निर्धारण करना

छात्र समुदाय के हितों की रक्षा के उद्देश्य से समग्र रूप से और स्वयं अल्पसंख्यकों को भी, आवश्यकता को बनाए रखने में

गैर-शोषणकारी शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के मानक अपने संस्थानों में। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनी प्रावधान

विधायिका या निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा विकसित योजना

प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है

अनुच्छेद 30 (1) या अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों के अधिकार के तहत अल्पसंख्यक

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अल्पसंख्यक। वे तर्कसंगत हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों के हित में अनुमत प्रतिबंध

अनुच्छेद 30 (1) के तहत और आम जनता के हित में [2016]

3.

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

:

संविधान का अनुच्छेद 19 (6) "।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. इनामदार के बारे में उनकी समझ को उनके अपने तरीके से समझाते हुए, एक भावुक याचिका दायर की गई कि ऐसे कानूनों को क़ानून की पुस्तकों में नहीं रहने दिया जाए जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक थे। 25. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर आधारित उपरोक्त मुद्दों के अलावा, इस न्यायालय में उठाए गए अतिरिक्त तर्क इस तरह के कानून को लागू करने की राज्य की शक्ति को छूते हैं क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का मामला संविधान की सातवीं अनुसूची (संघ सूची) की सूची I की प्रविष्टि 66 में आता है और सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) की सूची III की प्रविष्टि 25 में शामिल नहीं है।

26. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की उपरोक्त प्रस्तुतियों का कड़ा विरोध किया और उनके आदेश पर पूरी तीव्रता के साथ प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय दोषरहित था, जिसने अपीलार्थियों की सभी उपरोक्त प्रस्तुतियों पर उचित और पर्याप्त विचार किया था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थीं और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के अनुपात को सही ढंग से पढ़कर इन प्रस्तुतियों को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया, जैसा कि इस्लामिक शिक्षा अकादमी में समझाया गया था और पी. ए. इनामदार द्वारा विवाद से परे रखा गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में दिए गए तर्क का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया और कहा कि इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, उनका निवेदन था कि अधिनियम, 2007 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियम असंवैधानिक थे/भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अपीलार्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे। उनका निवेदन था कि निस्संदेह न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के नागरिकों के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

' टी. एम. ए. पाई में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत 'कब्जा'

नींव रखना और उन्हें समान अधिकारों के बराबर लाना जो पहले से ही अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए प्रदान किए गए थे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत पेशेवर/तकनीकी संस्थान। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि समान रूप से न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये उचित प्रतिबंधों के अधीन थे जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत लगाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि टी. एम. ए.

पाई फाउंडेशन ने इस प्रक्रिया में शिक्षा के स्तरों के आधार पर नियंत्रण की प्रकृति और सीमा के बारे में विस्तार से बताया, जिसे आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.)

और इसे छिपाया नहीं जा सकता है। इसे निर्णय के पैराग्राफ 61 में यह कहते हुए समझाया गया था कि जहां तक स्कूल स्तर की शिक्षा का संबंध है, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अधिकतम स्वायत्तता होनी चाहिए क्योंकि स्कूल स्तर पर छात्रों की योग्यता का आकलन करना संभव नहीं है। इसलिए इस स्तर पर चयन के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

केवल योग्यता पर। इसी तरह, गैर-तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्नातक महाविद्यालयों को भी इसी तरह का लाभ मिलेगा।

विद्यालयों के समान अधिकतम स्वायत्तता। हालाँकि, जब भी उच्च शिक्षा की बात आती है, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को अधिकतम स्वायत्तता के सिद्धांत का विस्तार नहीं किया जाएगा। यहां, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन संस्थानों के संबंध में अधिकतम नियम बनाए जा सकते हैं क्योंकि योग्यता बनाए रखने का सिद्धांत अलंघनीय था। और प्राथमिक। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए एक विनियमन लागू कर सकती है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, उन्होंने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के कुछ पैराग्राफ और पी. ए. इनामदार के इस पहलू पर अधिक केंद्रित चर्चा का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि ये निर्णय स्पष्ट रूप से राज्य को प्रवेश को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में सुनिश्चित ट्रिपल टेस्ट को मान्यता प्राप्त है और इस तरह के विनियमन में प्रवेश के लिए छात्रों की परामर्श के साथ सीईटी आयोजित करने की राज्य की शक्ति शामिल होगी।

व्यावसायिक संस्थान। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पी. ए. इनामदार में सात न्यायाधीशों की पीठ। बल्कि राज्यों को निजी गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त पेशेवर या तकनीकी संस्थानों में प्रवेश और शुल्क को विनियमित करने वाले कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद

पी. ए. इनामदार में निर्णय की घोषणा, कई राज्यों ने ऐसे संस्थानों में प्रवेश और शुल्क को विनियमित करने वाले कानून बनाए हैं। उसने प्रस्तुत किया

कि एक बार दिल्ली राज्य द्वारा अधिनियमित ऐसी विधि पर इस न्यायालय द्वारा भारतीय चिकित्सा संघ के मामले में विचार किया गया था। भारत संघ और अन्य। , जहाँ चुनौती ए. सी. एम. एस. के लिए थी जो द्वारा प्रबंधित कॉलेजों में केवल सैन्य कर्मियों के बच्चों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित करता था।

प्रशासन का विनियमन, गैर-शोषक शुल्क और अन्य उपायों का निर्धारण) अधिनियम, 2007, इस न्यायालय ने एसीएमएस अधिसूचना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं। सामान्य पूल से अपना स्रोत चुनने का अधिकार है। यह था।

8 * (2011) 7 एस. सी. सी. 17 [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि न तो अल्पसंख्यक और न ही गैर-अल्पसंख्यक संस्थान अपने शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से पेशेवर संस्थानों का कुशासन कर सकते हैं। संस्थान, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, और छात्रों को मनमाने ढंग से उन स्रोतों से चुनते हैं जिनमें से वे चुनने के हकदार हैं। जहाँ तक शुल्क विनियमों के संबंध में प्रावधान है

अभियोग लगाने का इरादा रखने वाले अपीलार्थियों को समिति के समक्ष रखा जाना था नियमों और समिति के तहत गठित समिति को इस बात पर विचार करना था कि प्रस्तावित शुल्क उचित है या नहीं और उस आधार पर अधिनियम और नियमों में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए शुल्क तय करना था जो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप थे।

और पी. ए. इनामदार के साथ-साथ मॉडर्न स्कूल बनाम। भारत संघ '। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल एक नियामक तंत्र था। सुश्री मखीजा ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विधिवत रूप से शामिल किया गया था

अधिनियम, 2007 की धारा 9 की उप-धारा (2) को शामिल करके स्थापित प्रक्रिया में और यहां तक कि अपील प्रक्रिया का प्रावधान भी प्रदान किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत।

27. जहाँ तक आरक्षण से संबंधित प्रावधान का संबंध है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के प्रावधान

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर संविधान लागू होता है या नहीं, यह अब एकीकृत नहीं था क्योंकि इसे संविधान में पहले ही बरकरार रखा जा चुका है।

प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट में दिया गया बेंच का फैसला

(पंजीकृत) & ओआरएस; वी। भारत संघ और अन्य "। उन्होंने यह भी बताया कि

कि आरक्षण से संबंधित उक्त प्रावधान को चुनौती नहीं दी गई थी

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा बलपूर्वक दबाव डाला गया।

अन्य वकीलों ने भी इसी तर्ज पर अपनी दलीलें दीं।

28. अब तक के मामले की चर्चा निष्पक्ष रूप से दर्शाती है कि जिन दो मामलों पर अपीलकर्ताओं द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है, वे हैं टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. इनामदार। इस प्रक्रिया में, इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में निर्णय का भी उल्लेख किया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि उत्तरदाताओं ने भी उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून से पोषण लिया है। इस प्रकार, दिलचस्प रूप से, स्टिकोमाइथिया जिसके परिणामस्वरूप तीव्र तर्क हुए, भावनात्मक रूप से भी।

" (2004) 5 एससीसी 583! "

(2014) 8 एस. सी. सी. I आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान की नींव एक ही मामले के कानून के आधार पर थी। इसलिए, अपने विश्लेषण को पूरा करते हुए, दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों पर विचार करते हुए, हम उपरोक्त निर्णयों के साथ-साथ कुछ अन्य निर्णयों की ओर ध्यान देंगे, जो इस मुद्दे पर असर डालते हैं, ताकि उसमें निर्धारित नींव के आधार पर वांछनीय और न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। हम यह भी देख सकते हैं कि इन तर्कों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, हमने प्रयास किया है

ठोस कानूनी सिद्धांतों के पेरिस्कोप का उपयोग करके विवेकपूर्ण और गहन भेदक विश्लेषण के साथ कार्य को पूरा करना और इसका निदान करना।

प्रकार।

विश्लेषण, कारण और निर्णय:

29. निजी मेडिकल कॉलेजों के कामकाज पर सरकारी नियंत्रण के बारे में विवाद का इतिहास अब काफी पुराना है लेकिन रस्साकशी जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और इस

देश के युवाओं को संस्थान स्थापित करने और पेशेवर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले निकायों के बीच कुछ हितों का टकराव है। जहां एक ओर राज्य सरकारें सामाजिक-राजनीतिक विचारों के लिए संस्थानों को नियंत्रित करना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर जो लोग संस्थानों में निवेश करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उन्हें चलाने की इच्छा होती है

छात्रों के सर्वोत्तम हित में संस्थान पर कार्यात्मक नियंत्रण, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार नहीं है और निजी चिकित्सा महाविद्यालय इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में धन की कमी है जो छात्रों को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा और नवीनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभर सकें।

30. इसलिए आधुनिक युग में, विशेष रूप से राज्य द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति के बाद, निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निकायों को स्थापित करने की अनुमति है। एक प्रतिमान बदलाव है

शिक्षा पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण (जैसे अन्य आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों) के युग से लेकर ऐसी स्थिति तक जहां निजी खिलाड़ियों को पनपने की अनुमति है। लेकिन साथ ही, नियामक तंत्र

इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे निजी संस्थान ऐसी नियामक व्यवस्था के भीतर काम करें। जब शिक्षा की बात आती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि

गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही उन्हें न्यूनतम सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दी जाती है।

शिक्षा को अब एक व्यवसाय के रूप में माना जाता है और इस प्रकार यह एक व्यवसाय बन गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसी समय इस विशेष व्यवसाय के संबंध में बंधन लगाए जाते हैं जिसे कुलीन कहा जाता है। अत: मुनाफाखोरी और

व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए न कि शैक्षणिक संस्थानों की इच्छा के अनुसार। गोद लेकर योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में कुछ कार्यप्रणाली और ऐसी कुछ विधियों का सुझाव दिया गया है, जिसमें सी. ई. टी. का आयोजन शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और गैर-शोषण की तीन कसौटी पर खरी उतरे।

इन परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ, हम विषयगत चर्चा का विज्ञापन करते हैं।

आई. रे. : द्वारा संचालित किए जाने वाले सी. ई. टी. से संबंधित प्रावधान

अधिनियम, 2007 के साथ-साथ नियमों के तहत राज्य तंत्र।

31. इसमें शामिल मुद्दा, जो मौलिक प्रकृति का है, न्यायिक समीक्षा के तीन चरणों की आवश्यकता है। सबसे पहले इसकी जांच की जानी चाहिए।

क्या अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया अधिकार एक मौलिक अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी, और यदि ऐसा है, तो क्या

इसकी क्या विशेषताएँ हैं? दूसरा चरण यह पता लगाना होगा कि क्या क़ानून, जो विवादित है, इस पर कोई प्रतिबंध लगाता है।

अपीलार्थी को दिया गया अधिकार? . यदि प्रतिबंध हैं, तो तीसरा पक्ष यह होगा कि क्या ऐसे प्रतिबंध उचित हैं और इसलिए,

संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत संरक्षित? 32. जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, इसमें कोई समस्या नहीं है और उत्तर अपीलार्थियों के पक्ष में जाता है। हम.

यहां यह दोहराया जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी खंड को कुछ अधिकार प्रदान करके स्वतंत्रता देता है जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार शामिल है। इस प्रकार, जहाँ तक धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी भी वर्ग का संबंध है, उन्हें दिया गया था।

धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार इसे एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसी तरह, अनुच्छेद 30 प्रदान करता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार। संस्थाएं। जहाँ तक अनुच्छेद 26 का संबंध है, यह 'धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार' शीर्षक के तहत आता है। जहाँ तक अनुच्छेद

30 का संबंध है, यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शीर्षक के तहत है। इस प्रकार, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार थे

हमेशा मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त। इसके अलावा, शैक्षणिक आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना और प्रबंधन के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों का अधिकार।

मध्य प्रदेश राज्य (ए. के. सिकरी, जे.)

संस्थानों को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी और उन्नी के मामले में पांच न्यायाधीशों की इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

कृष्णन। निर्णय के पैराग्राफ 198 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसलिए, हम बॉम्बे राज्य बनाम में तर्क की रेखा को अपनाने की राय रखते हैं। आर. एम. डी. चमरबागवाला और अन्र "। कि शिक्षा प्रदान करना व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। शिक्षा को वाणिज्य में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही न्याय याचिकाकर्ता इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

उक्त परिणाम 'व्यवसाय' के व्यापक अर्थ पर भरोसा करके उस मामले में, इस न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उक्त गतिविधि को 'पेशे' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के लिए पेशेवर संस्थानों के अधिकार को अंततः टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में इस अधिकार की मान्यता के लिए उपयुक्त एक 'व्यवसाय' के रूप में माना गया था।

" 25. किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन

एक व्यवसाय के रूप में माना जाता है, भले ही लाभ सृजन का कोई तत्व न हो। यह समझना मुश्किल है कि शिक्षा अपने आप में,
यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) की चार अभिव्यक्तियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आएगा।
व्यवसाय "एक व्यक्ति की एक गतिविधि होगी जो एक के रूप में की जाएगी

आजीविका का साधन या जीवन में एक मिशन। उपर्युक्त-उद्धृत
सोदन सिंह मामले में टिप्पणियाँ, (1989) 4 एस. सी. सी. 155, सही

अनुच्छेद 19 (1) (छ) में "व्यवसाय" अभिव्यक्ति की व्याख्या करें। “

व्यवसाय का अधिकार, अर्थात् (i) छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार; (ii) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार; (iii) कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) को नियुक्त करने का अधिकार; और (iv) किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही होने पर कार्रवाई करने का अधिकार। छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार की उपरोक्त मान्यता और व्यवसाय के हिस्से के रूप में एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के अधिकार को देखते हुए, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, अपीलकर्ताओं ने आसानी से प्रारंभिक बाधा को पार कर लिया है। यहाँ इस मुद्दे का दूसरा पहलू आता है। - व्यवसाय के इस अधिकार का दायरा क्या है?

1

1957 एससीआर 874 [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. यह इंगित करना आवश्यक हो जाता है कि उपचार करते समय

एक 'व्यवसाय' के रूप में शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन, न्यायालय था

स्पष्ट रूप से कि इस गतिविधि को 'व्यवसाय' के रूप में नहीं माना जा सकता है या

पेशा '। इस व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार जो शिक्षा है,

इसे अन्य व्यवसायों या व्यावसायिक गतिविधियों के बराबर नहीं रखा जाता है या

यहाँ तक कि अन्य व्यवसाय भी। यह एक अलग श्रेणी है जिसे अलग करके बनाया गया था टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में यह न्यायालय। एक विशिष्ट उद्देश्य था

ऐसा न करने के लिए। शिक्षा को 'नहीं' पर एक महान 'व्यवसाय' के रूप में माना जाता है।

लाभ बिना हानि के आधार पर। इस प्रकार, जो स्थापित कर रहे हैं और प्रबंधन कर रहे हैं

शैक्षणिक संस्थानों से मुनाफाखोरी में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती है या

इस महान गतिविधि का व्यावसायीकरण करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,

छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार का सम्मान और इसके निर्धारण के संबंध में भी शुल्क। जहाँ तक छात्रों के प्रवेश का संबंध है, न्यायालय ने

स्पष्ट है कि इस तरह के प्रवेश योग्यता के आधार पर होने चाहिए जब यह
उच्च शिक्षा में आता है, विशेष रूप से पेशेवर संस्थानों में।

35. सुश्री विभा दत्ता मखीजा का कहना सही है कि
टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने
शिक्षा के स्तर के आधार पर इसके नियंत्रण की प्रकृति और विस्तार।
जब उच्च शिक्षा की बात आती है, वह भी पेशेवर संस्थानों में,
योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 58 में की गई है।
निर्णय जो निम्नानुसार है:

" 58. किसी भी पेशेवर संस्थान में प्रवेश के लिए योग्यता अनिवार्य है।
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। जबकि यह सामान्य रूप से संभव नहीं हो सकता है
उस आवेदक की योग्यता का न्याय करें जो एक स्कूल में प्रवेश चाहता है,
एक पेशेवर संस्थान में प्रवेश लेने के लिए और बनने के लिए
एक सक्षम पेशेवर, यह आवश्यक है कि मेधावी उम्मीदवार
अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता है या वरीयताओं द्वारा नुकसान में नहीं डाला जाता है
कम मेधावी लेकिन अधिक प्रभावशाली आवेदकों को दिखाया गया। उत्कृष्टता
व्यावसायिक शिक्षा में अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी
प्रवेश चाहने वाले छात्र की योग्यता पर आधारित। उचित है।
इस उद्देश्य के लिए विनियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है
के संदर्भ में इस निर्णय में की गई अन्य टिप्पणियां
गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश "।

:

36. यह देखने के लिए कि योग्यता का निर्णय उपयुक्त और उचित रूप से किया जाता है,

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि प्रवेश के लिए प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए

. तैयार किया गया जो निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर होने के तिहरे परीक्षण को संतुष्ट करता है

शोषणकारी। अगला सवाल यह था कि उपरोक्त उद्देश्य आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

क्या हासिल किया जा सकता है? ऐसी योग्यता निर्धारित करने के लिए, न्यायालय ने पैराग्राफ 59 में यह कहते हुए रास्ता दिखाया कि ऐसी योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए।

या तो उन अंकों से जो छात्रों ने योग्यता परीक्षा में या संस्थानों द्वारा आयोजित सी. ई. टी. में या पेशेवर कॉलेजों के मामले में, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए। इन विधियों का सुझाव देने वाला अनुच्छेद 59 निम्नानुसार है:

" 59. पेशेवर और उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण आमतौर पर या तो योग्यता परीक्षा या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र चरण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के बाद साक्षात्कार, या संस्थान द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा, या पेशेवर महाविद्यालयों के मामले में, सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

यह अनुच्छेद विशेष रूप से सी. ई. टी. आयोजित करने के लिए अधिकृत करता है।

व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामले में सरकारी एजेंसियों द्वारा।

37. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त सी. ई. टी. निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन ने भी सरकार को अनुमति दी

गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विनियम बनाएँ। पैराग्राफ 67 और 68 जो इस तरह के प्रारूपण की अनुमति देते हैं नियमों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है;

" 67. अब हम उन नियमों पर आते हैं जिनसे संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं।

निजी के लिए। गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान।

68. सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने वाले समान नियमों और विनियमों को लागू करना अनुचित होगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान अपने प्रशासन में स्वायत्तता के हकदार हैं, जबकि साथ ही, वे इस सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं या त्याग नहीं करते हैं -

योग्यता। अत: मान्यता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय या सरकार के लिए एक निजी संस्थान की आवश्यकता की अनुमति होगी।

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान योग्यता-आधारित चयन के लिए प्रावधान करते हुए, साथ ही, प्रबंधन को पर्याप्त विवेकाधिकार देते हुए

छात्रों को प्रवेश। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।

प्रबंधन द्वारा उन छात्रों में से प्रवेश के लिए जिन्होंने स्वयं या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में आवेदन किया है, जबकि बाकी सीटें निम्नलिखित के आधार पर भरी जा सकती हैं -

राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श। यह संयोग से ध्यान रखेगा

समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग। इस उद्देश्य के लिए प्रतिशत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना है। अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और पेशेवर कॉलेजों के लिए स्थानीय जरूरतों और अलग-अलग प्रतिशत के अनुसार तय किया जा सकता है। यही सिद्धांत अन्य गैर-व्यावसायिक लेकिन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किए जा सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर गैर-व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान। "

38. अपीलार्थियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि शक्ति का प्रयोग करके

विनियम बनाने के लिए, राज्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस प्रवेश परीक्षा के संचालन के कार्य को हड़प नहीं सका। यह तर्क दिया गया कि इसका मतलब केवल यह है कि इस तरह की सी. ई. टी. का संचालन स्वयं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाना है और सरकार केवल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकती है और आयोजन के कार्य को छीन नहीं सकती है।

सीईटी।

39. इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी. ए. द्वारा दी गई स्पष्ट और स्पष्ट व्याख्या को देखते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

कुछ टिप्पणियों के संबंध में इनामदार, विशेष रूप से टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के पैराग्राफ 68 में। इस संबंध में, हम चाहते हैं कि

दोहराएँ कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में, ग्यारह न्यायाधीशों की एक पीठ

निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार के दायरे के मुद्दों और उक्त अधिकार के सरकारी विनियमन की सीमा से निपटना। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार शामिल है। लेकिन उक्त अधिकार को उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जा सकता है। कठोर शुल्क-संरचना का निर्धारण, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्धारित करना, अनिवार्य

नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे। हालाँकि, शिक्षा का व्यवसाय व्यवसाय नहीं था, बल्कि धर्मार्थ गतिविधि से जुड़ा व्यवसाय था। राज्य कैपिटेशन शुल्क और मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध लगा सकता है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। हालाँकि, शिक्षा के विकास के लिए एक उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है। प्रवेश के लिए योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राज्य या विश्वविद्यालय को प्रवेश में पर्याप्त विवेकाधिकार देते हुए योग्यता आधारित चयन के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान की आवश्यकता हो सकती है।

विद्यार्थी। स्कैट का कुछ प्रतिशत प्रवेश के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

सी. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

द्वारा आयोजित सीईटी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से प्रबंधन द्वारा

संस्थान या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में फैसले के पैराग्राफ 68 में कुछ टिप्पणियों की व्याख्या बहस का विषय रही है, जिसके लिए हम इसके बाद विस्तार से विज्ञापन देते हैं।

40. जैसा कि ऊपर बताया गया है, फैसले के तुरंत बाद। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, रिट याचिकाओं का एक समूह इस न्यायालय में दायर किया गया था, जो

इस्लामी अकादमी में पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा निपटा गया था शिक्षा. चार न्यायाधीश एक ही थे जो पक्षकार थे

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय। जिस मुद्दे पर विचार किया गया वह था

इस न्यायालय ने कहा कि शुल्क संरचना तय करने के लिए संस्थानों के पास स्वायत्तता है, लेकिन कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है क्योंकि शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति का है। इसके लिए प्रत्येक राज्य द्वारा निर्णय लेने के लिए एक समिति के गठन की आवश्यकता थी क्या किसी संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना उचित थी और यह मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क लेने के बराबर नहीं थी। शुल्क इस प्रकार तय किया गया है

तीन साल के लिए बाध्यकारी होगा जिसके अंत में एक संशोधन हो सकता है

की तलाश की।

41. प्रवेश में स्वायत्तता के संबंध में, यह नोट किया गया था कि पहले के फैसले में इस दुखद वास्तविकता को ध्यान में रखा गया था कि

मुनाफाखोरी करने वाले व्यावसायिक कॉलेजों की संख्या और /

प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसे नियंत्रित करना असंभव था मुनाफाखोरी/कैपिटेशन शुल्क का प्रभार, जब तक कि प्रवेश योग्यता के आधार पर न हो। यह आगे देखा गया कि एक छात्र को अधिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है

व्यक्तिगत परीक्षणों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार, प्रबंधन छात्रों का चयन कर सकता है या तो राज्य या किसी विशेष प्रकार के लिए सभी कॉलेजों के संघ द्वारा आयोजित सीईटी के आधार पर, उदाहरण के लिए, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या तकनीकी आदि। कुछ संस्थानों की अपनी प्रवेश प्रक्रिया है।

लंबे समय से जिसके खिलाफ कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई थी और निष्पक्षता और पारदर्शिता के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी-जो दावा विवादित था। 25 वर्षों से स्थापित संस्थान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं -

न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली समिति को छूट।

इस न्यायालय ने राज्य सरकारों को स्थायी नियुक्त करने का निर्देश दिया

महाविद्यालय संघ द्वारा आयोजित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए समितियाँ निष्पक्ष और पारदर्शी था।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. इस मामले पर तब पी. ए. इनामदार में सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दोनों समितियों के लिए

इस्लामी शिक्षा अकादमी में निर्णय के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और शुल्क संरचना निर्धारित करने की अनुमति नियामक उपायों के रूप में दी गई थी, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से छात्र समुदाय के साथ-साथ गैर-शोषणकारी शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखने में स्वयं अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। यह अनुच्छेद 30 (1) या अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है। यह देखा गया कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है

शुरुआती दौर में, उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाना असंभव होगा (जोर दिया गया)। इस आधार पर, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों के सुझाव, जिसके लिए संस्थानों द्वारा अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को अपनाने के बाद लेखा परीक्षा के बाद जांच द्वारा समितियों का गठन किया गया था, को अस्वीकार कर दिया गया था। द.

इस प्रकार, समितियों को राज्यों द्वारा बनाए गए उपयुक्त कानून या विनियमों तक प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि वे प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत सुविचारित कानून बनाएँ। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में अनुच्छेद 68 था

यह कहते हुए समझाया गया कि प्रबंधन को अनुमति देने वाली टिप्पणियाँ कुछ सीटें गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थीं

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। इसका मतलब योग्यता को नजरअंदाज करना नहीं था। यह भी माना गया कि सी. ई. टी. आयोजित की जा सकती है, अन्यथा योग्यता हताहत हो जाती है। इस प्रकार, सी. ई. टी. को किसी राज्य एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने पर कोई रोक नहीं है जब कानून ऐसा प्रदान करता है।

43. इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क उठाया गया कि निजी मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश देने या तय करने का पूर्ण अधिकार है शुल्क इस न्यायालय के पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं है। पेशेवर संस्थानों में प्रवेश में न तो योग्यता से समझौता किया जा सकता है और न ही कैपिटेशन शुल्क की अनुमति दी जा सकती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य नियामक उपायों को लागू करने के लिए खुला है। हम इन दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि राज्य केवल यह साबित करने के बाद हस्तक्षेप कर सकता है कि योग्यता से समझौता किया गया था या कैपिटेशन शुल्क लिया जा रहा था। जैसा कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में देखा गया है, लेखापरीक्षा के बाद के उपाय

विनियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। प्रारंभिक चरण में ही नियंत्रण की आवश्यकता थी।

इसलिए, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि यद्यपि आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

' व्यवसाय एक मौलिक अधिकार है, जो शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने और शुल्क तय करने का अधिकार देता है, साथ ही, ऐसे अधिकारों के दायरे पर चर्चा की गई है और सीमाओं की प्रकृति को समझाते हुए उपरोक्त निर्णयों द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की गई है।

इन अधिकारों पर।

44. जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह फिर से हो सकता है

यह स्वीकार करके आसानी से जवाब दिया जाता है कि विवादित कानून और नियम कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या ये उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुरूप हैं? यह चर्चा न्यायिक समीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित है जहां हमें यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या ये प्रतिबंध उचित हैं।

45. हम ध्यान दे सकते हैं कि नियामक प्रावधान को बनाए रखते हुए

प्रवेश, उच्च न्यायालय ने कहा है:

" 27. हमारा मानना है कि धारा 6 के साथ पढ़ा जाता है

अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), जो प्रवेश प्रदान करती है

स्वीकृत प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।
राज्य सरकार द्वारा केंद्रीकृत परामर्श के बाद या

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा

टी. एम. ए. में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप।

पाई फाउंडेशन बनाम। स्टेल ऑफ कर्नाटक (2002) 8 एस. सी. सी. 364 और पी. ए.

इनामदार और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 6

एससीसी 535। अधिनियम, 2007 की धारा 2 यह स्पष्ट करती है कि केवल
निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है जो

व्यावसायिक शिक्षा। इसलिए, हमें जांच करनी होगी

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. में निर्णय। इनामदार (ऊपर), से

पता लगाएँ कि क्या ये निर्णय पेशेवरों में प्रवेश की अनुमति देते हैं

में निर्धारित योग्यता के आधार पर शैक्षणिक संस्थान

सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद केंद्रीकृत परामर्श

राज्य सरकार या उसकी अभिकरण।

XX

XX

XX

28 ..... इस प्रकार निर्णय के पैरा 58 से यह स्पष्ट है कि टी. एम. ए. में

पाई फाउंडेशन (ऊपर), ऊपर उद्धृत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदक जो एक पेशेवर में प्रवेश चाहता है

एक सक्षम पेशेवर बनने के लिए शैक्षणिक संस्थान एक मेधावी उम्मीदवार होना चाहिए और उसे एक पद पर नहीं रखा जा सकता है

कम मेधावी लेकिन अधिक दिखाई गई प्राथमिकताओं से नुकसान

प्रभावशाली आवेदक और इसलिए, पेशेवर में उत्कृष्टता [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिक्षा के लिए योग्यता पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान या तो उन अंकों से जो छात्र योग्यता परीक्षा या एक सामान्य प्रवेश पर प्राप्त करते हैं

महाविद्यालय, सरकारी एजेंसियों द्वारा "। टीएमए पाई फाउंडेशन में (ऊपर), इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि योग्यता

एक पेशेवर संस्थान में प्रवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा।

46. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के अनुच्छेद 67 और 68 का उल्लेख करते हुए,

एस ने देखा:

" 29 ..... निर्णय के उपरोक्त भाग से यह स्पष्ट हो जाएगा।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, वह गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में स्वायत्तता के हकदार हैं लेकिन

वे योग्यता के सिद्धांत को त्याग या त्याग नहीं सकते हैं और यह होगा

इसलिए सरकार के लिए निजी की आवश्यकता की अनुमति होगी

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान योग्यता आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे

प्रवेश जबकि एक ही समय में प्रबंधन को पर्याप्त देना

प्रवेश में विवेक। निर्णय के उपरोक्त भाग में

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है

यह माना गया कि इसे विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है और एक

विधि यह प्रदान करके है कि सीटों का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है

उन छात्रों में से प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए आरक्षित जिन्होंने स्वयं या द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है

राज्य और प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में आवेदन किया है,

राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श। यहाँ भी, का निर्णय टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय स्पष्ट है कि

प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए आरक्षित सीटें, केवल वे

जिन छात्रों ने सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है प्रबंधन या राज्य द्वारा भर्ती किया जा सकता है।

XX

XX

XX

और श्री तन्खा। पीए में। इनामदार (ऊपर), सर्वोच्च न्यायालय गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर डर्न डेंटल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र v की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

एस. सी. सी. के पृष्ठ 603,604 और 605 पर अनुच्छेद 133 से 138 में अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों शैक्षणिक संस्थान। में। पी. ए. इनामदार (ऊपर) में अनुच्छेद 134 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए, उच्च मानक के प्रवेश और रखरखाव में उत्कृष्टता आवश्यक है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राज्य राष्ट्रीय हित में कदम उठा सकता है और बल्कि यह आवश्यक है क्योंकि व्यक्तियों के पास सामूहिक रूप से शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा राष्ट्रीय धन का गठन करती है और

पी. ए. में निर्णय के अनुच्छेद 135 में। इनामदार (ऊपर), सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अल्पसंख्यक पेशेवरों में

सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश राज्य स्तर पर होना चाहिए और प्रवेश में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पी. ए. में अनुच्छेद 136 और 137 में। इनामदार (ऊपर), सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेशेवरों में प्रवेश

शैक्षणिक संस्थान एक साझा प्रवेश परीक्षा के आधार पर बनाए जा सकते हैं जो या तो एक साथ जुड़े संस्थानों द्वारा या स्वयं राज्य या ऐसी परीक्षा आयोजित करने के लिए एक एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है।

47. पी. ए. इनामदार में अनुच्छेद 136 और 137 का उल्लेख करने के बाद, यह

देखा गया:

" इस प्रकार यह पी. ए. में निर्णय के पैराग्राफ 136 और 137 से स्पष्ट हो जाएगा। इनामदार (ऊपर), ऊपर उद्धृत किया गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सामान्य रूप से निर्धारित उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

प्रवेश परीक्षा के बाद समान या समान व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा या राज्य द्वारा या किसी ऐसी एजेंसी द्वारा केंद्रीकृत परामर्श दिया जाता है जिसे अत्यधिक विश्वसनीयता का आनंद लेना चाहिए और

विशेषज्ञता और उसके बाद सामान्य प्रवेश परीक्षा

केंद्रीकृत परामर्श को निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषक होने की तिहरी कसौटी को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. में उच्चतम न्यायालय के निर्णय। इनामदार (ऊपर), राज्य के साथ-साथ किसी भी एजेंसी द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता के निर्धारण के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देता है।

इस मामले में विश्वसनीयता और विशेषज्ञता और जिसे सुनिश्चित करना चाहिए

योग्यता में पारदर्शिता।

34. अधिनियम, 2007 की धारा 3 (घ), 6 और 7 में एक सामान्य एस. सी. आर. द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य या किसी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा

राज्य द्वारा प्राधिकृत स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करता है निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान योग्यता के आधार पर संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शुल्क लेने, अपने स्वयं के कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करने, अनुशासित करने और कर्मचारियों को हटाने, बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के हकदार हैं।

छात्र और ऐसे सभी अन्य कार्य करें जो पढ़ाने के लिए आवश्यक हों

छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा। इसलिए, अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), 6 और 7 मौलिक अधिकार को बाधित नहीं करती हैं।

स्थापना और प्रशासन के व्यवसाय को जारी रखना

एक व्यवसाय के रूप में व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान। एकमात्र अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), 6 और 7 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्कृष्टता के छात्रों का चयन राज्य या राज्य द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाए और उत्कृष्टता और योग्यता के बिना छात्र कदाचार और प्रभाव के माध्यम से इन व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश न करें। जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. दोनों में निर्णयों में माना गया है। . इनामदार (ऊपर), का अधिकार

निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान करेंगे प्रवेश

अपनी पसंद के छात्र एक पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-शोषणकारी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर छात्रों के चयन के अधीन हैं। इसलिए हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), 6 और 7 किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं। इस निष्कर्ष को देखते हुए, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है

यह तय करने के लिए कि क्या अधिनियम, 2007 की धारा 3 (डी), 6 और 7 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 (5) द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के दूसरे अंग द्वारा राज्य की एकाधिकार के निर्माण के लिए कानून बनाने की शक्ति से संबंधित हैं। किसी भी सेवा के संबंध में अनुग्रह "।

हम व्यापक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं, जो हमारे द्वारा और साथ ही पहले के भाग में चर्चा किए गए निर्णयों पर निर्भर है।

48. के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होगा

अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित राष्ट्रीय संस्थान। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में बहिष्कार को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथपी. ए. इनामदार में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सहायता निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

कि जहाँ तक ऐसे विनियामक उपायों का संबंध है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों के संबंध में भी इसे अपनाया जा सकता है। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम के मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा रखा गया रिलायंस। दिल्ली विश्वविद्यालय "बहुत मददगार नहीं हो सकता है क्योंकि यह मामला पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित नहीं था।

49. इस मोड़ पर, हम अपीलार्थियों के तर्कों पर विचार करना चाहेंगे कि अधिनियम और नियमों में निहित प्रावधान छात्रों को प्रवेश देने के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को पूरी तरह से छीनने का प्रभाव है।

50. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है, लेकिन खंड के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। (6) . कथित उल्लंघन किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध के उद्देश्य, प्रतिबंध की सीमा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

और अन्य प्रासंगिक कारक। इन कारकों को लागू करने में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को मौलिक अधिकारों और समाज के व्यापक हित के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। न्यायालय कानून में हस्तक्षेप करता है यदि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि विधानमंडल लोगों की जरूरतों को समझता है। संविधान मुख्य रूप से आम आदमी के लिए है। योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार, शुल्क और प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के बड़े हित और कल्याण को निश्चित रूप से विनियमित किया जा सकता है। 51. आइए हम इस चर्चा को कुछ और विस्तार से करें क्योंकि यह अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया केंद्रीय मुद्दा है।

संपत्ति की व्याख्या का दस्तावेज और
लागू:

52. निस्संदेह, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकार है।

अधिनियम। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अधिकार 'निरपेक्ष' नहीं है और सीमाओं के अधीन है यानी उचित प्रतिबंध जो लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 19 के खंड (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर कानून द्वारा। हालाँकि, उन प्रतिबंधों को उचित होना चाहिए। इसके अलावा, इस तरह के प्रतिबंध आम जनता के हित में होने चाहिए। अनुच्छेद 19 के खंड (6) में कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

" (6) उक्त खंड के उपखंड (छ) में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

किसी भी मौजूदा कानून का संचालन जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को आम जनता के हित में कोई कानून बनाने से रोकता है, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, और विशेष रूप से, उक्त उपखंड में कुछ भी किसी भी मौजूदा

कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह संबंधित है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

संबंधित,

((i) इसके लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएँ

किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार करना या

व्यवसाय, या

((ख) नागरिकों के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा चलाया जाना, चाहे वह नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए हो या नहीं।

अन्यथा "।

53. एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो उपरोक्त खंड के पढ़ने से देखी जा सकती है, वह यह है कि राज्य को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या विवादित प्रावधान

कानून और नियमों की उचित प्रतिबंधों के बराबर है और आम जनता के हित में लाए गए हैं, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है वह व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का संतुलन है। एक तरफ और दूसरी तरफ लगाए गए प्रतिबंध। इसी को 'आनुपातिकता का सिद्धांत' कहा जाता है। न्यायिक रूप से,

' आनुपातिकता 'को संवैधानिक रूप से अनुमत होने के लिए कानून द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार की सीमा के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तों को निर्धारित करने वाले नियमों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अहरोन बराक (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इज़राइल का सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार, आनुपातिकता के चार उप-घटक हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है 1 3 13, एक संवैधानिक अधिकार की सीमा संवैधानिक रूप से अनुमत होगी यदि: ((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है; (ii) इसके लिए किए गए उपाय प्रभावी रूप से ऐसी सीमाएं तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़ी हैं; (iii) किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो समान रूप से उसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

सीमा की एक कम डिग्री के साथ; और अंत में (iv) एक होना चाहिए 13 आनुपातिकता: ए हारोन बराक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2012 द्वारा संवैधानिक अधिकार और उनकी सीमा।

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

उचित उद्देश्य को प्राप्त करने का महत्व और संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने का सामाजिक महत्व। 54. संवैधानिक अधिकारों का आधुनिक सिद्धांत संवैधानिक अधिकारों के दायरे और इसके संरक्षण के दायरे के बीच एक मौलिक अंतर दर्शाता है। जहाँ तक संवैधानिक अधिकारों के दायरे का संबंध है, यह उक्त अधिकारों की बाहरी सीमाओं को चिह्नित करता है और इसकी सामग्री को परिभाषित करता है। इसके संरक्षण की सीमा इसके दायरे में अधिकारों के प्रयोग पर सीमाओं को निर्धारित करती है। इस अर्थ में, यह उन सीमाओं के औचित्य को परिभाषित करता है जिन्हें इस तरह के अधिकार पर लगाया जा सकता है।

55. अब यह लगभग स्वीकार किया जाता है कि कोई पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं हैं और ऐसे सभी अधिकार संबंधित हैं। अहरोन के विश्लेषण के अनुसार

बराक 1 5, सकारात्मक संवैधानिक अधिकारों को मान्यता देने के आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत को अपनी सीमाओं के साथ विकसित करने में दो प्रमुख तत्व लोकतंत्र और कानून के शासन की धारणाएं हैं। इस प्रकार, एक उप-संवैधानिक कानून, अर्थात कानून द्वारा संवैधानिक अधिकारों की आनुपातिक सीमाओं की आवश्यकता, स्वयं लोकतंत्र की धारणा की व्याख्या से प्राप्त होती है। जहां तक भारतीय संविधान का संबंध है, लोकतंत्र को माना जाता है

संविधान की मूल विशेषता के रूप में और विशेष रूप से एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है जिसे संविधान की प्रस्तावना में ही मान्यता प्राप्त है। यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि लोकतंत्र की इस धारणा में मानवाधिकार शामिल हैं जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। एक बार जब हम उपरोक्त सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं (और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है), तो यह भी स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन पर आधारित है। वास्तव में, अनुच्छेद 19 में ही ऐसा प्रावधान एक ओर अनुच्छेद 19 के खंड (1) में कुछ निश्चित स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और साथ ही साथ

1 14 + हालांकि। इस परेशान करने वाले मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ अधिकार हैं, हालांकि बहुत कम हैं, जिन्हें अभी भी 'निरपेक्ष' माना जा सकता है। दिए गए उदाहरण हैं:

(क) मानव गरिमा का अधिकार जो अलंघनीय है, (ख) यातना या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के अधीन नहीं होने का अधिकार।

ऐसे अधिकारों के संबंध में भी, एक सोच है कि व्यापक सार्वजनिक हित में, उनकी सुरक्षा की सीमा हो सकती है

कम किया जाए। हालाँकि, अब तक राज्यों के ऐसे प्रयासों को न्यायपालिका द्वारा विफल कर दिया गया है।

15 सुप्रा है, नोट [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1

सार्वजनिक रूप से उन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य ब्याज। यह धारणा आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत को स्वीकार करती है कि संवैधानिक अधिकार संबंधित हैं। इस सापेक्षता का अर्थ है कि उन अधिकारों को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक लाइसेंस दिया जाता है जहां इस तरह की सीमा सार्वजनिक हित या दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित होगी। यह घटना-संविधान में अधिकार और इसकी सीमा दोनों-लोकतंत्र के दो मौलिक तत्वों के बीच अंतर्निहित तनाव का उदाहरण है। एक ओर अधिकार का तत्व है, जो मूल लोकतंत्र का एक मौलिक घटक है; दूसरी ओर जनता का तत्व है, जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन अधिकारों को सीमित करता है। ये दोनों लोकतंत्र की धारणा का एक मौलिक घटक हैं।

हालांकि इस बार अपने औपचारिक पहलू में। इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि इस तनाव का समाधान संविधान से हारने वाले पहलू को समाप्त करके नहीं किया जाता है। बल्कि, तनाव को एक के माध्यम से हल किया जाता है

लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बीच एक रचनात्मक तनाव है। यह प्रत्येक पहलू को सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहते हुए विकसित करने में सक्षम बनाता है अन्य। इस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना है। इस तरह का संतुलन प्रत्येक पहलू को अन्य पहलुओं के साथ विकसित करने में सक्षम बनाता है, न कि उनके स्थान पर। दो मूलभूत पहलुओं के बीच इस तनाव-एक ओर अधिकार और दूसरी ओर इसकी सीमा-को संतुलन बनाकर हल किया जाना है।

ताकि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहें। यह संतुलन प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पहलू के सापेक्ष सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जब उचित संदर्भ में विचार किया जाए।

56. इस दिशा में अगला सवाल यह उठता है कि क्या

दोनों पहलुओं के बीच उचित संतुलन के लिए मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए। कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। यहाँ आनुपातिकता की अवधारणा आती है, जो एक उचित मानदंड है। सटीक शब्दों में कहें तो जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक होती है यदि वह आनुपातिक हो। प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं, और ऐसे उपाय आवश्यक हैं।

आनुपातिकता के सिद्धांत के इस सार को खूबसूरती से दर्शाया गया है।

आर. वी. में कनाडा के मुख्य न्यायाधीश डिक्सन द्वारा ओक्स ", निम्नलिखित में

1 6 16 (1986) 1 एस. सी. आर. 103 आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

शब्द (पृष्ठ 138 पर):

" यह स्थापित करने के लिए कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है, दो केंद्रीय मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, वह उद्देश्य, जिसे पूरा करने के लिए चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता की सीमा के लिए जिम्मेदार उपायों को तैयार किया गया है,

एक को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए

संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता। दूसरा, धारा I का आह्वान करने वाले पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि चुने गए साधन उचित और स्पष्ट रूप से उचित हैं। इसमें "आनुपातिकता का एक रूप" शामिल है।

"यद्यपि आनुपातिकता परीक्षण की प्रकृति परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होगी, प्रत्येक मामले में अदालतों को व्यक्तियों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

और समूह। मेरे विचार में, आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले अपनाए गए उपायों को उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, साधन होना चाहिए।

आई।

विचाराधीन अधिकार या स्वतंत्रता को "जितना संभव हो उतना कम" बाधित करना। तीसरा, चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार उपायों के प्रभावों और "पर्याप्त" के रूप में पहचाने गए उद्देश्य के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए।

महत्व "। एक के हानिकारक प्रभाव उतने ही गंभीर होते हैं

माप, उद्देश्य जितना अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए यदि माप

उचित और स्पष्ट रूप से उचित होना चाहिए और

लोकतांत्रिक समाज "।

57. इसलिए, जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा एक उद्देश्य के लिए है

एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक और इस तरह के अभ्यास में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन शामिल है, और अंततः एक आनुपातिकता के आधार पर मूल्यांकन अर्थात विभिन्न हितों का संतुलन।

58. हम बिना किसी हिचकिचाहट के टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सिद्धांत

आनुपातिकता, जिसे यहाँ ऊपर संक्षेप में समझाया गया है, अनुच्छेद 19 में निहित है।

जब हम खंड (1) को उसके खंड (6) के साथ पढ़ते हैं। यह परिभाषित करते हुए कि एक उचित प्रतिबंध क्या है, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि 'उचित प्रतिबंध' अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के खंड (1) के किसी भी उपखंड द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और किसी भी खंड (2) से (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। यह माना जाता है कि 'उचित' अभिव्यक्ति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा

अधिकार के उपभोग में मनमाना या अत्यधिक [2016] 3 एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकृति जनता के हित में आवश्यकता से परे है। इसके अलावा, उचित होने के लिए, प्रतिबंध का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है, और उस उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए। वी. भारत संघ और अन्य "।) . साथ ही, प्रतिबंध की तर्कसंगतता होनी चाहिए

एक वस्तुनिष्ठ तरीके से और आम जनता के हितों के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है न कि उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जिन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं या अमूर्त विचारों पर। वी. बिहार राज्य 1)। एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम इंस्पेक्टर केरल सरकार "। , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी वैधानिक प्रावधान की तर्कसंगतता की जांच करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा:

(1) राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत।

(2) प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए ताकि आम जनता के हित की आवश्यकता से परे जा सकें।

(3) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, कोई अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है ताकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो और यह हर मामले में अलग-अलग होगा।

बदलती स्थितियों, मानव जीवन के मूल्यों, संविधान के सामाजिक दर्शन, प्रचलित स्थितियों और आसपास के क्षेत्रों के संबंध में भी।

परिस्थितियाँ।

(4) अनुच्छेद 19 (6) द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण और लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। (5) सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं को भी लागू करना जिनका उद्देश्य प्रतिबंधों द्वारा संतुष्ट किया जाना है।

(6) लगाए गए प्रतिबंधों और इच्छित उद्देश्य के बीच एक प्रत्यक्ष और निकट संबंध या उचित संबंध होना चाहिए। हासिल किया। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक मजबूत धारणा उत्पन्न होगी।

59. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने निर्णय लिया है

ऊपर की गई हमारी विस्तृत चर्चा में मुद्दा। हम उक्त चर्चा का सारांश इस प्रकार दे सकते हैं:

17 (1982) 2 एससीसी 33 18 1959 एस. सी. आर. 629

" (1998) 8 एस. सी. सी. 227 आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

60. निस्संदेह, शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

संस्थानों को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे 'व्यवसाय' कहा जाता है, जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं में से एक है। इसे पहली बार टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में मान्यता दी गई थी। तब भी

ऐसा करते हुए, यह अधिकार कुछ चंगुल और बेड़ियों के साथ आया। अदालत ने

यह स्पष्ट किया कि यह एक महान व्यवसाय है जो व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं देगा और इसलिए, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को 'लाभ नहीं, नुकसान नहीं' के आधार पर चलाया जाना चाहिए। इस अधिकार के दायरे को समझाते हुए, छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार और शुल्क तय करने के अधिकार को इस अधिकार के पहलुओं के रूप में स्वीकार किया गया था, न्यायालय ने फिर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रदान करने के लिए

उच्च शिक्षा, और विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा में, प्रवेश लेना पड़ता है

योग्यता के आधार पर छात्र। योग्यता का आकलन करने के लिए, न्यायालय ने संकेत दिया कि एक सी. ई. टी. हो सकती है। ऐसा करते समय, इसने विशेष रूप से यह भी कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में इस तरह की सी. ई. टी.

राज्य द्वारा संचालित। यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा सी. ई. टी. का कार्य ग्रहण करते हुए किया जाता है, तो इसे उक्त अधिकार पर उचित प्रतिबंध के उपाय के रूप में टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में ही मान्यता दी गई थी। इस्लामी शिक्षा अकादमी ने आगे स्पष्ट किया कि

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन की व्याख्या करते हुए राज्य का ऐसा कार्य जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी सी. ई. टी. के संचालन की निगरानी के लिए समितियां

गठित की जा सकती हैं। व्याख्या की यह प्रक्रिया पी. ए. इनामदार में संतुलन और संवैधानिक संतुलन उल्लेखनीय रूप से हासिल किया गया था, न केवल सी. ई. टी. को समय से पहले रोक दिया गया था, बल्कि यह माना गया था कि सी. ई. टी. का संचालन करने वाली एजेंसी को पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए और इसके लिए

इस उद्देश्य से इसने राज्य को निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करने और कुप्रशासन को रोकने के हित में सी. ई. टी. आयोजित करने की प्रक्रिया प्रदान करने की अनुमति दी।

61. हमारा विचार है कि व्यापक जनहित इस तरह के उपाय की गारंटी देता है। में देखे गए कदाचारों को ध्यान में रखते हुए

ऐसे निजी संस्थानों द्वारा स्वयं आयोजित सी. ई. टी., जिसके लिए बहुत सारी सामग्री का उत्पादन किया जाता है, निस्संदेह, छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण में योग्यता को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता जोड़ना और नियंत्रण करना है।

कदाचार। प्रतिबंध की सीमा को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए

इन सभी कारकों को देखते हुए और इसलिए, हम महसूस करते हैं कि विवादित प्रावधान जो अपीलार्थियों के अपने 'व्यवसाय' को जारी रखने के अधिकार पर 'प्रतिबंध' के बराबर हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से 'उचित' हैं और [2016] 3 एस. सी. आर. को संतुष्ट करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आनुपातिकता का परीक्षण।

62. उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के अलावा, हमारे

संसद की एक हालिया रिपोर्ट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। समिति जिसे हम इस निर्णय के बाद के भाग में संदर्भित करेंगे। रिपोर्ट में भारी कैपिटेशन शुल्क और योग्यता से समझौता करके प्रवेश करने में शोषण की निराशाजनक तस्वीर पर ध्यान दिया गया है। यह नहीं हो सकता है

यह सभी संस्थानों पर लागू होता है लेकिन अगर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधानमंडल इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून लेकर आया है जो आम तौर पर प्रचलित है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि किसी भी नियामक की कोई आवश्यकता नहीं है

माप "। एक अधिनियम अपने वातावरण में एक जीव है। यह है।

सही कहा कि कानून अवधारणाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि जरूरतों, हितों और मूल्यों का रोजमर्रा का जीवन है जिसे एक दिए गए समाज एक निश्चित समय में महसूस करना चाहता है। कानून एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य समाज में मनुष्य की समस्याओं का समाधान प्रदान करना है।

63. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इन प्रावधानों का विश्लेषण किया है -

अधिनियम और पाया कि योग्यता आधारित प्रवेश और शुल्क निर्धारण के लिए प्रक्रिया के प्रावधान निजी संस्थानों के प्रवेश आयोजित करने और शुल्क तय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम सहमत हैं।

उक्त दृष्टिकोण के साथ और यह मानते हुए कि अधिनियम और नियमों में निहित प्रवेश से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 19 (1) (जी) के खिलाफ नहीं हैं। संविधान से।

II. री. : शुल्क निर्धारण से संबंधित अधिनियम नियमों में प्रावधान

64. हम फिर से खुद को याद दिला सकते हैं कि हालांकि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार को जारी रखने के अधिकार के रूप में माना जाता है ' 'व्यवसाय', जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में अदालत ने भी इस तरह के शैक्षिक अधिकार के बारे में आगाह किया था।

संस्था का मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण में लिप्त न होना। कि

निर्णय इन शैक्षणिक संस्थानों को कैपिटेशन शुल्क लेने से भी पूरी तरह से रोकता है। यह अपीलार्थी स्वयं मानते हैं कि

व्यावसायीकरण और शोषण की अनुमति नहीं है और शैक्षिक संस्थानों को 'कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं' के आधार पर चलाया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भी माना गया कि शिक्षा की लागत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न हो सकती है।

संस्थान और इस संबंध में कई परिवर्तनशील कारकों को लेना पड़ सकता है।

20 जस्टिस फ्रैंकफ्यूटर: वैधानिक निर्माण पर एक परिचर्चा: फॉरवर्ड ', 3, एल' और एल. रेव. 365,367 (1950)

शुल्क तय करते समय ध्यान में रखें। यह भी माना जाता है कि शैक्षिक संस्थान वह शुल्क ले सकते हैं जो इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का ध्यान रखेगा और साथ ही भविष्य की पीढ़ी के लिए शिक्षा के विस्तार का प्रावधान करेगा। साथ ही, वर्तमान छात्रों और उनके माता-पिता से अनुचित मांग नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए केवल एक 'उचित अधिशेष' उत्पन्न किया जा सकता है।

65. इस प्रकार टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, पी. ए. इनामदार और उन्नी कृष्णन में शिक्षा का मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण किया गया है। घृणित। उपरोक्त निर्णयों में तर्क का मूल सूत्र यह है कि शैक्षिक गतिविधि अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की है और

इसके माध्यम से व्यावसायीकरण या लाभ उठाना अस्वीकार्य है। उक्त गतिविधि यह सुनिश्चित करने के व्यापक सार्वजनिक हित को कम करती है कि राष्ट्र अपने उच्च शिक्षित लोगों के बल पर विकास और प्रगति करे

नागरिक। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार रहा है कि अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों संस्थानों के मौलिक अधिकारों को संतुलित करते हुए, यह आवश्यक है कि सभी मेधावी उम्मीदवारों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो। यह भी महसूस किया गया है कि इस लक्षय को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका,

इस कल्याणकारी लक्षय में निजी भागीदारी को मान्यता देना यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कोई व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी न हो।

66. उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने प्रवेश की प्रक्रिया की देखरेख के लिए नियामक समितियों के गठन के साधन तैयार किए थे

और इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में शुल्क नियम। हालांकि, नियामक निकायों की अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी देते हुए, पी. ए. इनामदार में इस न्यायालय का विचार था कि इस योजना को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केंद्र या राज्य के कानूनों द्वारा वैधानिक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए।

67. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और पी. ए. इनामदार में प्रतिपादित सिद्धांतों को इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में लागू किया गया था। जहां दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 18 (4) और 18 (5) के साथ पठित धारा 24 (3) के तहत

मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ एक चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि माता-पिता/छात्रों से एकत्र की गई कोई भी फीस/धनराशि मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय निधि से किसी सोसायटी या ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों की विस्तार से जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने उक्त निर्देशों को इस आधार पर बरकरार रखा कि राज्य के लिए शुल्क को इस तरह से विनियमित करने का अधिकार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मुनाफाखोरी या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट न हो।

[2016] 3 एस सी आर।

शिक्षा का व्यावसायीकरण होता है।

68. संक्षेप में, हालांकि शुल्क शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और यह संस्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकता है

ऐसे प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है। यह देखने के लिए कि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायीकरण और शोषण में लिप्त नहीं हैं, सरकार नियामक लेने के लिए आवश्यक शक्तियों से लैस है

उपाय और यह सुनिश्चित करना कि ये शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें न कि पैसा कमाने के लिए। इतना ही नहीं, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब सरकार के संज्ञान में यह आता है कि कोई विशेष संस्थान शुल्क ले रहा था

या अन्य शुल्क जो अत्यधिक हैं, उसे कम करने के लिए ऐसी संस्था को निर्देश जारी करने का अधिकार है।

69. अगला सवाल यह है कि ऐसा नियामक ढांचा कैसे बनाया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कोई अत्यधिक शुल्क नहीं लिया जाता है। मॉडर्न स्कूल के मामले में, इस न्यायालय ने इस बात की जांच करने के लिए एक समिति के गठन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा कि क्या स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस (जो दिल्ली में स्कूलों द्वारा शुल्क निर्धारित करने का मामला था जो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित हैं) अत्यधिक है या नहीं। का अनुपात

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन में निर्णयों पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गई:

" 16. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में फैसला 31-10-2002 पर दिया गया था। भारत संघ, राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों ने इसमें बहुमत के फैसले को समझा।

अलग-अलग दृष्टिकोण से मामला। इसके कारण कई अदालतों में मुकदमे हुए। इन परिस्थितियों में, पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था
इस्लामी शिक्षा अकादमी के मामले में v. की स्थिति

कर्नाटक ताकि संदेह/विसंगतियों, यदि कोई हो, को स्पष्ट किया जा सके। संबंधित निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक
निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क संरचना का निर्धारण। प्रबंधन की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे संस्थानों को न केवल छात्रों के प्रवेश के संबंध में बल्कि निम्नलिखित के संबंध में भी पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी:

उनकी अपनी शुल्क संरचना के निर्धारण के संबंध में। यह प्रस्तुत किया गया था कि ये संस्थान अपनी शुल्क संरचना तय करने के हकदार थे जिसमें शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से उचित राजस्व अधिशेष शामिल हो सकता है।

यह आंतरिक महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

प्रस्तुत किया गया था कि जब तक कोई मुनाफाखोरी नहीं है, तब तक सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, भारत संघ, राज्य सरकारों और कुछ छात्रों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा अधिकार सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों के अधीन है। यह तर्क दिया गया था कि

शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण राज्य पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे और इसके परिणामस्वरूप राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों को राज्य के कार्य करने की अनुमति दे रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार के पास एक वैधानिक व्यवस्था थी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुनाफाखोरी न हो, शुल्क तय करने का अधिकार। दोनों पक्षों ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में बहुमत के फैसले के विभिन्न अंशों पर भरोसा किया। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को देखते हुए, चार प्रश्न तैयार किए गए थे। हम पहले प्रश्न से

चिंतित हैं, कि क्या शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क संरचना तय करने के हकदार हैं। यह माना गया कि कोई कठोर शुल्क संरचना नहीं हो सकती है। प्रत्येक संस्थान को संस्थान चलाने के लिए धन जुटाने और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए।

अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए जिसका उपयोग उस शैक्षणिक संस्थान की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए। शुल्क संरचना उपलब्ध आधारभूत संरचना और सुविधाओं, किए गए निवेश, शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, संस्थान के विस्तार और/या बेहतरी के लिए भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए, जो दो प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात्, गैर-मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क का गैर-शुल्क। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिशेष/लाभ उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन उनका उपयोग उसके लाभ के लिए किया जाएगा।

शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित किया और इसलिए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुल्क संरचना को मंजूरी देने या कुछ अन्य शुल्क का प्रस्ताव करने के लिए नामित किया जाएगा जो संस्थान द्वारा लिया जा सकता है।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(जोर दिया गया) "

70. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि शुल्क संरचना तय करने के लिए, निम्नलिखित इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

उपलब्ध आधारभूत संरचना और सुविधाएं:

(अ)

किया गया निवेश, शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान;

(ख)

संस्थान के विस्तार और/या बेहतरी के लिए भविष्य की योजनाएं

((ग)

दो प्रतिबंधों के अधीन, अर्थात। गैर-लाभकारी और गैर-लाभकारी
कैपिटेशन शुल्क का प्रभार "।

हम जल्दबाजी में यहाँ यह जोड़ सकते हैं कि अधिनियम, 2007 की धारा 9

उपरोक्त पैरामीटर का बहुत ध्यान रखता है।

71. जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में ही देखा जा सकता है, यह

न्यायालय ने कहा है कि सरकार कैपिटेशन शुल्क और मुनाफाखोरी के प्रभार को नियंत्रित करने के लिए नियम प्रदान कर सकती है। प्रश्न संख्या 3 पहले

न्यायालय इस बारे में था कि क्या सरकारी विनियम हो सकते हैं, और यदि हां, तो निजी संस्थानों के मामले में किस हद तक? अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 57 में जो कहा है, वह हमारे उद्देश्यों के लिए शिक्षाप्रद है।

और वही नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 57. लेकिन हम एक बात पर जोर देना चाहते हैं और वह यह है कि

क्योंकि शिक्षा का व्यवसाय, एक अर्थ में, माना जाता है

धर्मार्थ के रूप में, सरकार ऐसे नियम प्रदान कर सकती है जो

शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना, जबकि शुल्क लेने से मना करना
संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क और लाभ उठाना। चूंकि वस्तु

एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना परिभाषा के अनुसार "धर्मार्थ" है।

यह स्पष्ट है कि कोई शैक्षणिक संस्थान इस तरह का शुल्क नहीं ले सकता है
जैसा कि उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक नहीं है। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना में,

उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा
अनिवार्य रूप से प्रकृति में धर्मार्थ। हालांकि, एक हो सकता है

उचित राजस्व अधिशेष, जो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है

शिक्षा के विकास के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान

और संस्थान का विस्तार "।

निर्णय के अनुच्छेद 69 में, इस मुद्दे पर विचार करते हुए, यह

न्यायालय ने फिर से कहा कि एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जा सकता है

राज्य या विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाता है और कोई मुनाफाखोरी नहीं होती है, हालांकि इसके लिए एक उचित अधिशेष है।

शिक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति है।

हालांकि न्यायालय ने आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

उन्नी कृष्णन में पहले का निर्णय, जो उसमें बनाई गई योजना की सीमा तक था और उसे लागू करने के निर्देश, निर्णय का हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, को वैध माना गया था। इसी तरह, यह सिद्धांत भी सही माना गया कि कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए।

72. जब हम इस्लामी शिक्षा अकादमी के फैसले पर आते हैं, तो इस अदालत द्वारा बनाया गया पहला सवाल यह था कि क्या शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क संरचना तय करने के हकदार हैं। यह है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए एक समिति में लाया गया था जो तब तक संचालित होना था जब तक कि सरकार/उपयुक्त अधिकारी उचित विनियमों को तैयार करने पर विचार नहीं करते। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 20 में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

राज्यों में समितियों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पारित किया गया था और जब तक उचित कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक उन्हें लागू रहना था।

संसद द्वारा अधिनियमित।

73. पी. ए. इनामदार के फैसले में, हालांकि इस्लामी शिक्षा अकादमी में फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी, लेकिन तंत्र को छोड़ दिया

समितियों को अबाधित रखना। फैसले के अनुच्छेद 129 में

पी. ए. इनामदार में, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य विनियमन न्यूनतम होना चाहिए और केवल प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने और अत्यधिक धन या कैपिटेशन शुल्क वसूलकर शोषण को रोकने के लिए होना चाहिए। में।

अनुच्छेद 140 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पूंजी शुल्क का प्रभार केवल अनुमेय नहीं है। इसी तरह, मुनाफाखोरी की भी अनुमति नहीं है। इस न्यायालय ने कहा कि वह शिक्षा के व्यावसायीकरण और कई लोगों द्वारा अपनाई जा रही बुरी प्रथाओं की कठोर वास्तविकताओं के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।

संस्थान अपने निजी या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि अर्जित करते हैं। में।

निजी संस्थानों के मामले में सरकारी विनियमन के संबंध में उसके तहत बनाए गए प्रश्न संख्या 3 के संबंध में, इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 141 में जवाब दिया कि प्रत्येक संस्थान अपनी शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे मुनाफाखोरी को रोकने के हित में विनियमित किया जा सकता है और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। पैराग्राफ 145 में, पोस्ट-ऑडिट या चेक के सुझाव को खारिज कर दिया जाता है यदि संस्थान अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को अपनाते हैं क्योंकि इस न्यायालय का विचार था कि शुल्क के निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।

74. यह उपरोक्त संदर्भ में है कि हमें इस प्रश्न का निर्धारण करना है कि क्या शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधान उल्लंघनकारी [2016] 3 एस. सी. आर. हैं।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत या वे विनियामक प्रकृति के हैं,

जो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञेय है, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास मुनाफाखोरी को रोकने के हित में शुल्क के निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति है और इसके अलावा शुल्क के निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित

किया जाना है। जब हम अधिनियम, 2007 की धारा 9 को उपरोक्त कोण से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि शुल्क निर्धारित करते समय जिन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे वास्तव में वही हैं जो ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित किए गए हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति, अर्थात् - प्रवेश और शुल्क नियामक समिति, केवल निर्वहन कर रही है

नियामक कार्य। वह शुल्क जो एक विशेष शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों से लेना चाहता है, उक्त द्वारा सुझाया जाना चाहिए।

स्वयं शैक्षणिक संस्थान। समिति को एक उद्देश्य के साथ अधिकार दिया गया है

स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था और अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित समझदार कारकों पर आधारित था। इसलिए, हमारे विचार में, यह केवल एक विनियामक उपाय है और अपने स्वयं के शुल्क तय करने के लिए शैक्षणिक संस्थान की शक्तियों को नहीं छीनता है। हम,

इस प्रकार, पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 39 में निहित विवादित निर्णय में इन प्रावधानों का विश्लेषण पूरी तरह से क्रम में है,

जिसमें इसे निम्नलिखित रूप में देखा जाता है:

" 39. हमारा विचार है कि अधिनियम, 2007 की धारा 4 (1) और 4 (8) को अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उन कारकों से संबंधित है जिन्हें समिति द्वारा एक निजी व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान। अधिनियम, 2007 की धारा 9 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलेगा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान का स्थान,

व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति, भूमि और भवन की लागत, उपलब्ध आधारभूत संरचना, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और

एक निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय समिति द्वारा उपकरण, प्रशासन और रखरखाव पर खर्च, पेशेवर संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और किसी अन्य प्रासंगिक कारक पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, विशेष निजी के सभी लागत घटक

गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के साथ-साथ

डर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

संस्थान और पेशेवरों को प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अन्य सभी कारक

शुल्क निर्धारित करते समय समिति द्वारा शिक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। अधिनियम, 2007 की धारा 4 (8) में आगे यह प्रावधान है कि समिति को निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। समिति को शुल्क निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान

जो प्रत्येक व्यावसायिक पाठचक्रम के संबंध में संस्थान द्वारा लिया जा सकता है। प्रत्येक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान, इसलिए, प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से शुल्क लेने के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

सभी लागत घटकों, विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए धारा 9 (1) में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।

अधिनियम, 2007 और समिति का कार्य केवल यह पता लगाना है कि अधिनियम, 2007 की धारा 9 (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद क्या संस्थान द्वारा छात्र से लिए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित हैं और क्या

यह शिक्षा के मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है। "निर्धारण" शब्द को ब्लैक के नियम में परिभाषित किया गया है।

शब्दकोश, आठवें संस्करण का अर्थ है न्यायालय या एक प्रशासनिक एजेंसी द्वारा अंतिम निर्णय। इसलिए, समिति शुल्क का निर्धारण करते समय केवल संतुष्ट होने के बाद प्रस्तावित शुल्क को अंतिम मंजूरी देती है, कि यह अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था और शिक्षा का कोई मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण नहीं था। अधिनियम, 2007 की धारा 4 (1) में 'शुल्क निर्धारण' का अर्थ है कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से लिया जाने वाला शुल्क छात्र-छात्र में भिन्न नहीं था और

अधिनियम, 2007 की धारा 4 (8) में उल्लिखित एक निश्चित अवधि के लिए भी निर्धारित रहा। जैसा कि सर्वोच्च द्वारा आयोजित किया गया है

पीयरलेस जनरल फाइनेंस बनाम में न्यायालय। भारतीय रिजर्व बैंक (ऊपर), न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कानून के प्रावधानों के सार की जांच करनी होगी कि क्या कानून के प्रावधान लागू करते हैं।

आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध। द.

अधिनियम, 2007 की धारा 4 (1), 4 (8) और 9 के प्रावधान समिति को केवल इस बात से संतुष्ट होने का अधिकार देते हैं कि प्रस्तावित शुल्क

एक निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा शिक्षा का मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण नहीं था और यह [2016] 3 एस. सी. आर. पर आधारित था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 2007 की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारक। इसलिए अधिनियम, 2007 के प्रावधान निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थान के अपने शुल्क लेने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।

प्रतिबंध लगाते हैं और किसी भी संवैधानिक बुराई से पीड़ित नहीं होते हैं। 75. इसलिए अधिनियम और नियमों का प्रावधान पी. ए. इनामदार में निहित भावनाओं और निर्देशों के अनुरूप है। द.

विचाराधीन अधिनियम किसी भी मौजूदा केंद्रीय कानून की अवहेलना नहीं करता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर सी. ई. टी. की शुरुआत का संबंध है, इसे राज्य क़ानून के संचालन की अवधि के दौरान लागू नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में, इन संस्थानों के शुल्क के निर्धारण या निर्धारण के संबंध में कोई नियम नहीं होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं देते हैं, राज्य विधानमंडल उसी के संबंध में प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

76. उस समय जब विवादित कानून बनाए गए थे,

निजी महाविद्यालय संघ पहले से ही वर्ष 2005 से 2007 तक अपनी सी. ई. टी. आयोजित कर रहा था। हालाँकि, निजी विश्वविद्यालय टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का पालन करने में विफल रहे थे और मेधावी छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के संबंध में राज्य के अधिकारियों को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं। पैराग्राफ 32 से 39 में

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर में, यह विधिवत उल्लेख किया गया था कि निजी कॉलेजों के संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे सी. ई. टी. के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य के कानून लागू होने के बाद की अवधि के लिए भी, इस न्यायालय द्वारा पारित 27 मई, 2009-1 के अंतरिम आदेश के तहत, जिसमें निजी कॉलेजों को एनआरआई सीटों को छोड़कर 50 प्रतिशत सीटों के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, राज्य को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं। यदि किसी प्रणाली में प्रचलित कदाचार और/या बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता होती है, तो विधानमंडल ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, बशर्ते वह संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरता हो, जो वह संविधान के प्रावधानों में करता है।

21 (2009) 7 एससीसी 751}

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

77. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे 'वैश्वीकरण' के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में, निस्संदेह निजी खिलाड़ियों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। आर्थिक गतिविधियाँ, जैसा कि मान्यता ने इस वास्तविकता की ओर आकर्षित किया है कि व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय आदि सहित आर्थिक गतिविधियाँ राज्य की सामान्य विशेषता नहीं हैं और इसमें राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यही कारण है कि दूरसंचार, बिजली, बीमा, नागरिक उड्डयन आदि जैसे कई क्षेत्र जो अब तक राज्य के एकाधिकार में थे, अब निजी उद्यमों के लिए खुल गए हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य /

जनता और आम लोगों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर शिक्षा प्रदान करना। यह था। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक और तकनीकी, वैज्ञानिक और तकनीकी

सहित सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना सरकार का लगभग गंभीर कर्तव्य माना जाता है। पेशेवर, समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से, जब देश की एक तिहाई आबादी गरीबी से ग्रस्त है।

निजी क्षेत्र द्वारा शोषण, निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उन आर्थिक गतिविधियों के संबंध में भी जो निजी क्षेत्र द्वारा की जाती हैं अनिवार्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से (और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है), इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को निजी क्षेत्र के हाथों में देते हुए, राज्य ने नियामक व्यवस्था की शुरुआत की है:

अच्छी तरह से प्रासंगिक कानूनों के तहत विनियम प्रदान करके।

विनियामक यंत्रों की आवश्यकता:

79. नियामक तंत्र, या जिसे नियामक अर्थशास्त्र कहा जाता है, [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दिन का क्रम है। पिछले 60-70 वर्षों में, इसकी आर्थिक नीति

देश ने विनियामक शासन के साथ उदार अर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में लैसेज़ फेयर से मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा की है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी आई और विमानन, बीमा, रेलवे, बिजली/बिजली, दूरसंचार आदि जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार हो गया। लाइसेंस/परमिट

राज इस अवधि के दौरान सरकार के सख्त नियंत्रण के साथ उन उद्योगों के संबंध में भी प्रचलित था जहां निजी क्षेत्रों को संचालित करने की अनुमति थी। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 90 के दशक की शुरुआत में एलपीजी मॉडल पर बड़े नीतिगत बदलावों का अनुभव किया, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और

वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए सुधारों की शुरुआत के साथ,

जुलाई 1991 में भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आर्थिक परिवर्तन की इस अवधि का समग्र आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

80. जब हमारे पास उदार अर्थव्यवस्था होती है जो बाजार की ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है (इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है), तो ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आपूर्ति और मांग द्वारा स्थापित मुक्त मूल्य प्रणाली में निर्धारित की जाती हैं। यह अक्सर एक नियोजित अर्थव्यवस्था के विपरीत होता है जिसमें एक केंद्र सरकार एक निश्चित मूल्य प्रणाली का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित करती है। बाजार अर्थव्यवस्थाएँ भी हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के विपरीत जहां मूल्य प्रणाली पूरी तरह से मुक्त नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी नियंत्रण या भारी विनियमित है, जिसे कभी-कभी राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना के साथ जोड़ा जाता है जो एक नियोजित अर्थव्यवस्था का गठन करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं है।

अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व शुद्ध रूप में नहीं होना चाहिए। बाजार की ताकतों द्वारा स्व-विनियमन की अनुमति देने के बजाय विभिन्न उद्योगों के कुछ विनियमन की आवश्यकता है। नियामक निकायों के माध्यम से यह हस्तक्षेप, विशेष रूप से मूल्य निर्धारण में, है समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाने वाली और अर्थशास्त्री बताते हैं कि ऐसी नियामक अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था के चरित्र को नहीं छीनती है जो अभी भी एक बाजार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित ऐसे उद्योगों में भी नियामक निकायों के लिए औचित्य लोगों के कल्याण में निहित है। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बुनियादी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विनियामक उपायों को आवश्यक महसूस किया जाता है। इस वजह से

इसका कारण यह है कि हम सभी महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे बीमा, बिजली और बिजली, दूरसंचार आदि में नियामक निकाय पाते हैं।

82. इस प्रकार, यह महसूस किया जाता है कि किसी भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में, यहां तक कि निजी आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के लिए भी।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

&

उद्योगों में नियामक निकाय की आवश्यकता है और शिक्षा क्षेत्र के लिए इस तरह का नियामक ढांचा और भी आवश्यक हो जाता है। यह तब अधिक होगा जब, अन्य उद्योगों के विपरीत, भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है।

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय इस आशय के हैं कि शिक्षा में मुनाफाखोरी से बचा जाए।

83. इस प्रकार, जब ऐसे नियामक हो सकते हैं जो शुल्क तय कर सकते हैं

दूरसंचार कंपनियों के लिए विभिन्न सेवाओं के संबंध में जो ऐसी कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रदान करती हैं; जब नियामक प्रीमियम तय कर सकते हैं और

उन्हें शिक्षित करें। शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए, यह संवैधानिक लक्षय महत्वपूर्ण बना हुआ है जो इसे अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ विरोधाभास में विशिष्ट और विशेष बनाता है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और इस तरह एक बेहतर समाज लाना है क्योंकि इसका उद्देश्य बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना है जो समाज में योगदान देगा। राष्ट्र का आर्थिक और राजनीतिक उत्थान। समाज के कल्याण की अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूती से लागू होगी। अन्यथा भी, अर्थशास्त्री के लिए, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में शिक्षा, कृषि और उद्योग जैसी अन्य आर्थिक चिंताओं की तुलना में अनुकूल रूप से, अपने स्वयं के निवेश और परिणाम हैं और इस प्रकार इसका विश्लेषण बुनियादी आर्थिक साधनों जैसे कि वापसी के नियम, समतुल्य उपयोगिता के सिद्धांत और सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में किया जाता है। इन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, राज्य को शिक्षा में उस बिंदु तक निवेश करना चाहिए जहां शिक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ अन्य राज्यों के बराबर हो।

व्यय, जबकि व्यक्ति एक प्रकार की शिक्षा के लिए भुगतान करने के अपने निर्णय में उसे प्राप्य रिटर्न की संभावना से निर्देशित होता है। ये सभी विचार एक स्थिर नियामक की स्थापना के लिए एक मामला बनाते हैं। तंत्र।

84. इस मायने में, जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है

समाज का वर्ग, विशेष रूप से कमजोर वर्ग और जब ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थान महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन की चुनौती का सामना करने के लिए राज्य द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं।

:

संवैधानिक वादे, मामले की जांच एक अलग रंग में की जानी है। यह वह भावना है जिसे हमने अधिकार को संतुलित करते हुए ध्यान में रखा है।

इन शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत दिया गया है

एक हाथ और लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता

विवादित कानून द्वारा। प्रवेश का अधिकार या शुल्क तय करने का अधिकार

इन अपीलार्थियों को दी गई गारंटी पूरी तरह से नहीं ली गई है, जैसा कि आशंका है।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन ऐसे संस्थानों को स्वायत्तता देता है जो अभी भी मौजूद हैं। अक्षत। सी. ई. टी. को राज्य के नियंत्रण में रखने में कोई बाधा नहीं है

यह स्वायत्तता। प्रवेश अभी भी इन संस्थानों के हाथों में है। एक बार

अपीलार्थियों द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि छात्रों के प्रवेश में तीन गुना

परीक्षण 'पूरा किया जाना है, विवादित कानून का उद्देश्य वही है। आखिरकार, एकमात्र

सी. ई. टी. आयोजित करने का उद्देश्य योग्यता का निर्धारण करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रवेश

जो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, वे पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होते हैं। यह

पुनः व्यापक जनहित सुनिश्चित करने के लिए है। यह समझ से परे है कि

केवल सी. ई. टी. रखने की शक्ति ग्रहण करके, का मौलिक अधिकार

छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपीलकर्ताओं को ले जाया जाता है। इसी तरह, जब यह आता है शुल्क निर्धारित करने के लिए, जैसा कि पहले से ही विस्तार से बताया गया है, मुख्य उद्देश्य यह है कि

राज्य एक नियामक के रूप में कार्य करता है और खुद को संतुष्ट करता है कि प्रस्तावित शुल्क

शैक्षणिक संस्थान में मुनाफाखोरी का तत्व नहीं है

और यह भी कि कोई कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं लिया जाता है। वास्तव में, यह दोहरा कार्य विनियामक प्रकृति सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने जा रही है जैसे कि

वे छात्र जो अन्यथा मेधावी हैं लेकिन इस स्थिति में नहीं हैं

-कैपिटेशन शुल्क आदि की अनुचित मांगों को पूरा करने से वंचित नहीं हैं

प्रवेश मिलता है। इसलिए, विवादित प्रावधानों का उद्देश्य है -

व्यापक लोक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना। कानून स्थिर नहीं है, यह

बदलते समय और बदलती सामाजिक/सामाजिक स्थितियों के साथ बदलना पड़ता है।

III. री. : अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण,

अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग

85. इस मुद्दे पर अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह है कि

निजी क्षेत्र में आरक्षण संवैधानिक योजना के लिए अज्ञात है

और पी. ए. के मामले में इस न्यायालय द्वारा ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है।

इनामदार। यह उनकी दलीलें हैं जो निर्णय के अनुपात को खारिज करती हैं।

पी. ए. इनामदार में इस न्यायालय की संसद ने संविधान में संशोधन किया

और अनुच्छेद 15 (5) पेश किया। उक्त अनुच्छेद 15 (5) निम्नानुसार है:

" 15 (5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

कानून द्वारा, किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति के लिए

नागरिकों के पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के लिए।

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

अनुसूचित जनजातियाँ जहाँ तक इस तरह के विशेष प्रावधान संबंधित हैं -

निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश

शैक्षणिक संस्थान, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा

अनुच्छेद 30 का खंड (1)।

86. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाति आधारित आरक्षण नीति या राज्य सरकार की सामाजिक इंजीनियरिंग नीति को उन निजी संस्थानों के कंधों पर नहीं चलाया जा सकता है जिन्हें संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा और तरीका जिस अधिकार को विनियमित किया जा सकता है, वह संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत निर्धारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. ए. इनामदार में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निजी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान होगा

' अनुचित प्रतिबंध और इसलिए, 19 (1) (जी) का उल्लंघन होगा और भारत के संविधान के 19 (6) द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तर्क के आधार पर निजी संस्थानों में आरक्षण को खारिज किया गया है, वह यह है कि इस न्यायालय ने पाया कि इस तरह के प्रतिबंध 'अनुचित' प्रतिबंध होंगे और इसलिए, प्रभावी रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) का उल्लंघन करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 15 (5) के प्रावधान अनुच्छेद 14 के अपवाद नहीं हैं और इसलिए, जब न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि -

निजी संस्थानों में आरक्षण अनुचित, विवादित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

87. किसी भी मामले में, चूंकि पी. ए. इनामदार में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

राज्य द्वारा आरक्षण का कोई निर्धारण या सीटों का विनियोग नहीं किया जा सकता है, आरक्षण जो कोटा को अलग करता है,

अनुमति है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि प्रावधानों को वापस लाना चाहते हैं

राज्य कोटा स्थापित करने की उन्नी कृष्णन प्रणाली जो

इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य माना गया। इस तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि अनुच्छेद 15 के खंड (5) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विवादित निर्णय से देखा जा सकता है।

संविधान, नियम, 2008 के नियम 4 (2), 7 और 15 के साथ पठित धारा 8 को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी गई थी। वास्तव में, अपीलार्थियों के वकील ने स्वीकार किया कि उन्होंने 93 वें संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी थी संविधान में किस अनुच्छेद 15 (5) को जोड़ा गया था। जो भी हो,

उक्त संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने के लिए शायद ही कोई आधार है, जिसे प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के मामले में संविधान पीठ के फैसले द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। एकमात्र अन्य

यह तर्क दिया गया कि नियम [2016] 3 एस. सी. आर. में आरक्षण प्रावधानों को पढ़ा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 नियम, 2009 से पता चलेगा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न विशेष विषयों में स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या कम है, उक्त प्रतिशत का पता लगाना मुश्किल होगा। उच्च न्यायालय ने इस तर्क से सफलतापूर्वक निपटा है -

शुल्कों के माध्यम से उचित रूप से यह प्रदर्शित करना कि न केवल विभिन्न वर्गों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण की सीमा का पता लगाना संभव था।

श्रेणियां, सामान्य के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध थीं

श्रेणियाँ भी। इस प्रकार, हम एससी/एसटी और ओ. बी. सी. आदि के लिए सीटों के आरक्षण को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के साथ।

88. जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 2015 के आई. ए. संख्या 83 में दायर अपने जवाब में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है, निजी महाविद्यालयों का संघ अपने सी. ई. टी. को निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसंगत तरीके से आयोजित करने में विफल रहा है। राज्य के कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता निजी कार्यों की तुलना में बहुत अधिक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य तंत्र में भ्रष्टाचार की घटनाओं को जनता की नजरों में लाया गया था

तुरंत और तेजी से संबोधित किया गया है। ऐसा भी हो सकता है।

निजी कार्यों के मामले में कभी नहीं किया गया है। तुलनात्मक दक्षता पर भी, यह स्पष्ट है कि राज्य की प्रक्रिया निजी कॉलेजों द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिनके पास किसी भी नियंत्रण और संतुलन का कोई तंत्र नहीं है। राज्य की एजेंसियां सूचना का अधिकार अधिनियम, लेखा परीक्षा, राज्य के अधीन हैं।

विधायिका, भ्रष्टाचार-रोधी अभिकरण, लोकायुक्ता आदि।

89. राज्य के लिए संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य एक कल्याणकारी कार्य है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक मानकों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। जिस पर

दूसरी ओर, निजी दलों के लिए प्राथमिक प्रेरणा लाभ का उद्देश्य या परोपकार है। जब संस्थानों के लिए प्राथमिक प्रेरणा लाभ का उद्देश्य है,

यह स्वाभाविक है कि इसे प्राप्त करने के लिए कई साधन अपनाए जाएंगे। निजी संस्थान जो बड़े पैमाने पर गोपनीयता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार, विवादित कानूनों के तहत परिकल्पित विनियमों का तंत्र कानूनी, संवैधानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी है और योग्यता के प्राथमिक मानदंडों को बनाए रखता है। वही उल्लंघन नहीं करता है

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए

वैध है।

IV. क्या विवादित कानून इससे परे है

मध्य प्रदेश राज्य की विधायी क्षमता?

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

90. अगला मुद्दा जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या प्रवेश की विषय वस्तु विशेष रूप से सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा कवर की गई थी, जिससे राज्यों के पास इससे निपटने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है।

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश या शुल्क के निर्धारण का विषय।

91. अपीलार्थियों की ओर से मुख्य निर्भरता भारती विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय) और अन्य पर रखी गई है। वी. महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. अपीलकर्ताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. पर भी भारी निर्भरता रखी। वी. श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और डॉ. प्रीति के मामले में संविधान पीठ का निर्णय

92. प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं: सूची 1, प्रविष्टि 66 और सूची 3, प्रविष्टि 25। इस प्रक्रिया में, सूची II, प्रविष्टि 32 पर भी एक नज़र डालने की आवश्यकता है। अतः इसके लिए उचित विश्लेषण, हम इन प्रविष्टियों को नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" सूची I

· 66 . उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण

संस्थाएं। सूची II

32. सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा निगमों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साक्षरता, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और

संघ; सहकारी समितियाँ।
सूची III

25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

93. हमारे दिमाग में, सूची I में प्रविष्टि 66 एक विशिष्ट प्रविष्टि है जिसमें बहुत कुछ है

विशिष्ट और सीमित दायरा। यह उच्च शिक्षा या अनुसंधान के साथ-साथ संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण से संबंधित है।

मानकों के निर्धारण का अर्थ होगा उक्त मानकों को निर्धारित करना। 22 (2004) 11 एससीसी 755

23 1964 (पूरक) 1 एस. सी. आर. 112

24 (1999) 7 एससीसी 120 [2016] 3 एस. सी. आर.

इस प्रकार, जब उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों के लिए मानकों को निर्धारित करने की बात आती है, तो संघ को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। हालांकि, इसमें परीक्षा आदि आयोजित करना और ऐसे संस्थानों में छात्रों का प्रवेश या उच्च शिक्षा के इन संस्थानों में शुल्क निर्धारित करना आदि शामिल नहीं होगा। वास्तव में, इस तरह के समन्वय और निर्धारण जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है, मानकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के रूप में संसदीय कानून द्वारा और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसे वैधानिक निकाय का निर्माण करके प्राप्त किया जाता है।

(संक्षेप में, 'एमसीआई')। एमसीआई को सौंपे गए कार्यों में एक चिकित्सा संस्थान में मानकों के व्यापक निर्धारण के साथ-साथ मानकों और शैक्षणिक संस्थानों का समन्वय शामिल है। जब शिक्षा को विनियमित करने की बात आती है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय (जो उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं) भी शामिल हैं।

शिक्षा), जो सूची III की प्रविष्टि 25 में निर्धारित है, जिससे संघ और राज्यों दोनों को समवर्ती शक्तियां मिलती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि

ध्यान दें कि विश्वविद्यालयों सहित पूर्व शिक्षा, सूची II में प्रविष्टि 11 का विषय था। इस प्रकार, इस हद तक शक्ति राज्य विधानमंडलों को दी गई थी। हालाँकि, इस प्रविष्टि को संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा 3 जुलाई, 1977 से हटा दिया गया था और उसी समय सूची II में प्रविष्टि 25 में संशोधन किया गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा सहित शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रक्रिया में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को भी जोड़ा गया। अत: यदि

अपीलार्थियों का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, यह प्रविष्टि 25 को पूरी तरह से अनुचित बना सकता है। जब शिक्षा से संबंधित दो प्रविष्टियाँ, एक संघ सूची में और दूसरी समवर्ती सूची में, सह-अस्तित्व में होती हैं, तो उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि

जब उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारित करने की बात आती है, तो राज्य को बाहर करने की शक्ति केंद्र/संसद के पास होती है।

विधायिकाएँ। हालांकि, तकनीकी सहित शिक्षा के अन्य पहलू और चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के शासन का संबंध है, यहां तक कि राज्य विधानमंडलों को भी प्रविष्टि 25 के आधार पर शक्ति दी जाती है। सूची III की प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया गया क्षेत्र काफी चौड़ा है और सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के अधीन होने की सीमित सीमा तक सीमित है।

94. प्रवेश सहित अधिकांश शैक्षणिक गतिविधियों में दो हैं।

25 प्रविष्टि 11: विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, प्रविष्टि 63 के प्रावधानों के अधीन। 64. 65 और सूची I की 66 और सूची III की प्रविष्टि 25

26 सूची III में असंशोधित प्रविष्टि 25 इस प्रकार है: ' श्रम का सामयिक और तकनीकी प्रशिक्षण 'आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

पहलू: पहला शिक्षा के न्यूनतम मानकों को अपनाने और स्थापित करने से संबंधित है। न्यूनतम मानक निर्धारित करने का उद्देश्य पूरे देश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की क्षमता और गुणवत्ता का एक मानक प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के मानकों का समन्वय निर्धारित किया जाता है

राष्ट्रव्यापी मानकों के निर्धारण के लिए सहायक है। राष्ट्र की विशाल विविधता को महसूस करते हुए, जिसमें शिक्षा के स्तर बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की कमी से उच्च उत्कृष्टता वाले संस्थानों में उतार-चढ़ाव करते थे, विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना और निर्धारित करना वांछनीय था।

अनुसंधान संस्थानों, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों का स्तर। इस प्रकार, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए,

राष्ट्र के लिए एक समान न्यूनतम मानक निर्धारित करना आवश्यक था। नतीजतन, संविधान निर्माताओं ने अनुसंधान, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से सूची I में प्रविष्टि 66 का प्रावधान किया।

95. शिक्षा का दूसरा/अन्य पहलू शिक्षा के द्वारा निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में है।

संसद, और शिक्षा की संपूर्ण गतिविधि का विनियमन। इस गतिविधि में अनिवार्य रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में संसद द्वारा निर्धारित मानकों का अनुप्रयोग शामिल है। इस प्रकार, जबकि प्रविष्टि 66 सूची I मानकों के निर्धारण और समन्वय से संबंधित थी, दूसरी ओर, सूची II की मूल प्रविष्टि 11 ने राज्यों को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की।

शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के संबंध में, न्यूनतम मानकों के निर्धारण और समन्वय को छोड़कर जो राष्ट्रीय हित में था। तत्पश्चात, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के विशिष्ट विधायी क्षेत्र के संबंध में -

शिक्षा को हटा दिया गया और हटा दिया गया, और उसी को प्रतिस्थापित किया गया प्रविष्टि 25, सूची 3 में संशोधन, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां प्रदान करना, सिवाय इसके कि जो विशेष रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत आता था:

सूची I की प्रविष्टि 63 से 66 तक।

96. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारती विद्यापीठ में यह देखा गया है कि प्रवेश का पूरा दायरा सूची I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है।

हालाँकि, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय पहले की बड़ी पीठ के फैसलों में निर्धारित कानून के विपरीत है। गुजरात विश्वविद्यालय में, एक बेंच एस. यू. आई. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

पाँच न्यायाधीशों में से पाँच न्यायाधीशों ने सूची I की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 2 (जो अब सूची III की प्रविष्टि 25 है) के दायरे की जांच की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति जिस हद तक संसद को सौंपी गई है, उसे प्रतिबंधित माना जाता है। मानकों का समन्वय और निर्धारण सूची I के दायरे में था और राज्य की शक्ति उक्त विषय पर संघ की शक्ति के अधीन थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों प्रविष्टियाँ कुछ हद तक परस्पर व्याप्त हैं और सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा प्रदत्त शक्ति को राज्य की शक्ति पर प्रबल होना चाहिए। राज्य विधान की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह संघ विधान के अभाव में भी 'मानकों के समन्वय या निर्धारण' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आर. चित्रलेखा बनाम। मैसूर राज्य, वही मुद्दा फिर से था

संस्थान & Ors.28, यह देखा गया कि इस हद तक कि राज्य विधान यदि प्रविष्टि 25 के तहत केंद्रीय कानून के साथ टकराव में है, तो यह अमान्य और निष्क्रिय होगा। डॉ.

प्रीति श्रीवास्तव और महाराष्ट्र राज्य बनाम में इसी प्रभाव का दृष्टिकोण लिया गया है। संत ज्ञानेश्वर शिक्षा

शास्त्र महाविद्यालय और अन्य। " यद्यपि मध्य प्रदेश राज्य बनाम में लिया गया दृष्टिकोण। कुमारी निवेदिता जैन और अजय कुमार सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। इस प्रभाव से कि सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा कवर किए गए प्रवेश मानकों को केवल प्रवेश के बाद ही लागू किया जा सकता था, डॉ. प्रीति श्रीवास्तव में खारिज कर दिया गया था, यह नहीं माना गया था कि प्रवेश का पूरा सरगम सूची I द्वारा कवर किया गया था जैसा कि भारती विद्यापीठ में गलत तरीके से माना गया था।

97. हमें यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता है कि डॉ. प्रीति श्रीवास्तव राज्यों की भूमिका को प्रवेश से पूरी तरह से अलग करती हैं। इस प्रकार, भारती विद्यापीठ में टिप्पणियों कि प्रवेश के पूरे सरगम को सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा कवर किया गया था, को उस हद तक बरकरार और खारिज नहीं किया जा सकता है। नहीं।

संदेह, सूची III की प्रविष्टि 25 प्रविष्टि 66 सूची I के अधीन है, सूची III की प्रविष्टि 25 से प्रवेश के पूरे सरगम को बाहर करना संभव नहीं है।

हालाँकि, सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग प्रविष्टि 25 के लिए संदर्भित केंद्रीय कानून के अधीन होना चाहिए। 27 (1964) 6 एससीआर 368

29 (2006) 9 एससीसी 1 30 (1981) 4 एससीसी 29

31 (1994) 4 एससीसी 40 जे

जे. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

98) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा संचालित किए जा रहे सी. ई. टी. में शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

या राज्य द्वारा नामित या शुल्क निर्धारित करने वाली एजेंसी। ऐसा करने का राज्य का अधिकार केंद्रीय कानून के अधीन है। एक बार जब 'एन. ई. ई. टी.' नामक सी. ई. टी. के संचालन के लिए केंद्रीय कानूनों के तहत अधिसूचनाएं लागू हो जाएंगी, तो यह राज्यों और केंद्र के बीच का मामला होगा।

इसे संविधान के अनुच्छेद 254 की कसौटी पर सुलझाना होगा। हमें इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

EPILOGUE:

99. इस मामले से अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि हमने पक्षों के बीच समझौता तय कर लिया है, लेकिन यह अपने आप में उन सभी बुराइयों को ठीक नहीं करता है जिनसे व्यवस्था पीड़ित है और कुछ और करने की आवश्यकता है।

उस मोर्चे पर भी किया। अपीलार्थियों की ओर से की गई शिकायत का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि राज्य द्वारा नामित एजेंसी द्वारा भी राज्य के कानून या केंद्रीय कानून के तहत किए गए प्रवेशों में विश्वसनीयता की कमी हो सकती है। इस अदालत ने पी. ए. अनामदार में भी इस चिंता पर ध्यान दिया है। इससे निपटने के लिए एक चतुर और दूरदर्शी दृष्टिकोण भी आवश्यक है।

जमीनी वास्तविकताओं के साथ। इस न्यायालय ने पहले प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए सभी राज्यों में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समितियों की नियुक्ति की थी। यह उपयुक्त होने तक एक ठहराव व्यवस्था थी। कानून बनाया गया था और एक बार एक वैधानिक कानून के तहत प्रवेश प्रक्रिया चालू हो जाने के बाद, नियामक तंत्र के उचित कामकाज के विषय पर सभी संबंधितों की शिकायतों को ठीक से संबोधित करने की आवश्यकता होगी। यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि केंद्र सरकार ने स्वयं डॉ. रंजीत रॉय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त किया था

चौधरी ने 07 जुलाई, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए कहा। उक्त समिति ने 25 सितंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट में सुधारों का सुझाव दिया।

चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा पेशे का विनियामक निरीक्षण। सिफारिशों में स्नातक के तहत पर्यवेक्षण का विषय शामिल था।

और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ अन्य संबंधित मुद्दे। यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 92 वीं रिपोर्ट में 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की कार्यप्रणाली' पर अपनी बात रखी है। 8 मार्च, 2016 को राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय चिकित्सा परिषद इस मामले में गई है। हो सकता है कि

अन्य सेवा उन्मुख व्यवसायों के लिए भी नियामक तंत्र की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे पर उचित समय पर विधि आयोग सहित संबंधित अधिकारियों का ध्यान जाएगा।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100. समिति ने चिकित्सा पेशे, यानी एमसीआई के नियामक निरीक्षण की मौजूदा संरचना की जांच की। यह देखा गया कि एमसीआई बार-बार अपने लक्षय को पूरा करने में विफल रहा है।

अनिवार्य जिम्मेदारियाँ। चिकित्सा शिक्षा की योग्यता अपने सबसे निचले स्तर पर थी, सही प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवर देश की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले उत्पाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और यहां तक कि जिला स्तर पर भी खराब संसाधन व्यवस्थाओं में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चिकित्सा स्नातकों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल कार्यों को करने में कुशलता की कमी थी। अनैतिकता के उदाहरण

कॉन प्रथाओं का विकास जारी रहा। एमसीआई चिकित्सा शिक्षा में किसी भी गंभीर सुधार का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था। एमसीआई ने न तो प्रतिनिधित्व किया

पेशेवर उत्कृष्टता और न ही इसके लोकाचार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नामांकित व्यक्ति भी कॉर्पोरेट निजी अस्पतालों से थे जो अत्यधिक व्यावसायीकृत हैं। यह भी पाया गया कि वे मूल्य ढांचे का उल्लंघन कर रहे थे और अनैतिक प्रथाओं में लिप्त थे जैसे कि

निकालने के लिए अनावश्यक निदान परीक्षण और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएँ

असहाय रोगियों से धन। चुनावी प्रक्रियाएँ बहुत सारे समझौते लाती हैं और पेशेवरों को आकर्षित करती हैं जो नियामक निकाय के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। पेशेवर ईमानदारी और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों के नियामकों को एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। समिति ने रंजीत राय चौधरी समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के साथ सहमति व्यक्त की कि

विनियामक संरचना को चुनाव या नामांकन के बजाय पारदर्शी तंत्र के माध्यम से चुने गए व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के पास एमसीआई से असहमत होने की कोई शक्ति नहीं थी, हालांकि

स्वास्थ्य योजनाओं को आकार देने में सरकार मुख्य हितधारक थी। सरकार के पास नियामक निकाय को नीतिगत निर्देश देने की शक्ति होनी चाहिए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा की मौजूदा प्रणाली

इसका पुनः आविष्कार करने की आवश्यकता थी। प्रवेश प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेजों में अधिकांश सीटें कैपिटेशन शुल्क के लिए आवंटित की जा रही थीं। यह प्रणाली सबसे मेधावी और वंचित छात्रों को बाहर रखती है। एकात्मक सी. ई. टी. कैपिटेशन शुल्क से निपटेगी और पारदर्शिता लाएगी। स्नातकोत्तर सीटें प्रवेश की पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अभाव में बेची जा रही थीं। इसने शिक्षण संकाय और डॉक्टरों के पेशेवर आचरण के विनियमन में कमी को भी नोट किया। एमसीआई में भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए यह था

उन्होंने सिफारिश की कि कानून में संशोधन करने और एक नया कानून बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली असंतोषजनक पाई गई। समिति के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

डर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v. मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

" समिति का मानना है कि देश में चिकित्सा शिक्षा के नियामक के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद दशकों से अपने सभी आदेशों पर बार-बार विफल रही है। समिति ने इस रिपोर्ट के पहले भाग में इन विफलताओं से कुछ विवरणों में निपटा है। इस खंड में, समिति समस्या के समाधान का सुझाव देने से पहले, चीजों को उचित परिप्रेक्षय में रखने के लिए एमसीआई की निम्नलिखित प्रमुख विफलताओं पर संक्षेप में बात करना चाहेगी:

(i) ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने में विफलता जो भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और गरीब शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए उपयुक्त डॉक्टर तैयार करे; इससे दोनों के बीच संबंध टूट गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली;

((ii) स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने में विफलता;

(iii) प्रवेश में योग्यता का विकास, विशेष रूप से निजी चिकित्सा संस्थानों में कैपिटेशन शुल्क के प्रचलन के कारण, जो चिकित्सा शिक्षा को केवल अमीरों के लिए उपलब्ध कराता है और अमीरों के लिए नहीं।

अनिवार्य रूप से सबसे योग्य के लिए;

((iv) एक सक्षम बुनियादी चिकित्सक तैयार करने में विफलता; (v) चिकित्सा स्नातकों और स्नातकोत्तरों के किसी भी मानकीकृत सारांशात्मक मूल्यांकन में एमसीआई की गैर-भागीदारी;

(vi) जब कोई नया स्नातक प्रणाली में प्रवेश करता है और अभ्यास करना शुरू करता है तो एक मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करने में विफलता;

(vii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पर बहुत कम निगरानी से मानकों में भारी बदलाव होता है: (viii) निरीक्षण के दौरान बुनियादी ढांचे और मानव कर्मचारियों की बारीकियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन गुणवत्ता का कोई पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना:

(ix) बहुत खराब डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात;

(x) मेडिकल कॉलेज निरीक्षण और मान्यता या मान्यता रद्द करने की एक पारदर्शी प्रणाली बनाने में विफलता;

(xi) आवश्यकता के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्गदर्शन करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप भौगोलिक रूप से चिकित्सा का वितरण खराब हो जाता है।

कुछ राज्यों में क्लस्टर वाले कॉलेज और कई [2016] में अनुपस्थित 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य राज्यों और राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता;

(xii) चिकित्सा शिक्षकों की भारी कमी;

(xiii) देश में निरंतर चिकित्सा शिक्षा की देखरेख और मार्गदर्शन करने में विफलता, इस महत्वपूर्ण कार्य को हाथों में छोड़ते हुए

वाणिज्यिक निजी उद्योग;

(xiv) चिकित्सा पेशेवर में नैतिकता की एक पेशेवर संहिता के लिए सम्मान पैदा करने और आचार संहिता आदि का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में विफलता। (पैरा 13.1)

समिति ने साथ ही कहा कि चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की विफलता की जिम्मेदारी विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद पर नहीं रखी जा सकती है। लगातार आने वाली सरकारों का भी इसमें अपना हिस्सा है। यह तथ्य कि राज्यों में मेडिकल कॉलेजों के वितरण में असंतुलन है, एमसीआई की गलती नहीं है; यह लगातार सरकारों की गलती है कि उन्होंने एमसीआई को उस दिशा में आगे नहीं बढ़ाया। राज्य सरकार की ओर से भी विफलता है। (पैरा 13.2)

चिकित्सा पेशे के नियामक ढांचे में आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता कई वर्षों से कार्यसूची में रही है।

राष्ट्रीय मानव संसाधन उपचार आयोग विधेयक, 2011, जिसे 22 दिसंबर, 2011 को राज्य सभा में पेश किया गया था, इस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस पर 60 वीं रिपोर्ट 23 नवंबर, 2012 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। अपनी 60 वीं रिपोर्ट में समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उसके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की फिर से जांच करने और एक नया विधेयक लाने की सिफारिश की थी। एक बेहतर विधेयक लाने के अवसर का लाभ उठाने के बजाय, मंत्रालय बना रहा

एम. सी. आई. की भारी विफलताओं और सुधारों को लागू करने में सरकार की ओर से पहलों की कमी के कारण, प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है, जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा प्रणाली तेजी से नीचे की ओर खिसक रही है और चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार के बढ़ते व्यावसायीकरण के संदर्भ में गुणवत्ता को काफी कम किया गया है। स्थिति उस बिंदु से बहुत आगे निकल गई है जहाँ वृद्धि हो रही है। मौजूदा प्रणाली या टुकड़ों-टुकड़ों में दृष्टिकोण में बदलाव से विचारित लाभांश मिल सकता है।

यही कारण है कि समिति दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v है। मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

यह मानते हुए कि एमसीआई को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ठीक नहीं किया जा सकता है।

निश्चित रूप से पुराना है। अगर हम मौजूदा अधिनियम में संशोधन या संशोधन करने का प्रयास करते हैं, तो दस साल बाद भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होंगे जिनका हम आज

सामना कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी शैक्षिक प्रक्रिया का निरीक्षण नहीं है, विशेष रूप से, चिकित्सा शिक्षा का निरीक्षण एमसीआई जैसे निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है। 400 से अधिक मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन करना बहुत बड़ा काम है जिसे अकेले एमसीआई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि 21 वीं सदी की मेडिकल शिक्षा के सामने आने वाली चुनौती वास्तव में बहुत बड़ी है और इसका समाधान ठोस और अपारदर्शी तरीके से नहीं किया जा सकता है

एमसीआई की तरह निकाय। परिवर्तन तभी होगा जब हम व्यवस्था के अंतर्भाग को बदलेंगे। (पैरा 13.4)

परिवर्तनकारी प्रकृति के गेम चेंजर सुधार इसलिए समय की आवश्यकता हैं और उन्हें तत्काल और तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि, यदि विनियामक संरचना के सुधार में राजनीतिक औचित्य सहित किसी भी आधार पर और देरी होती है,

बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि बाद में दिशा बदलने के प्रयासों की भरपाई करने के लिए बहुत अधिक गति बनाई गई होगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली एक अथाह गड्ढे में गिर जाएगी और देश को महान सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।

लागतें। (पैरा 13.5)

स्वास्थ्य प्रणाली। इसलिए सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान बुराइयों को दूर करने और चिकित्सा शिक्षा को समकालीन वैश्विक शिक्षाशास्त्र और प्रथाओं तक बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी सुधार के लिए नेतृत्व करते हुए सभी भारतीयों के स्वास्थ्य को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता।

प्रासंगिकता। (पैरा 13.6)

(दिवंगत) प्रो. के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति। सरकार द्वारा जुलाई, 2014 में सुधारों का सुझाव देने के लिए रानित रॉय चौधरी का गठन किया गया था।

चिकित्सा पेशे के नियामक ढांचे ने फरवरी, 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी एक प्रति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को प्रदान की गई है

यह संसदीय समिति। विशेषज्ञ समिति ने नियामक निकाय के लोकाचार में बड़े बदलाव और इसके कार्यों के प्रमुख संरचनात्मक पुनर्गठन की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति ने कुछ अधिनियमों के माध्यम से एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) के गठन का सुझाव दिया है। एन. एम. सी. में चार कार्यक्षेत्र होंगे (i) यू. जी. चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, (iii) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड और (iv) राष्ट्रीय चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। इन ऊर्ध्वाधर प्रमुखों के अलावा, विशेषज्ञ समिति ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन की भी सिफारिश की है जिसमें राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य चिकित्सा परिषदों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और एन. एम. सी. के सदस्य शामिल होंगे। समिति को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्माण और (परिशिष्ट में) परिकल्पित संरचना को प्रख्यात चिकित्सा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यक्तियों के एक समूह द्वारा अनुमोदित किया गया है। (पैरा 13.7)

समिति ने सुझाए गए नए नियामक ढांचे का कठोर विश्लेषण किया है और पाया है कि इसके कई मुद्दों को विनियमन के सुझाए गए नए मॉडल में संबोधित किया गया है।

इस समिति द्वारा इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। (पैरा 13.8) संक्षेप में, समिति का मानना है कि दोहराव के जोखिम पर भी, देश में चिकित्सा पेशे के नियामक निरीक्षण में बड़े संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता इतनी जरूरी है कि इसे अब और स्थगित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, समिति इस बात से अवगत है कि नियामक में बदलाव करने का कोई भी प्रयास

ढांचे को गहराई से निहित निहित स्वार्थों से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो पूरी कवायद को पटरी से उतारने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाना है, तो सरकार अब दूसरा रास्ता नहीं देख सकती है और उसे अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना होगा और भारत की चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार की नियामक प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार के लिए निर्णायक और अनुकरणीय कार्रवाई करनी होगी।

समिति, आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य [ए. के. सिकरी, जे.]

इसलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रोत्साहित करता है कि

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करें।

तुरंत और संसद में एक नया व्यापक विधेयक लाएं।

इस उद्देश्य के लिए जल्द से जल्द। (पैरा 13.9) "सीओ

101. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित पर अभी तक सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है, हम इसकी सामग्री पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि

इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करें और आगे उचित कार्रवाई करें।

102. साथ ही, हम महसूस करते हैं कि विचाराधीन है

एमसीआई और अन्य सभी के कामकाज की निगरानी के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त कार्यपालिका या विधायिका स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन करने की आवश्यकता है।

संसदीय समिति द्वारा विचार किए गए मामले।

103. उपरोक्त को देखते हुए, जबकि हम इसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और इन अपीलों को खारिज करते हुए, हम एक निगरानी समिति के गठन का निर्देश देते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

सदस्य:

1 .

न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा

(भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)

2 .

प्रो. (डॉ.) शिव सरीन

(निदेशक, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान)

3 .

श्री विनोद राय

(के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

भारत)

104. उक्त समिति के गठन के संबंध में अधिसूचना

आज से दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाए। समिति को सब कुछ दिया जाए

कार्य करने की सुविधाएँ। समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक उनके परामर्श से तय किया जा सकता है।

105. उक्त समिति के पास सभी की देखरेख करने का अधिकार होगा।

एमसीआई अधिनियम के तहत वैधानिक कार्य। एम. सी. आई. के सभी नीतिगत निर्णय

निरीक्षण समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। समिति उचित उपचारात्मक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह समिति करेगी

जब तक केंद्र सरकार कोई अन्य उपयुक्त कार्य नहीं करती

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर उचित विचार करने के बाद तंत्र।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

प्रारंभ में समिति एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी, जब तक कि उपयुक्त तंत्र पहले नहीं लाया जाता है जो उक्त समिति का स्थान लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि उक्त अवधि के भीतर केंद्र सरकार एक उपयुक्त तंत्र के साथ आएगी।

106. एक साल के बाद मामले को ऐसे आगे के निर्देशों के लिए सूचीबद्ध करें जो आवश्यक हो सकते हैं।

आर. भानुमति, जे. 1. मुझे गुजरने का फायदा मिला है

मेरे सम्मानित भाई माननीय न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी द्वारा प्रस्तावित मसौदा निर्णय। तर्क की एक उल्लेखनीय प्रक्रिया के आधार पर मेरे विद्वान भाई ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं अपने स्वयं के कुछ तर्क जोड़ना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि निर्णय के लिए और विस्तार की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं।

2.टी. एम. ए. पाई में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में

फाउंडेशन और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी. 481, इस्लामी शिक्षा अकादमी और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओआरएस। (2003) 6 एस. सी. सी. 697 और पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 6 एस. सी. सी. 537, मध्य प्रदेश राज्य ने एम. पी. निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का) को लागू किया है।

विनियम अवाम शुल्क का निर्देशन) अधिनियम, 2007 (2007 का एम. पी. अधिनियम No.21)। मध्य प्रदेश राज्य के निजी दंत चिकित्सा और चिकित्सा महाविद्यालयों के संघ ने 2008 की रिट याचिका दायर की है जिसमें अधिनियम 2007 के प्रावधानों को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है। अधिकार क्षेत्र। 2008 के डब्ल्यू. पी. No.9496 में, एसोसिएशन ने अधिनियम 2007 के तहत बनाए गए प्रवेश नियम 2008 को भी चुनौती दी है क्योंकि

संविधान और एम. पी. अधिनियम 2007। राज्य सरकार ने 28.02.2009 पर आदेश जारी किए कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (VYAPAM) के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET) आयोजित करेगी। एसोसिएशन ने स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वी. वाय. ए. पी. ए. एम. को सी. ई. टी. आयोजित करने के लिए अधिकृत करने वाले दिनांक 1 के आदेश को मनमाना और टी. एम. ए. पाई में निर्धारित कानून के विपरीत बताते हुए चुनौती दी है।

2009 के डब्ल्यू. पी. No.2764 में फाउंडेशन और पी. ए. इनामदार मामले।

मध्य आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

प्रदेश उच्च न्यायालय ने आम विवादित फैसले द्वारा बरकरार रखा

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की वैधता और सभी को खारिज कर दिया

लेखन याचिकाएँ। 2009 के नियमों के नियम 10 (2) (iii) में कहा गया है कि

उम्मीदवार को राज्य के साथ स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए था मध्य प्रदेश की चिकित्सा परिषद और राज्य चिकित्सा परिषदों से नहीं

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों का

मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी चिकित्सा संस्थान में

" अल्ट्रा वायर्स माना जाता है।

3. तर्क: हालाँकि अभिवचनों और प्रस्तुतियों में, अपीलकर्ताओं ने विभिन्न तर्क उठाए हैं, संक्षेप में, उनकी दलीलों का सार ये हैं:

मध्य प्रदेश अधिनियम 2007 समवर्ती सूची में प्रविष्टि 25 के लिए संदर्भित नहीं है और प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा संघ सूची की प्रविष्टि 66 के भीतर आने वाली उच्च शिक्षा के मानकों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और राज्य विधानमंडल संघ में शामिल विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं था।

सूची.
टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के पैरा (50) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (ए) छात्रों को प्रवेश देने के अधिकारों के साथ-साथ है। (b) स्थापित करना

एक उचित शुल्क संरचना; और (ग) एक शासी निकाय का गठन करना; जबकि एम. पी. की धारा 3 (घ) और धारा 6।
अधिनियम 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर इस तरह से होगा जैसा कि राज्य द्वारा निर्धारित किया जाए, गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकार और संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में और वही एक अनुचित प्रतिबंध होगा जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडा में आयोजित किया गया था।
यह मामला।

अधिनियम 2007 की धारा 4 (1) के साथ पठित धारा 9 सशक्तीकरण

प्रभारित की जाने वाली शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए समिति

गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उल्लंघन किया जाता है

उन संस्थानों की स्वायत्तता जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के संदर्भ में अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने का अधिकार है। धारा 4 और विनियमन 5

के संदर्भ में समिति को शुल्क [2016] 3 एस. सी. आर. निर्धारित करने के लिए बेलगाम शक्ति दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो संस्थान द्वारा प्रभारित किया जा सकता है और समिति विभिन्न शीर्षों में निर्धारित राशियों की जांच कर सकती है जो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में निर्धारित गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार के अनुसार नहीं है।

गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम 2007 की धारा 8 के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
संवैधानिक योजना और यह एक अनुचित विघटन होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करेगा और इस तरह के अनुचित प्रतिबंध प्रभावी रूप से उल्लंघन करते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1)।

4. अनुभाग के लिए चुनौती और आरक्षण प्रदान करना: धारा 8

अधिनियम 2007 के तहत निजी संस्थानों में प्रवेश में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

संबंधित व्यक्तियों के लिए गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह आरक्षण अनुसरणीय है।

अनुच्छेद सम्मिलित करते हुए नब्बेवें संविधान संशोधन का विरोध। 15 (5)

संविधान से। आक्षेपित निर्णय के पैरा (41) में, यह ओ. बी. है

यह सेवा प्रदान की कि अनुच्छेद 15 (5) को सम्मिलित करते हुए नब्बेवां संविधान संशोधन

संविधान को कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है

अलग-अलग रिट याचिकाएँ और इसलिए इसमें कोई तर्क नहीं दिया गया था
अधिनियम 2007 के विचारों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ। इसलिए ऐसा नहीं है।

अधिनियम 2007 की धारा 8 की शक्तियों में जाना आवश्यक है।

5. पुनः विवादः राज्य की विधायी क्षमता का अभाव। अधिनियम 2007 के रूप में क्षेत्र संघ सूची की प्रविष्टि 66 द्वारा कब्जा कर लिया गया हैः यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधायी क्षमता का मुद्दा न तो था

उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया और न ही तर्क दिया गया, जैसा कि इसकी कमी से स्पष्ट है

विवादित में संवैधानिक महत्व के इस मुद्दे पर चर्चा

निर्णय। चाहे जो भी हो, दलीलों की सराहना करने के लिए, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की एक झलक पाना फायदेमंद होगा।

केंद्र और राज्यों के बीच विधायी क्षेत्रों के वितरण पर।

केंद्र और राज्य सरकारों की विधायी शक्तियाँ हैं - सातवीं में दी गई तीन सूचियों में प्रासंगिक प्रविष्टियों द्वारा शासित

अनुसूची. संघ सूची में प्रविष्टि 66 में समन्वय और समन्वय का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का निर्धारण या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान। संविधान से पहले

42 वां संशोधन, "शिक्षा जिसमें विश्वविद्यालय विषय आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।

वी.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

संघ सूची की प्रविष्टियों 63,64,65,66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों को राज्य सूची की प्रविष्टि 11 में दिखाया गया था। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा 03.01.1977 से प्रभावी, प्रविष्टि 11 को राज्य सूची से हटा दिया गया था और

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के साथ समामेलित।,

सूची I-संघ सूची की प्रविष्टि 66 निम्नानुसार हैः

प्रविष्टि 66. समन्वय और मानकों का निर्धारण

उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों में और

वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान।

सूची III-समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 इस प्रकार है:

प्रविष्टि 25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की 63,64,65 और 66 प्रविष्टियों के प्रावधानों के अधीन; व्यावसायिक और तकनीकी

श्रम प्रशिक्षण।

संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत, भारत सरकार को उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और रखरखाव करना आवश्यक है। भारत संघ को उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है और ये राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होंगे। की प्रविष्टि 25

समवर्ती सूची सूची 1 की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन है और राज्य की केंद्रीय अधिनियम के विपरीत नीति नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद 257 (1) के तहत, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि राज्य सरकार के कार्य में बाधा या पूर्वाग्रह न आए।

संघ की कार्यकारी शक्ति।

6. जबकि 'शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिसकी 25 वीं प्रविष्टि है।

संविधान द्वारा प्रतिस्थापित समवर्ती सूची (बयालीसवां संशोधन)। अधिनियम 1976, संघ सूची की प्रविष्टियाँ 65 और 66 संघ को शक्ति देती हैं -

यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान आदि के मानकों को किसी विशेष राज्य या राज्य के हाथों राष्ट्रीय प्रगति को नुकसान पहुँचाने के लिए कम न किया जाए और राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि वर्तमान प्रविष्टि के तहत संघ की शक्ति का सीधे अतिक्रमण न हो। हालाँकि संसद और राज्यों के लिए उपलब्ध विधान का क्षेत्र निश्चित रहा है जैसा कि कहा गया है। ऊपर, अधिक बार, अतिव्यापी की एक निश्चित मात्रा अपरिहार्य हो सकती है; जो कानून इस प्रकार अतिव्यापी होगा

} .

[2016] 3 एस सी आर।

एसयूपीके 'मी कोर्ट रिपोर्ट

वह उस विषय पर है जो उस विधानमंडल के पक्ष में आरक्षित है। सक्षम करने के लिए
हमारे संविधान के संघीय ढांचे का सुचारू रूप से काम करना, "आकस्मिक"

किसी एक क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र का 'अतिक्रमण' या 'अतिव्यापी' होना

अन्य सूचियों में प्रविष्टियों की अनुमति तब तक है जब तक कि यह उल्लंघन नहीं करती है

कानून बनाने वाली विधायिका के लिए निर्धारित कानून की सीमा,

'पीठ और पदार्थ' के सिद्धांत द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा।

7. डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्र। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य।

(1999) 7 एस. सी. सी. 120, यह माना गया कि प्रविष्टि 25 के तहत "शिक्षा" शब्द

अनुसूची VII की सूची III का व्यापक महत्व है। यह अपने तह में शामिल होगा

पढ़ाया जाता है, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण भी है

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाना आवश्यक है

चिकित्सा शिक्षा। पाठ्यक्रम में 'शिक्षा' शब्द भी शामिल है।

8. 'शिक्षा' की अवधारणा का उल्लेख करने के बाद विस्तार से बताते हुए

पी. ए. इनामदार मामले में शब्दकोश का अर्थ और इंडिया विजन-2020,

पैरा (88) से (90) में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

आई.

" 88 , शिक्षा इस प्रकार है:

" ..... व्यक्तित्व का निरंतर विकास, व्यक्तित्व का निरंतर विकास

चरित्र, और जीवन में गुणात्मक सुधार: एक प्रशिक्षित

मन में हर व्यक्ति से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करने की क्षमता होती है।

अनुभव हो, चाहे वह हार हो या जीत, दुख हो या आनंद। शिक्षा है।

मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना और मस्तिष्क को नहीं भरना ",

(एक बदलते समाज के लिए शाश्वत मूल्य, खंड देखें। III
भारतीय विद्या द्वारा प्रकाशित मानव उत्कृष्टता के लिए शिक्षा

भवन, बॉम्बे, पी। 19.)

" हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, ताकत मिले।

कोई अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ..... सभी शिक्षाओं का अंत,
सभी प्रशिक्षण मानव-निर्माण होना चाहिए। सभी का अंत और उद्देश्य

प्रशिक्षण मनुष्य को विकसित करने के लिए है। प्रशिक्षण जिसके द्वारा

वर्तमान और इच्छा की अभिव्यक्ति को नियंत्रण में लाया जाता है और

फलदायी बनना शिक्षा कहलाता है।

(स्वामी विवेकानंद के रूप में ओडरन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

उद्धृत आई. बी. आई. डी. , पी पर। 20.)

89. शिक्षा, एक उपयोगी गतिविधि के रूप में स्वीकार की गई, चाहे वह दान के लिए हो

या लाभ के लिए, एक व्यवसाय है। फिर भी यह रुकता नहीं है

समाज की सेवा करें। और भले ही यह एक पेशा है, यह नहीं कर सकता है

इसे किसी व्यापार या व्यवसाय के बराबर माना जाए।

90. संक्षेप में, शिक्षा राष्ट्रीय संपत्ति है जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

प्रगति और समृद्धि "।

9. संघ सूची समन्वय की प्रविष्टि 66 के आधार पर और

उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का निर्धारण या

आर्क, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान "संघ के लिए आरक्षित हैं।

दिया। समन्वय करने की शक्ति केवल मूल्यांकन करने की शक्ति नहीं है, बल्कि

ठोस कार्रवाई के लिए गैर या सुरक्षित संबंध।

ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश (7 म संस्करण) 'को-ऑर्डिनेट' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

" समन्वय करें; (भागों, आंदोलनों आदि) को उचित संबंध में लाना, एक साथ या उचित रूप से कार्य करने का कारण बनना।

आदेश "।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10 वीं संस्करण) निर्धारित 'को इस प्रकार परिभाषित करती है:

" परिभाषित सीमाएँ होना; निश्चित; निश्चित और दृढ़ संकल्प * को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "आधिकारिक रूप से कुछ तय करने का कार्य;
विशेष रूप से।, अदालत या प्रशासनिक एजेंसी द्वारा अंतिम निर्णय।

इन परिभाषाओं से यह पता चलता है कि 'निर्धारण' एक अभिव्यक्ति का आधिकारिक लक्षण वर्णन है और 'समन्वय' का अर्थ है जिसके माध्यम से निर्धारित मानदंडों या मानकों को सामंजस्य में रखा जाता है

एक-दूसरे के साथ।

10. संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में (दसवां संस्करण, संशोधित)

मानक शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है:

" गुणवत्ता या प्राप्ति का एक स्तर, एक आवश्यक या सहमत

गुणवत्ता या प्राप्ति का स्तर (प्राथमिक विद्यालयों में) परीक्षा द्वारा परखी जाने वाली प्रवीणता का एक स्तर, जो तुलनात्मक मूल्यांकन में एक माप, मानक या मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

ब्लैक का कानून शब्दकोश (10 वीं संस्करण) 'मानक' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

" प्रथा, सहमति या प्राधिकरण द्वारा सही के रूप में स्वीकार किया गया एक मॉडल; स्वीकार्यता, गुणवत्ता को मापने के लिए एक मानदंड

13

या सटीकता।

रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन तृतीय संस्करण। मानक को भी परिभाषित करता है

के रूप में:

" कुछ ऐसा जो प्राधिकरण, रीति-रिवाजों या सामान्य सहमति द्वारा एक मॉडल या उदाहरण के रूप में स्थापित किया जाता है जिसका पालन किया जाना है
[एस. 18 (4), एक्सप्लन, बीड़ी और सिगार श्रमिकों (की शर्तें)

रोजगार) अधिनियम (1966 का 32)]

बार-बार और निरंतर आवेदन के लिए एक मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा अनुमोदित और निर्धारित विनिर्देश। मानक आमतौर पर एक बुनियादी निर्धारित करता है, हालांकि औसत से अधिक
गुणवत्ता का स्तर "।

11. प्रविष्टि 66, संघ सूची का विधायी इतिहास इस संबंध में एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है। लाभप्रद रूप से, हम इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं

' भारतीय परिप्रेक्षय में कानून के एक विषय के रूप में 'शिक्षा' का निर्धारण किया जाना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने सातवीं अनुसूची में विधायी सूचियों को निर्धारित किया। सूची 2 की प्रविष्टि 17, अर्थात प्रांतीय राज्य सूची निम्नानुसार है:

" सूची I के पैराग्राफ 13 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा

सूची I का पैराग्राफ 13 यानी संघीय विधायी सूची इस प्रकार है:

" बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम

विश्वविद्यालय "।

स्पष्ट रूप से, विश्वविद्यालयों सहित कानून के क्षेत्र के रूप में "शिक्षा"

यह दो विश्वविद्यालयों अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रांतों के लिए उपलब्ध था, जो संघीय विधायी क्षमता के क्षेत्र में थे। यहां तक कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब भी शिक्षा को राज्य का विषय बनाने और संघ की भूमिका को केवल समन्वित शैक्षणिक संस्थान तक सीमित रखने का विचार था

हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में दृढ़।

बहुत

1 आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र V

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

12. यदि हम संविधान सभा की बहसों के खंड IX का उल्लेख करते हैं

बुधवार, 31 अगस्त 1949 को आयोजित, यह स्पष्ट करता है कि जबकि

सूची I की प्रविष्टि 66 (जैसा कि यह अपने वर्तमान रूप में है) का परिचय देते हुए डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर ने संघ को स्थापित करने के लिए सशक्त बनाने के अलावा और कुछ नहीं प्रस्तावित किया

केवल उच्च शिक्षा के लिए मानक और दोनों के बीच समन्वय

संस्थाएं। बहस के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं आगे बढ़ता हूँ:

“ कि सूची I की प्रविष्टि 57 के बाद, निम्नलिखित नई प्रविष्टि होगी

सम्मिलित किया गया:

'57 (ए) में मानकों का समन्वय और रखरखाव

उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी के लिए संस्थान

अनुसंधान के लिए संस्थान और संस्थान "।

यह प्रविष्टि केवल पिछली प्रविष्टि संख्या 57 का पूरक है। में।

प्रांतों द्वारा बनाए गए संस्थानों से निपटने के लिए, प्रविष्टि 57 ए का प्रस्ताव है

समन्वय की सीमित सीमा तक केंद्र को शक्ति देना शोध संस्थान और उन संस्थानों में मानकों को बनाए रखना

उन्हें नीचे आने से रोकने के लिए।

13. श्रीमान, मैं भी कहता हूँ:

" कि सूची 1 की प्रस्तावित नई प्रविष्टि 57 ए में सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में 'रखरखाव' शब्द के लिए

'निर्धारण प्रतिस्थापित किया जाए' शब्द।

डॉ. अम्बेडकर के उक्त प्रस्ताव का श्री वी. एस. ने विरोध किया।

सर्वते (मध्य भारत)। यह सुझाव देकर कि केवल "द्वारा पदोन्नति"

संस्थानों में मानकों की वित्तीय सहायता या अन्यथा

उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान और अनुसंधान के लिए संस्थानों को संघ के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, ताकि

कानून बनाने की राज्य की शक्ति में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। शिक्षा से संबंध '। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए '

राज्य का विषय होने के कारण, श्री वी. एस. सर्वते ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

व्यक्ति को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है, निश्चित रूप से
अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व के साथ लगातार। अगर यह

क्या शिक्षा में इच्छा है, तो इसका पूरा दायरा होना चाहिए

विविधता के लिए। शिक्षा में कोई एकरूपता नहीं होनी चाहिए

क्योंकि एकरूपता व्यक्ति के विकास को मार देगी। कोई नहीं।

कह सकते हैं कि बौद्धिक भार का एक मानक होना चाहिए

और मनुष्यों के लिए उपाय। इसलिए मुझे लगता है कि

शिक्षा पूरी तरह से प्रांतों पर छोड़ दी जानी चाहिए। ”

श्री वी. एस. सर्वते ने सूची की प्रविष्टि 66 को लागू करने का विरोध किया

I (वर्तमान रूप में) यह देखते हुए कि संघ नहीं होगा तकनीकी शिक्षा के लिए मानक
निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सक्षम

चिकित्सा शिक्षा के रूप में। उनका अवलोकन नीचे उद्धृत किया गया है:

मानकों को तय करने के लिए संसद या केंद्र सरकार
उच्च शिक्षा, उदाहरण के लिए उच्च चिकित्सा शिक्षा में।

क्या संसद के लिए यह पता लगाना संभव होगा कि क्या हैं?

चिकित्सा शिक्षा के लिए मानक?

अन्य संविधान निर्माताओं की चिंताओं का जवाब देने के लिए,

डॉ. अम्बेडकर ने सूची I की प्रविष्टि 66 के सीमित दायरे को स्पष्ट किया।

;

(जैसा कि वर्तमान रूप में), जैसा कि उनके द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तावित किया गया
है:

" प्रविष्टि 57 ए केवल कुछ के रखरखाव से संबंधित है।
संस्थानों के कुछ वर्गों, अर्थात् संस्थानों में मानक

उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रदान करना

उम्मीदवार को किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अब, मान लीजिए मद्रास विश्वविद्यालय का कहना है कि बी. ए. में एक उम्मीदवार।

परीक्षा, यदि उसने कुल अंकों का 15 प्रतिशत प्राप्त किया हो

यह माना जाएगा कि उसने वह परीक्षा उत्तीर्ण की है, और मान लीजिए कि

बिहार विश्वविद्यालय का कहना है कि एक उम्मीदवार जिसने प्राप्त किया है

20 प्रतिशत। अंकों को उत्तीर्ण माना जाएगा
बी. ए. डिग्री परीक्षा; और कुछ अन्य विश्वविद्यालय कुछ ठीक करते हैं

अन्य मानक, तो यह काफी अराजक स्थिति होगी,
और अभिव्यक्ति जो आमतौर पर उपयोग की जाती है, कि उम्मीदवार

मुझे लगता है कि स्नातक होना अर्थहीन होगा। इसी तरह,

कुछ शोध संस्थान हैं, जिनके परिणामों पर
केंद्र और प्रांतीय सरकारों की इतनी सारी गतिविधियाँ

निर्भर करता है। जाहिर है कि आप इनके परिणामों की अनुमति नहीं दे सकते।

मानक और फिर भी उन्हें केंद्रीय उद्देश्यों के लिए, अखिल भारतीय उद्देश्यों के लिए या इसके उद्देश्यों के लिए मान्यता देने की अनुमति दें
राज्य "।

14. प्रविष्टि की शुरुआत करते समय हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा

66 इस प्रकार संघ सूची केवल संघ को पूरे देश में उच्च शिक्षा का एक समान मानक निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने तक सीमित थी। और राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की अपनी पूरी शक्ति से वंचित नहीं करना।

शिक्षा से संबंध 'और अपने स्वयं के सामान्य प्रवेश द्वार का आयोजन जाँच।.

15. यदि हम संघ की वर्तमान प्रविष्टि 66 के दायरे पर विचार करें

राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करें ताकि वे इस क्षेत्र में काम कर सकें - निर्धारित मानकों के अनुसार संबंधित राज्यों में उच्च शिक्षा

संघ सूची की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधान; जबकि राज्य है तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा पर कानून बनाने में सक्षम,

चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय, यह निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए संघ द्वारा।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. शब्द 'समन्वय' और 'का निर्धारण

उच्च शिक्षा में मानक संसद का संरक्षण है और

विशेष रूप से संघ सूची की प्रविष्टि 66 द्वारा शामिल हैं। शब्द 'को' समन्वय 'का अर्थ है एक समान प्रतिरूप बनाने की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना।

समन्वित कार्रवाई के लिए। 'संस्थानों के मानकों का निर्धारण' शब्द

उच्च शिक्षा का उद्देश्य समन्वय स्थापित करना है। देश भर में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थान। देख रहे हैं।

संघ और संघ के बीच विधायी शक्तियों का वर्तमान वितरण

शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में राज्य, उस राज्य की शक्ति

तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा के संबंध में विधान,

चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय "संघ के समान हैं।

तथापि, ऐसी शक्ति संघ की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के अधीन है।

सूची, जैसा कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में दिया गया है। यह है जिम्मेदारी

उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार

और इसे किसी विशेष राज्य के हाथों कम नहीं किया जाना चाहिए।

17. यहाँ तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी मान्यता दी कि संघ मानकों को निर्धारित करने की बड़ी जिम्मेदारी लेगा। नीति 1986 में कहा गया है:

" 3.13 ..... जबकि इस संबंध में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रहेगा, संघ सरकार सुदृढ़ीकरण के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखें (जिनमें शामिल हैं) सभी स्तरों पर शिक्षण पेशा), अध्ययन और निगरानी करने के लिए पूरे देश की शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में विकास के लिए मानव शक्ति, अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्नत अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल के लिए पूरे देश में शैक्षिक पिरामिड। समरूपता एक साझेदारी को दर्शाता है, जो एक ही समय में सार्थक है और चुनौतीपूर्ण; राष्ट्रीय नीति इस दिशा में उन्मुख होगी इसे अक्षर और आत्मा में प्रभाव देना।

एफ.

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

5.30 राज्य स्तर की योजना और उच्च अधिकारियों का समन्वय उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यू. जी. सी. और ये परिषदें समन्वयात्मक विकास करेंगी।

मानकों पर नजर रखने के तरीके।

XXX

10.4 राज्य सरकार राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित कर सकती है

सी. ए. बी. ई. की तर्ज पर शिक्षा। प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

विभिन्न राज्यों में तंत्रों को एकीकृत करने के लिए लिया जाए
मानव संसाधन विकास से संबंधित विभाग।

10.5 प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

शैक्षिक योजनाकार, प्रशासक और संस्थानों के प्रमुख।

इस उद्देश्य के लिए संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए।

चरणों में "। (एमएचआरडी। गव. इन/साइट/अपलोड _ फाइल/एम. एच. आर.
डी./फाइल /
दस्तावेज़/एन. पी. ई. 86-मॉड 92 अपलोड करें। पी. डी. एफ.)

नीति ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि राज्य इसे पूरा करना जारी रखेगा।

अपनी जिम्मेदारियाँ। यह प्रविष्टि में संशोधन से भी स्पष्ट है।

25 समवर्ती सूची। अगर इरादा उच्च शिक्षा को बनाए रखने का होता

केवल संघ के हाथों में, केवल राज्य से प्रवेश 11 को छोड़ना

सूची पर्याप्त होगी। विधायी इरादा संघ को अनुमति देना था

अपने अंगों के माध्यम से मानकों को निर्धारित करना, जिसे राज्य सुगम बनाएँगे।

18. इस प्रकार, जो उभरता है वह यह है कि सूची I के तहत,

संघ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों के निर्माण और समन्वय के संबंध में है। उच्च शिक्षा में मानक के निर्धारण का तात्पर्य है कि संसद को ऐसा निर्धारित करने का अधिकार है

उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानदंड। 'उच्च शिक्षा में मानकों का समन्वय और निर्धारण' अभिव्यक्ति का अर्थ है कि मानकों को बनाए रखने के लिए ठोस कार्रवाई करना संसद का काम है। प्रविष्टि 66 के साथ केंद्रीय विधानमंडल को सशक्त बनाने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि उच्च शिक्षा के मानकों को किसी विशेष राज्य के हाथों

राष्ट्रीय प्रगति के नुकसान के लिए कम नहीं किया गया था और यह कि राज्य द्वारा प्रयोग की गई शक्ति सीधे संघ प्रविष्टि 66 की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करती थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. अर्थ की व्याख्या, "समन्वय" जैसा कि सूची I की प्रविष्टि 66 में दिखाई देता है, शाह जे. द्वारा चर्चा में निहित है, जबकि

गुजरात विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. में बहुमत के विचार व्यक्त करते हुए। वी. श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य। [1963] सप. 1 एससीआर 112। इस मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या राज्य विधानमंडल विश्वविद्यालय और घटक कॉलेजों से संबद्ध संस्थानों में गुजराती और/या देवनागरी लिपि में हिंदी को शिक्षा और परीक्षा के विशेष माध्यम के रूप में लागू कर सकता है। यह माना गया था कि:

" यदि किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को शिक्षा के अनन्य माध्यम के रूप में लागू करने वाले कानून के परिणामस्वरूप मानकों में कमी आने की संभावना है, तो यह अनिवार्य रूप से सूची I की मद 66 के भीतर आना चाहिए और

उस सीमा तक सूची 11 की मद 11 से बाहर रखा गया है।

शिक्षा के माध्यम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता था

निर्देश की प्रभावशीलता और इसके द्वारा प्राप्त परिणामी मानक। यह आगे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" यदि पर्याप्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं या माध्यम में सक्षम प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिनके माध्यम से निर्देश दिया जाता है, या छात्र उस माध्यम से निर्देश प्राप्त करने या आत्मसात करने में सक्षम नहीं हैं, जिसमें इसे दिया जाता है, तो मानकों को अनिवार्य रूप से गिरना चाहिए, और ऐसे मामलों में मानकों के समन्वय के लिए कानून में माध्यम से संबंधित कानून शामिल होंगे।

निर्देश देते हैं।

यदि किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में शिक्षा के एक विशेष माध्यम को लागू करने से संबंधित कानून; पाठ्यपुस्तकों और पत्रिकाओं की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सक्षम शिक्षक और

विषयों को समझने में छात्रों की असमर्थता के परिणामस्वरूप मानकों के कम होने की संभावना है, यह कानून, हमारे विचार में, अनिवार्य रूप से सूची I की मद 66 के भीतर आएगा और यह होगा -

के आयाम से उस हद तक बहिष्कृत माना जाता है

सूची II की मद 11 द्वारा प्रदत्त शक्ति।

20. गुजरात विश्वविद्यालय के मामले में न्यायाधीश सुब्बा राव ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि कोई भी प्राधिकरण इस हद तक नहीं गया है कि यह माना जा सके कि भले ही किसी अधिनियम का सार और सार किसी विशेष अधिनियम के दायरे में आता हो।

प्रविष्टि, इसे अटकलबाजी और अग्रिम आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए

कि यह एक समन्वित द्वारा बनाए गए कानून के साथ टकराव में आ सकता है एक अन्य प्रविष्टि के आधार पर विधायिका; यदि एक आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र पर राज्य के कानून का प्रभाव।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

केंद्रीय विधान इतना भारी और विनाशकारी था कि इसका सफाया कर दिया गया या केंद्रीय क्षेत्र को काफी कम करें, तो यह पकड़ने के लिए एक मैदान हो सकता है।

कि राज्य का कानून शक्ति का एक रंगीन प्रयोग था और

सार यह राज्य प्रविष्टि के तहत नहीं, बल्कि संघ प्रविष्टि के तहत आता है।

21. आर. चित्रलेखा और अन्र में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। (1964) 6

एस. सी. आर. 368, राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक को सूचित किया

कि इसके लिए अधिकतम अंक का 25 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया गया था वैकल्पिक विषयों में परीक्षा साक्षात्कार के अंकों के रूप में और उस आधार पर,

इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन किया गया था। इस तरह के मानकों के लिए राज्य के कानून के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह था

अभिनिर्धारित किया कि राज्य कानून के लिए अंकों का एक उच्च प्रतिशत निर्धारित करता है

महाविद्यालयों में प्रवेश के मामले में पाठ्येतर गतिविधियाँ नहीं की जा सकती हैं।

संघ सूची की प्रविष्टि 66 द्वारा कवर किए गए क्षेत्र पर अतिक्रमण कहा जाएगा और यह कि राज्य सरकार निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर होगी

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यताएँ जब तक कि इसकी कार्रवाई नहीं होती है

किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है।

22. यह आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में देखा गया था।

संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए इस तरह का 'संयुक्त खेल' भी वांछनीय है। हमारे संविधान का "।

23. टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य में। वी. अधियामन शैक्षिक और

अनुसंधान संस्थान और अन्य। , (1995) 4 एस. सी. सी. 104, प्रश्न शामिल क्या केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद, अखिल भारतीय परिषद

तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987, राज्य सरकार के पास था

शैक्षणिक संस्थान शुरू करने की अनुमति दें और वापस लें। यह था।

अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद उस हद तक

संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत मानकों का समन्वय और निर्धारण करना।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में तकनीकी संस्थानों के प्रावधान;

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा को [2016] 3 एस. सी. आर. में अप्रवर्तनीय माना जाएगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों के लिए। पैरा (41) में, यह

सिद्धांतों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

" 41. उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह इस प्रकार है: (i) संघ की प्रविष्टि 66 में प्रयुक्त 'समन्वय' अभिव्यक्ति

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची केवल

औसत मूल्यांकन। इसका अर्थ है एक जाली बनाने की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना।

एक निश्चित डिजाइन के अनुसार एक ठोस कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न,

विकास की योजना या योजना। अत: इसमें कार्रवाई शामिल नहीं है केवल मानकों में असमानताओं को दूर करने के लिए बल्कि रोकने के लिए भी

इस तरह की असमानताओं की घटना। इसमें यह भी शामिल होगा कि

उन सभी चीजों को करने की शक्ति जो रोकने के लिए आवश्यक हैं

'समन्वय' को असंभव या कठिन बना दें। यह शक्ति है

पूर्ण और बिना शर्त और किसी भी वैध के अभाव में

सम्मोहक कारणों से, इसका पूरा प्रभाव इसके अनुसार दिया जाना चाहिए

स्पष्ट और स्पष्ट इरादा।

((ii) इस हद तक कि राज्य का विधान इसके साथ टकराव में है -

केंद्रीय कानून हालांकि पूर्व कथित रूप से किया गया है समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत बनाया गया लेकिन प्रभावी रूप से

बनाए गए अधीनस्थ विधान सहित विधानों पर अतिक्रमण

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र द्वारा या देना संघ सूची की प्रविष्टि 66 के प्रभाव से, यह अमान्य होगा और

निष्क्रिय।

(iii) यदि दोनों विधानों के बीच कोई टकराव है, जब तक कि

केंद्रीय कानून, वही निष्क्रिय होगा। ((iv) क्या राज्य का कानून संघ की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण करता है।

प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को सूचीबद्ध करें या उसके प्रतिकूल हैं।

समवर्ती सूची का निर्धारण करना होगा

दोनों कानूनों की जांच और तथ्यों पर निर्भर करेगा हर मामले में।

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

(v) जब उपलब्ध स्थितियों से अधिक आवेदक हों /

सीटें, राज्य प्राधिकरण को उच्च स्थान निर्धारित करने से नहीं रोका जाता है

केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों या योग्यताओं की तुलना में या

आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण। जब राज्य

प्राधिकरण ऐसा करता है, यह संघ की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण नहीं करता है केंद्रीय कानून के प्रतिकूल कानून की सूची बनाएँ या बनाएँ।

(vi) हालांकि, जब स्थितियां/सीटें उपलब्ध हों और राज्य

अधिकारी एक आवेदक को इस आधार पर अस्वीकार करते हैं कि

आवेदक अपने मानकों या योग्यताओं के अनुसार योग्य नहीं है,

जैसा भी मामला हो, हालांकि आवेदक मानकों को पूरा करता है
या केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएँ, वे कार्य करते हैं

उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकता, हालांकि यह मानदंडों को संतुष्ट करती है और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, राज्य अधिकारी अवैध रूप से कार्य करते हैं।

24.डॉ. प्रीति श्रीवास्तव मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया

क्या यह राज्य के लिए विभिन्न प्रवेश मानदंड निर्धारित करने के लिए खुला था,

विभिन्न न्यूनतम योग्यता अंकों को निर्धारित करने के अर्थ में, विशेष के लिए

स्नातकोत्तर चिकित्सा में प्रवेश पाने के इच्छुक श्रेणी के उम्मीदवार

सामान्य की तुलना में आरक्षित सीटों की श्रेणी के तहत पाठ्यक्रम

श्रेणी के उम्मीदवार। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या मानदंडों के लिए प्रवेश का शिक्षा के मानकों के साथ कोई संबंध है,

प्रवेश के नियम जो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आते हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केंद्रीय क़ानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का राज्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। पैरा (35) और (36) में यह

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:

" 35. ..... संघ और राज्यों दोनों के पास शक्ति है

अन्य रूप से, सूची I की प्रविष्टि 66 जो मानकों को निर्धारित करने से संबंधित है उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के लिए संस्थानों में

एस सी आर।

तकनीकी संस्थान और ऐसे मानकों का समन्वय भी। ए.

इसलिए, राज्य को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि इस क्षेत्र पर किसी भी संघ का कब्जा न हो।

कानून। दूसरा, शिक्षा को नियंत्रित करते हुए राज्य ऐसा नहीं कर सकता।

राज्य में, उच्च स्तर के संस्थानों में मानकों का उल्लंघन शिक्षा. क्योंकि यह विशेष रूप से इसके दायरे में है

संघ सरकार। इसलिए, मानदंड निर्धारित करते समय

उच्च शिक्षा सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश

चिकित्सा शिक्षा, राज्य मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है

इस विषय पर मामलों पर विचार करते समय यह भी आवश्यक है कि याद रखें कि 1977 से, शिक्षा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा भी शामिल है,

और विश्वविद्यालय शिक्षा, अब समवर्ती सूची में है ताकि संघ प्रवेश मानदंड पर भी कानून बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो

राज्य इस क्षेत्र में कानून बनाने में सक्षम नहीं होगा, सिवाय इसके कि निम्न में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 254।

शिक्षा के स्तर से कोई संबंध नहीं है, या कि प्रवेश के लिए नियम केवल सूची III की प्रविष्टि 25 में शामिल हैं। मानक

प्रवेश का मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है शिक्षा. बेशक, प्रवेश के लिए ऐसे नियम हो सकते हैं जो हैं -

मानकों के अनुरूप या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते हैं

संघ द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित शिक्षा

सूची I की प्रविष्टि 66. उदाहरण के लिए, एक राज्य में प्रवेश के लिए

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम, इसके अलावा योग्यता निर्धारित करते हैं

सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत निर्धारित लोगों के लिए यह होगा

उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम। लेकिन निर्धारित मानदंडों में कोई कमी के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है

उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा। मानकों

किसी संस्थान या महाविद्यालय में शिक्षा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता; आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उचित
पाठ्यक्रम

(2)

दिए गए समय में शिक्षा;
छात्र-शिक्षक अनुपात;

(3)

छात्रों और अस्पताल के बिस्तरों के बीच का अनुपात

(+)

प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध;

संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों की क्षमता:

(5)

उपकरण और प्रयोगशाला सुविधाएं, या अस्पताल सुविधाओं के लिए

(6)

चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले में प्रशिक्षण;

महाविद्यालय और उससे जुड़े संस्थानों के लिए पर्याप्त आवास

(?)

अस्पताल; और

रीति सहित आयोजित परीक्षाओं का मानक

(8)

जिन कागजातों को सेट किया जाता है और उनकी जांच की जाती है और
नैदानिक

प्रदर्शन का आंकलन किया जाता है।"

25. जैसा कि प्रीति श्रीवास्तव में निर्णय में निर्धारित किया गया है, यह भीतर है
शक्ति के प्रयोग में राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता

उच्च शिक्षा निर्धारित करने के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत एक निश्चित योग्यता के अलावा प्रवेश के लिए योग्यता और उच्च अंक

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उच्च गुणवत्ता लाने के लिए

चिकित्सा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले छात्रों से आउटपुट। उपरोक्त के बाद

इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ (13) और (14) में

विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड अन्र। वी. कृष्णेन्दु हलदर & ओआरएस। , (2011) 4 एस. सी. सी. 606 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया:

" 13. राज्य या विश्वविद्यालय का उद्देश्य पात्रता मानदंड तय करना ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा तय की गई राशि से दोगुना अधिक है। सबसे पहले और

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि भाग लेने वाले उम्मीदवारों की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है

प्रभावी तरीके से प्रवेश के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए राज्य, जब उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदक हों। एक बार

; [2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य और जाँच निकाय की शक्ति, उच्चतर तय करने के लिए योग्यताओं को मान्यता दी जाती है, उनके द्वारा बनाए गए नियम और विनियम

वे सुझाए गए न्यूनतम से अधिक योग्यता निर्धारित करते हैं

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा, बाध्यकारी होगा और संबंधित क्षेत्रों में लागू होगा

राज्य, जब तक कि ए. आई. सी. टी. ई. स्वयं बाद में अपने मानदंडों को संशोधित नहीं करता है

द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे पात्रता मानदंड को बढ़ाना

विश्वविद्यालय और राज्य। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पात्रता

राज्य और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों में वृद्धि हुई

मानक केवल मामूली रूप से, यानी निर्धारित प्रतिशत से 5 प्रतिशत अधिक हैं।

ए. आई. सी. टी. ई. यह नहीं कहा जा सकता है कि द्वारा निर्धारित उच्च मानक राज्य या विश्वविद्यालय असामान्य रूप से उच्च या अप्राप्य हैं

सामान्य छात्र, ताकि नीचे की ओर संशोधन की आवश्यकता हो, जब वहाँ

खाली सीटें हैं। सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया गया कि एआईसीटीई

स्वयं पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है। जो भी हो सकता है।

14. उत्तरदाताओं (कॉलेजों और छात्रों) ने प्रस्तुत किया कि

उस विशेष वर्ष (2007-2008) लगभग 5000 इंजीनियरिंग सीटें

अधूरा रह गया। उन्होंने तर्क दिया कि जब भी बड़ी संख्या में

अनुपलब्धता के कारण सीटें खाली रह गईं

पर्याप्त उम्मीदवार, अधियामन (1995) के पैरा 41 (v) और (vi)

4 एस. सी. सी. 104 खेल में आ जाएगा और स्वचालित रूप से निचला

अकेले ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक लागू होंगे। यह निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विवाद को खारिज किया जा सकता है

प्रीति श्रीवास्तव में संविधान पीठ के फैसले में नीचे

(डॉ.) (1999) 7 एस. सी. सी. 120 और में बड़ी पीठ का निर्णय

एस. वी. ब्राथीप (2004) 4 एस. सी. सी. 513 जो टिप्पणियों की व्याख्या करता है।

अधियामम (1995) 4 एस. सी. सी. 104 में सही परिप्रेक्षय में। हम.

इन निर्णयों से उभरते हुए स्थिति को संक्षेप में नीचे दें:

(i) प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते समय

उच्च शिक्षा के संस्थान, राज्य/विश्वविद्यालय नहीं कर सकते हैं केंद्रीय निकाय द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है /

ए. आई. सी. टी. ई. "मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है" शब्द का अर्थ है -

केंद्रीय निकाय/ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों को कम करना।

डर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

प्रवेश के लिए निर्धारित करके उच्च मानक निर्धारित करना

द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अतिरिक्त या उससे अधिक योग्यताएँ ए. आई. सी. टी. ई., उच्च मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप

और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, के रूप में नहीं माना जाएगा

केंद्रीय निकाय द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना / ए. आई. सी. टी. ई.

(ii) अधियामन (1995) 4 एस. सी. सी. के पैरा 41 (vi) में अवलोकन

104 इस प्रभाव से कि जहां सीटें खाली रहती हैं, राज्य

अधिकारी संतुष्ट करने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक, भले ही वे नहीं हैं। अपने मानकों के अनुसार योग्य होना, अच्छा कानून नहीं है।

(iii) तथ्य यह है कि किसी विशेष वर्ष में रिक्त सीटें हैं,

इसका मतलब यह नहीं है कि उस वर्ष, राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड /

विश्वविद्यालय आवेदन करना बंद कर देगा या न्यूनतम पात्रता

अकेले ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा सुझाए गए मानदंड लागू होंगे। जब तक नहीं

उनके द्वारा निर्धारित, वे इस तथ्य के बावजूद आवेदन करना जारी रखेंगे कि किसी भी वर्ष में रिक्तियां या खाली सीटें होती हैं। मुख्य उद्देश्य

पात्रता मानदंड निर्धारित करने का अर्थ यह सुनिश्चित करना नहीं है कि सभी सीटें

महाविद्यालय भरे हुए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानकों में उत्कृष्टता

उच्च शिक्षा को बनाए रखा जाता है।

(iv) राज्य/विश्वविद्यालय (साथ ही ए. आई. सी. टी. ई.) को समय-समय पर

इस तरह के अंतराल जो वे उचित समझते हैं) पात्रता के प्रिस्क्रिप्शन की समीक्षा करें
प्रवेश के लिए मानदंड, संतुलन में रखना, बनाए रखने की आवश्यकता

राज्य में उपलब्ध सीटों की संख्या और इच्छुक छात्रों की संख्या दूसरी ओर प्रवेश।
यदि आवश्यक हो तो वे पात्रता में संशोधन कर सकते हैं।

मानदंड ताकि शिक्षा में उत्कृष्टता जारी रहे और साथ ही

में अंकों के प्राप्य मानकों के बारे में यथार्थवादी होने का समय

योग्यता परीक्षाएँ "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि राज्य का कानून तय करता है

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता इसके बाहर नहीं है।
राज्य की विधायी क्षमता।

26. अंबेश कुमार (डॉ.) बनाम। प्राचार्य, L.L.R.M. चिकित्सा

महाविद्यालय, मेरठ और अन्य।, (1986) बशर्ते एस. सी. सी. 543, राज्य द्वारा विहित

55 % स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक।

न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या राज्य लागू कर सकता है

चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अलावा भारत और केंद्र सरकार द्वारा
बनाए गए नियम। यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार पात्रता योग्यता निर्धारित करती है, अर्थात्, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में कुछ न्यूनतम अंक प्राप्त करना है

अधिनियम और न ही संघ की शक्ति का कोई उल्लंघन जो संघ की प्रविष्टि 66 में प्रदान किया गया है सूची. यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

उम्मीदवारों द्वारा एमबीबीएस परीक्षा किसी भी तरह से नहीं हुई है। भारतीय चिकित्सा के तहत बनाए गए नियमों का अतिक्रमण

परिषद अधिनियम न ही इसमें प्रदत्त केंद्रीय शक्ति का उल्लंघन करता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66। आदेश केवल एक अतिरिक्त पात्रता योग्यता प्रदान करता है।

27. यह देखते हुए कि सातवें में प्रासंगिक प्रविष्टियों का दायरा

संविधान की अनुसूची को बताए गए तरीके से समझना होगा

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव मामले में, टी. एन. और एन. आर. राज्य में। वी. एस. वी. ब्राथीप

(माइनर) और ओआरएस। (2004) 4 एस. सी. सी. 513, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

9. सूची III की प्रविष्टि 25 और सूची I की प्रविष्टि 66 को पढ़ना होगा। एक साथ और इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक

प्रवेश के मामले में विशिष्टता लेकिन यदि कुछ प्रिस्क्रिप्शन

मानकों को सूची I की प्रविष्टि 66 के अनुसार बनाया गया है, तो

वे मानक राज्य द्वारा निर्धारित मानकों पर हावी होंगे।

सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जहाँ तक वे

भारत संघ द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या इसके अधीन कार्य करने वाला कोई अन्य प्राधिकरण।

इसलिए, क्या होना चाहिए DERN DENTAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

वर्तमान मामले में देखा गया है कि क्या प्रिस्क्रिप्शन

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मानक किसी भी तरह से प्रतिकूल हैं।

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानकों से या उससे कम। इसमें कोई शक नहीं

यह सच है कि ए. आई. सी. टी. ई. ने प्रवेश के दो तरीके निर्धारित किए हैं-एक है

केवल योग्यता परीक्षा और दूसरे पर निर्भर, यह सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर निर्भर करता है।

वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने योग्यता निर्धारित की -

संबंधित विषयों में निश्चित प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

जो योग्यता परीक्षा में न्यूनतम से अधिक है

प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए। यदि उच्च न्यूनतम निर्धारित किया गया है

राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था एआईसीटीई, क्या यह कहा जा सकता है कि यह किसी भी तरह से प्रतिकूल है

इस आधार पर कि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानदंड केवल प्रवेश की अनुमति देंगे। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर,

लागू की गई अतिरिक्त परीक्षा सामान्य प्रवेश परीक्षा है। राज्य सरकार द्वारा। अगर हम मानक लेने के लिए आगे बढ़ते हैं

राज्य सरकार द्वारा योग्यता में न्यूनतम से अधिक कुछ अंक प्राप्त करने का प्रिस्क्रिप्शन सामान्य में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए परीक्षा

प्रवेश परीक्षा सामान्य प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त है। दोनों में

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा प्रस्तावित धाराओं को किसी भी मामले में कम नहीं किया गया है।

तरीके से। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की है वह है

कि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा जो निर्धारित किया गया है वह अक्षम्य है और

केवल न्यूनतम को ध्यान में रखा जाना चाहिए और नहीं

अन्य मानकों को और भी अधिक तय किया जा सकता है जैसा कि इसके द्वारा कहा गया है।

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव मामले (1999) 7 एस. सी. सी. 120 में अदालत, यह नहीं है

निर्धारित उच्च मानकों के कारण सीटें खाली हो सकती हैं। तय किए गए मानक हमेशा यथार्थवादी होने चाहिए जो प्राप्य हों।

और उम्मीदवारों की पहुंच के भीतर हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अलावा

वर्तमान मामले में ए. आई. सी. टी. ई. ऐसे हैं जो प्राप्य नहीं हैं या

जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों की पहुंच में नहीं हैं। यह बहुत अधिक प्रतिशत नहीं है।

न्यूनतम 60 प्रतिशत नीचे की ओर निर्धारित किए गए अंकों की संख्या, लेकिन निश्चित रूप से केवल उत्तीर्ण अंकों से अधिक। उच्चतर में उत्कृष्टता

शिक्षा पर हमेशा इन निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा जोर दिया जाता है।

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव मामला (1999) 7 एस. सी. सी. 120 सहित न्यायालय।

यदि उच्च न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं, तो यह निश्चित रूप से होगा में छात्रों के प्रवेश के मामले में उत्कृष्टता जोड़ें

उच्च शिक्षा।

28. एक और तर्क जो सामने रखा गया है वह यह है कि

विश्वविद्यालयों आदि में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कानून बनाना

समवर्ती की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें

केवल सूची। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 और पूर्ववर्ती प्रविष्टि 11 के अंतर्गत राज्य सूची, राज्य सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं जो

अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। उदाहरण के लिए,

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, राजीव गांधी

उद्योगिकी विश्वविद्यालय आधीनियम, राष्ट्रीय विधि संगठन

विश्वविद्यालय अधिनियम आदि की स्थापना राज्य द्वारा की गई थी।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रही सरकार।

इसी तरह, केंद्र सरकार ने भी विभिन्न कानून बनाए हैं

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत उच्च शिक्षा से संबंधित

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को

विश्वविद्यालय अधिनियम 1994, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996,

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 आदि। केंद्रीय

सरकार के पास प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति हो सकती है

आई. आई. टी., एन. आई. टी., जे. आई. पी. एम. ई. आर. आदि जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान लेकिन इस संबंध में नहीं।

राज्य में चल रहे अन्य संस्थानों से।

29. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है

संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत संघ की शक्ति निर्धारित करने तक सीमित है। के स्तर में एकरूपता लाने के लिए उच्च शिक्षा के मानक

पूरे देश में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार, प्रविष्टि का दायरा 66

इसका अर्थ आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v को निर्धारित करने की वास्तविक भावना तक सीमित होना चाहिए।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

उच्च शिक्षा के मानक 'और प्रवेश निर्धारित करने के नहीं

प्रक्रिया। किसी भी मामले में राज्य को कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है।

सूची III की प्रविष्टि 25। अधिक तो, में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय।

30. मुझे दोषियों की शक्तियों को बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है

कानून जो राज्य सरकार को प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार देता है

राज्य के भीतर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रक्रिया। में। वास्तव में, राज्य के कल्याण और विकास के लिए जिम्मेदार होने के नाते

राज्य के लोगों को अपने कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

जो राज्य के विकास और विकास को सीधे प्रभावित करता है, वह बन जाता है राज्य को ऐसे कदम उठाने का विशेषाधिकार है जो कल्याण को आगे बढ़ाते हैं

लोग और विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में, राज्य

सरकार के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली एकमात्र इकाई होनी चाहिए

उस विशेष में चलने वाले संस्थानों को नियंत्रित करने वाले प्रवेश और शुल्क आदि

आई. आई. टी., एन. आई. टी. आदि जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को छोड़कर राज्य क्योंकि

आवश्यकताओं और असमानताओं का इससे बेहतर न्यायकर्ता कोई नहीं हो सकता।

उस राज्य की तुलना में किसी विशेष राज्य के लोगों के लिए अवसर। केवल

राज्य का कानून छात्रों के लिए समान स्तर का अवसर पैदा कर सकता है

जो राज्य बोर्ड और अन्य धाराओं से निकल रहे हैं।

31. क्या विवादित कानून उचित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध

गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने "व्यवसाय के अधिकार" में कहा गया है: टी. एम. ए. पाई में

मामला, ग्यारह-न्यायाधीश पीठ ने पैरा (20) और (25) में अभिनिर्धारित किया कि

शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद के अर्थ में एक व्यवसाय था।

19 (1) (छ) और यह कि शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत सभी नागरिकों को संस्था की गारंटी दी गई है।

भारत का संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए और

30 भारत का संविधान। शिक्षा की स्थापना के लिए ये अधिकार

पी. ए. इनामदार में भी संस्थान की पुष्टि की गई है।

32. अधिनियम 2007 का उद्देश्य ". के विनियमन के लिए प्रावधान करना है

निजी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश और शुल्क का निर्धारण [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान सामान्य आधार पर होगा प्रवेश परीक्षा इस तरह से जो राज्य द्वारा निर्धारित की जाए

सरकार। धारा 3 (डी) में 'सामान्य प्रवेश परीक्षा' को परिभाषित किया गया है।

का अर्थ है योग्यता के निर्धारण के लिए आयोजित एक प्रवेश परीक्षा

उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर केंद्रीकृत परामर्श के बाद

एकल खिड़की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान

राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा।

33. अपीलार्थियों का तर्क है कि धारा 6 को धारा के साथ पढ़ा जाए।

3 (घ) अधिनियम, 2007 राज्य के पक्ष में एकाधिकार बनाता है सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और यह कि यह सीधे अतिक्रमण करता है

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के मौलिक अधिकार पर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है

कि पी. ए. इनामदार मामले के पैरा (137) में केवल तभी अभिनिर्धारित किया गया है जब प्रवेश

यह दिखाने के लिए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ट्रिपल टेस्ट को संतुष्ट करने में विफल, राज्य ने प्रवेश लिया था

प्रक्रिया। टी. एम. ए. पाई के पैरा (65) पर भी बहुत जोर दिया गया। यह तर्क देने के लिए कि निजी शैक्षणिक संस्थानों को अधिकार है

छात्रों का चयन करें और राज्य द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा

निजी शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का अधिकार

एक अनुचित प्रतिबंध के लिए और उसी को निरस्त किया जा सकता है।

34. पूर्ण 'कब्जे के अधिकार' का दावा जो अपीलार्थी

टी. एम. ए. पाई, पी. ए. इनामदार मामलों के आधार पर नहीं उठाया गया है

टिकाऊ। टी. एम. ए. पाई और पी. ए. इनामदार में कोई निरंकुश अधिकार नहीं था। निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को व्यापार करने के लिए अनुदान और

द्वारा अधिनियमित वैधानिक विनियमों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना व्यवसाय

सक्षम विधायिका। एक मौलिक अधिकार बिना किसी माप के नहीं है - नियंत्रण और यह हमेशा उचित प्रतिबंध के अधीन होगा जो आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

राज्य व्यापक लोक हित में लागू करने के लिए बाध्य है। श्रीनिवास में

सामान्य व्यापारी और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1983)

4 एस. सी. सी. 353, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 17. किसी भी पेशे का अभ्यास करने का सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार

या किसी निश्चित व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के लिए

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपनी सीमाएँ हैं। एक की स्वतंत्रता

व्यक्ति द्वारा जैसा चाहे वैसा करना निरपेक्ष नहीं है। इसका पालन करना चाहिए

आम भलाई। पूर्ण या अप्रतिबंधित व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

और किसी भी आधुनिक राज्य में मौजूद नहीं हो सकता है। कोई सुरक्षा नहीं है

अधिकार स्वयं जब तक कि नियंत्रण का कोई उपाय न हो और

सभी के हितों में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का विनियमन।

35. एम. पी. अधिनियम 2007 "प्रवेश के विनियमन" के लिए अधिनियमित किया गया था।

और निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क का निर्धारण

मध्य प्रदेश राज्य में और अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, अनुसूचित जाति

जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग "। इस प्रकार अधिनियम 2007 आगे बढ़ रहा है।

समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व का

उन मेधावी उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का अवसर जो आगे बढ़ना चाहते हैं

चिकित्सा शिक्षा। अधिनियम 2007 राज्य को सामान्य संचालन करने में सक्षम बनाता है।

चिकित्सा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के हित में प्रवेश परीक्षा शिक्षा ताकि गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे शिक्षा में प्रगति हो सके।

राज्य सरकार या किसी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा इसके द्वारा अधिकृत एक उचित प्रतिबंध के बराबर है।

36. समय-समय पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हित में

जिन स्थितियों में उन्हें रखा जाता है। संदर्भ दिया जा सकता है नरेंद्र कुमार और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। वी. भारत संघ और

ओआरएस। ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 430, जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:

" 15. यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित तीन मामलों में। चिंतामन

राव (1950) 1 एससीआर 759, कूवरजी एयर 1954 एससी 220 और मध्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3

एस सी आर।

भारत एसोसिएशन लिमिटेड ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 634, न्यायालय ने विचार किया

असली सवाल यह है कि क्या हस्तक्षेप

मौलिक अधिकार "उचित" था या इसके हितों में नहीं था आम जनता और यदि प्रश्न का उत्तर में था

सकारात्मक, कानून वैध होगा और यह अमान्य होगा यदि

तर्कसंगतता का परीक्षण पारित नहीं किया गया था। इन सब में प्रतिबंध था।

मामलों को केवल एक प्रकार के "प्रतिबंध" के रूप में माना जाता है।

18. तर्कसंगतता के परीक्षण को लागू करने में, न्यायालय को

तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रश्न पर विचार करें और जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया था,

उस बुराई की प्रकृति को ध्यान में रखें जिसे दूर करने की कोशिश की गई थी ऐसा कानून, द्वारा व्यक्तिगत नागरिकों को हुए नुकसान का अनुपात

प्रस्तावित उपचार, उचित रूप से अपेक्षित लाभकारी प्रभाव के लिए

आम जनता के लिए परिणाम। इस पर भी विचार करना आवश्यक होगा। इस संबंध में कि क्या कानून के कारण प्रतिबंध अधिक है

जो आम जनता के हित में आवश्यक था।

37. लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का निर्धारण करते समय

ई अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत 'व्यवसाय की स्वतंत्रता' पर राज्य

(छ) जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जा सकता है, उनका सारांश दिया गया था।

इस न्यायालय ने एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम निरीक्षक, केरल सरकार और

(1998) 8 एस. सी. सी. 227, निम्नलिखित प्रासंगिक निष्कर्षण में:

" इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं:

प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए,

(1)

न्यायालय को निर्देशात्मक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा

राज्य की नीति।

(2)

प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए।

ताकि ब्याज की आवश्यकता से परे जा सके
आम जनता।

प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, नहीं

(3)

अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत को DERN DENTAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE v रखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

ताकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो और वही होगा

प्रत्येक मामले के साथ-साथ परिवर्तन के संबंध में भी भिन्नता होती है।

मानव जीवन की परिस्थितियाँ, मूल्य, सामाजिक दर्शन

संविधान, प्रचलित परिस्थितियाँ और आसपास

परिस्थितियाँ।

प्रतिबंधों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

(4)

अधिरोपित और अनुच्छेद (6) द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण

अनुच्छेद 19.

(5) प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताएँ जो हैं -

प्रतिबंधों से संतुष्ट होने के इरादे को वहन करना होगा
दिमाग। (देखिए: यू. पी. राज्य बनाम कौशैलिया एयर 1964 एससी

416.)

एक प्रत्यक्ष और निकटवर्ती सांठगांठ या एक उचित संबंध होना चाहिए।

(6)

लगाए गए प्रतिबंधों और वस्तु के बीच संबंध

हासिल करने की कोशिश की। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध है, तो एक मजबूत

अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान

स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। (देखिएः कवलाप्पुरा कोट्टाराथिल कोचुनी

वी. मद्रास और केरल राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1080; ओ. के. घोष बनाम। पूर्व ई. जोसेफ ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 812) ”

मद्रास राज्य बनाम में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। वी. जी

पंक्ति, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196 और के. के. कोचुनी बनाम। मद्रास राज्य

और केरल, ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1080।

38. टी. एम. ए. पाई में, जबकि इस न्यायालय ने अधिकार को स्वीकार किया

अनुच्छेद के तहत गारंटी के रूप में निजी शैक्षणिक संस्थानों का 'राशन'

(छ) भारत के संविधान के पैरा (54) में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया

अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार से संबंधित कानून

निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा के संबंध में एटोरी का अर्थ है आयतन, जो नीचे लिखे अनुसार हैः

" 54. एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार हो सकता है

विनियमित; लेकिन इस तरह के नियामक उपायों, सामान्य रूप से, होना चाहिए

उचित शैक्षणिक मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करना, [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वातावरण और अवसंरचना (योग्य कर्मचारियों सहित) और

प्रबंधन के प्रभारी लोगों द्वारा कुप्रशासन की रोकथाम।

एक कठोर शुल्क संरचना का निर्धारण, गठन को निर्धारित करना और एक शासी निकाय की संरचना, अनिवार्य नामांकन

छात्रों की नियुक्ति या नामांकन के लिए शिक्षक और कर्मचारी

प्रवेश अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।

39. टी. एम. ए. पुई में, पैरा (58) और (59) में, संविधान पीठ

दोहराया कि व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए

संस्थान, योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निम्नलिखित रूप में आयोजित किए जाते हैं:

" 58. किसी भी पेशेवर संस्थान में प्रवेश के लिए योग्यता अनिवार्य है।

एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। जबकि यह सामान्य रूप से संभव नहीं हो सकता है

उस आवेदक की योग्यता का न्याय करें जो एक स्कूल में प्रवेश चाहता है,

एक पेशेवर संस्थान में प्रवेश लेने के लिए और बनने के लिए

व्यावसायिक शिक्षा में अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी
प्रवेश चाहने वाले छात्र की योग्यता पर आधारित। उचित है।

इस उद्देश्य के लिए विनियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है

के संदर्भ में इस निर्णय में की गई अन्य टिप्पणियां

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश।

59. योग्यता आमतौर पर पेशेवरों में प्रवेश के लिए निर्धारित की जाती है और
उच्च शिक्षा महाविद्यालय, या तो उन अंकों से जो छात्र

योग्यता परीक्षा या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है

साक्षात्कार के बाद का चरण, या एक सामान्य प्रवेश परीक्षा
संस्थान द्वारा संचालित, या पेशेवर कॉलेजों के मामले में,

सरकारी एजेंसियों द्वारा "।

40. टी. एम. ए. पाई में शंकाओं/विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए,

इस्लामी शिक्षा अकादमी में संविधान पीठ का गठन किया गया था जिसमें इस न्यायालय
ने दोहराया कि पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश

सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा योग्यता पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग में

142 , इस न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में दो समितियों के गठन का निर्देश दिया।

ओडरन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायालय न्यायाधीश

एसोसिएशन द्वारा आयोजित ट्रांस परीक्षण और अनुमोदन के लिए भी

संस्थान द्वारा प्रस्तावित टूटना। के पैरा (19) और (20) में

तथापि, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

महाविद्यालय संघ द्वारा संचालित कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग समिति का गठन किया जाएगा। द.

समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

न्यायाधीश को उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना है।

राज्य। समिति के पास परीक्षणों की निगरानी करने की शक्तियां होंगी।

पेपर-सेटर और परीक्षक और अपनाई गई विधि की जांच करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात लीक न हों। समिति इसकी निगरानी करेगी।

और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए

तरीके से। समिति के पास अनुमति देने की शक्ति होगी

संस्था, जिसकी स्थापना की गई है और जिसे

अंतिम के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की अनुमति, पर कम से कम, 25 वर्ष, अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया अपनाने के लिए और यदि

समिति महसूस करती है कि ऐसे संस्थान की आवश्यकताएँ वास्तविक हैं।

आवंटित कोटा से अधिक अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देना।

राज्य सरकार द्वारा उन्हें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नहीं

संस्थान, जिसे स्थापित नहीं किया गया है और जिसका पालन नहीं किया गया है

अंतिम, कम से कम, 25 वर्षों के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया,

आवेदन करने की अनुमति दी जाए या प्रवेश से छूट दी जाए

छात्र ऊपर बताए गए तरीके से। 20. समितियों के दो समूह स्थापित करने के लिए हमारा निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राज्यों को पारित किया गया है जो उचित कानून बनने तक लागू रहेंगे।

संसद द्वारा अधिनियमित। स्थापना पर होने वाले खर्च

ऐसी समितियों का संचालन प्रत्येक राज्य द्वारा किया जाएगा। द.

ढांचागत आवश्यकताएँ और भत्ता और पारिश्रमिक का प्रावधान

समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी [2016] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

41. पी. ए. इनामदार में, इस न्यायालय ने कहा कि एक होना चाहिएराज्य सरकार द्वारा आयोजित गैर-प्रवेश परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी

राज्य में एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं और इसके पैरा (136) में

निम्नलिखित रूप में आयोजित नहीं किया गया:

" 136. चाहे अल्पसंख्यक हों या गैर-अल्पसंख्यक संस्थान, हो सकते हैं

शिक्षा प्रदान करने वाले एक से अधिक समान रूप से स्थित संस्थान

किसी भी राज्य में कोई भी एक अनुशासन। वही आकांक्षी खोज रहा है

शिक्षा के किसी भी एक विषय में शिक्षा लेने के लिए प्रवेश

कई संस्थानों से प्रवेश पत्र खरीदने होंगे।

और विभिन्न स्थानों पर आयोजित कई प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं

एक ही या अलग-अलग तारीखों पर और तारीखों का टकराव हो सकता है।

यदि एक ही उम्मीदवार को कई परीक्षणों में उपस्थित होना पड़ता है, तो वह अनावश्यक और टालने योग्य खर्च और असुविधा के अधीन होगा। प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है

समान या समान प्रदान करने वाले संस्थानों के एक समूह के लिए आयोजित

शिक्षा. एक राज्य में या उससे अधिक में स्थित ऐसे संस्थान

एक राज्य एक साथ शामिल हो सकता है और एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है या

राज्य स्वयं या किसी अभिकरण के माध्यम से धारण करने की व्यवस्था कर सकता है -

इस तरह का परीक्षण। ऐसी सामान्य योग्यता सूची में से सफल उम्मीदवार अलग-अलग लोगों को आवंटित किए जाने के लिए पहचाना और चुना जा सकता है

प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रमों के आधार पर संस्थान, संख्या

सीटों की संख्या, संस्था किस प्रकार की अल्पमत से संबंधित है और अन्य प्रासंगिक कारक। ऐसी एजेंसी जो आम संचालन करती है प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में "सी. ई. टी".) अत्यधिक आनंद लेने वाली होनी चाहिए।

इस मामले में विश्वसनीयता और विशेषज्ञता। यह बेहतर होगा कि

पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति। सीईटी है

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के हित में आवश्यक और

छात्र समुदाय को उत्पीड़न से बचाने के लिए और शोषण। इस तरह की सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बाद

केंद्रीकृत परामर्श या, दूसरे शब्दों में, एकल-खिड़की प्रणाली

प्रवेश को विनियमित करने से अधिकार में कोई कमी नहीं आती है अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों को प्रवेश देंगे

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

सफल उम्मीदवारों ने क्रम में बदलाव किए बिना सी. ई. टी. में तैयारी की। इस प्रकार चुने गए छात्रों की योग्यता।

42. पैरा (138) में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि

छात्र समुदाय का व्यापक हित और कल्याण, यह होगा

केंद्रीकृत प्रदान करके प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति और एकल-खिड़की प्रक्रिया। पैरा (138) इस प्रकार है:

यी

" 138 , यह विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि

योग्यता, उत्कृष्टता प्राप्त करना और कदाचार पर अंकुश लगाना, यह होगा केंद्रीकृत प्रदान करके प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति और

एकल-खिड़की प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया, काफी हद तक,

पारदर्शी आधार पर योग्यता आधारित प्रवेश का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

जब तक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक प्रवेश समितियाँ इसकी देखरेख कर सकती हैं।
प्रवेश ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्यता हताहत न हो।

43. संविधान पर इस्लामी अकादमी में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करना

इस विषय पर एक सुविचारित कानून बनाने के लिए, यह था
पी. ए. इनामदार में पैरा (144) और (155) में आयोजित किया गया:

" 144. प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो समितियाँ
और इस्लामी निर्णय में शुल्क संरचना का निर्धारण करना

अकादमी (2003) 6 एस. सी. सी. 697, हमारे विचार में, इस प्रकार
स्वीकार्य हैं -

छात्र के हितों की रक्षा के उद्देश्य से नियामक उपाय
समूचे समुदाय के साथ-साथ स्वयं अल्पसंख्यकों को भी

गैर पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखना

प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण की निगरानी का उल्लंघन नहीं होता
है।
अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार या अल्पसंख्यकों का अधिकार

और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गैर-अल्पसंख्यक। वे तर्कसंगत हैं।

अल्पसंख्यक संस्थानों के हित में अनुमत प्रतिबंध

अनुच्छेद 30 (1) और अनुच्छेद के तहत आम जनता के हित में

19 (6) संविधान से।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई.

· 155. यह केंद्र सरकार या राज्य के लिए है।

केंद्रीय कानून के अभाव में सरकारें सामने आएंगी

इस विषय पर एक विस्तृत सुविचारित विधान के साथ। इस तरह की
कानून लंबे समय से प्रतीक्षित है। राज्यों को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए।

दिशा। राज्य की न्यायिक शाखा को कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है जब

अन्य दो शाखाएँ, विधायिका और कार्यपालिका, कार्य नहीं करती हैं।

भारत संघ और राज्य सरकारें जितना जल्दी कार्रवाई करेंगी, उतना ही बेहतर होगा।
प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने वाली समितियाँ

और शुल्क संरचना मौजूद रहेगी, लेकिन केवल एक अस्थायी के रूप में

केंद्रीय तक उपाय और एक अपरिहार्य गुजरने वाला चरण
सरकार या राज्य सरकारें एक उपयुक्त उपाय तैयार करने में सक्षम हैं।

तंत्र और इसके अनुरूप एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करना

ऊपर की गई टिप्पणियाँ। कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी निर्णय
ऐसी समितियों द्वारा और केंद्र या राज्य द्वारा लिया गया

सरकारें, इसके अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होंगी
इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए तय किए गए मानदंड।

44. पी. ए. इनामदार के पैरा (155) में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, राज्य

सरकारों को एक विस्तृत सुविचारित रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है

इस विषय पर एक और अवलोकन के साथ कानून कि कोई भी निर्णय

समितियों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा लिया गया

तय किए गए मापदंडों के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रहें

ऐसी अधिकारिता का प्रयोग। विवादित विधान-अधिनियम 2007

टी. एम. ए. पाई, इस्लामिक अकादमी और पी. ए. इनामदार में एक दृष्टिकोण के साथ
अदालत प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

45. सामान्य प्रवेश परीक्षा-एकल खिड़की प्रणाली जो इसे नियंत्रित करती है

गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश उन लोगों के
मौलिक अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है

संस्थानः टी. एम. ए. पाई और पी. ए. इनामदार में, यह न्यायालय स्पष्ट रूप से

यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

'मेरिट' शब्द लैटिन मूल का शब्द है, जिसकी जड़ें मेरिटम से निकलती हैं।

जिसका अर्थ है 'उचित पुरस्कार' और 'मेरेरी' जिसका अर्थ है 'अर्जित करें, योग्य'। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (11 वां संस्करण) 'योग्यता' को 'उत्कृष्टता' के रूप में परिभाषित करता है।

के लायक है? . आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र पर पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत कानून शब्दकोश (तीसरा संस्करण) v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

योग्यता का विषय गुमन सिंह बनाम का उल्लेख करता है। राजस्थान राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 452, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गयाः

" ..... योग्यता विभिन्न गुणों और विशेषताओं का कुल योग है।

कर्मचारी जैसे कि उसकी शैक्षणिक योग्यता, में उसका विशिष्टता

विश्वविद्यालय, उसका चरित्र, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और

जिस तरह से वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इससे जुड़े विभिन्न अन्य मामले, या कारक हो सकते हैं, जैसे कि उनकी समयबद्धता

कार्य में, उनके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और उनके वरिष्ठों और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार का तरीका

और आम जनता, सेवा में उनका पद और वार्षिक
गोपनीय रिपोर्ट। ये सभी और अन्य कारक हो सकते हैं

योग्यता के मूल्यांकन में ध्यान में रखा जाता है "।

इसके अतिरिक्त, डॉ. प्रदीप जैन और अन्य में। वी. भारत संघ

और ओआरएस।, (1984) 3 एस. सी. सी. 654, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" ..... योग्यता में उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ-साथ एक

तीक्ष्ण और तीक्ष्ण मन, बुनियादी विषयों का अच्छा ज्ञान

और कड़ी मेहनत के लिए अनंत क्षमता और एक भावना की भी आवश्यकता होती है गरीबों के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता और समर्पण "।

46. यह सर्वविदित है कि चिकित्सा के अध्ययन की बहुत मांग है

भारत में छात्र। चिकित्सा में प्रवेश की उच्च मांग के कारण महाविद्यालय और सीटों की सीमित संख्या, चयन और/या जांच के तरीके

क्रीम डी ला क्रीम का चयन करने के लिए विकसित हुए हैं। की सतह को देखते हुए

शैक्षणिक रूप से अच्छी तरह से योग्य आवेदकों, चयन विधि होनी चाहिए असाधारण रूप से उच्च शैक्षणिक स्थान देकर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनें

सीमाएँ। यह इस संदर्भ में है कि 'योग्यता' निर्धारित करने में काम आती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए मानदंड।

47. योग्यता किसी भी व्यक्ति के मूल्य का संचयी मूल्यांकन है।

विभिन्न जाँच विधियों के आधार पर। आदर्श रूप से, एक होना चाहिए सरकार दोनों के लिए राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा

महाविद्यालयों और निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए,

कौरव, एडिशनल। मध्य प्रदेश राज्य के लिए महाधिवक्ता ए. एफ. आर. सी. के लिए उपस्थित होना, राज्य द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा है

:

अधिक लाभप्रद। : - ((i) निर्धारित समय-सारणी का पालन करना।

पूरे राज्य में परीक्षा और परामर्श और एक एकल खिड़की प्रवेश के लिए प्रणाली; (iii) मानक प्रश्न पत्र,

प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ, प्रश्न के रिसाव की रोकथाम

कागजात और निष्पक्ष मूल्यांकन और (iv) न्यूनतम मुकदमेबाजी। इसके अलावा, प्रक्रिया

विभिन्न महाविद्यालयों को योग्यता सूची, परामर्श और आवंटन तैयार करने के लिए के अधिकार के अधीन है। सूचना अधिनियम और इस प्रकार निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और

पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता।

48.प्रवेश से संबंधित प्रचलित शर्तों को ध्यान में रखते हुए

मध्य राज्य में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में

प्रदेश, विधानमंडल ने अपने विवेक में यह विचार रखा है कि योग्यता

आधारित प्रवेश केवल एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

इसके बाद राज्य या किसी एजेंसी द्वारा केंद्रीकृत परामर्श दिया जाता है।

राज्य द्वारा अधिकृत। इच्छुक आवेदकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए

के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए

भारत, विवादित कानून द्वारा विधायिका ने प्रणाली की शुरुआत की

योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.)

पारदर्शी आधार। यदि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान दिए जाते हैं

संस्थाएं। राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य और योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर

विभिन्न संस्थानों को आवंटित किए जाने के लिए उम्मीदवारों की पहचान की जा सकती है अध्ययन के पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विषयों के आधार पर

कारक। यह जुड़वां वस्तुओं को सुनिश्चित करेगा: - ((i) निष्पक्षता और पारदर्शिता

छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण के संबंध में योग्यता को बढ़ावा देना और उत्कृष्टता प्राप्त करना और दुराचारों पर अंकुश लगाना,

राज्य के लिए प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति होगी

केंद्रीकृत और एकल खिड़की प्रक्रिया। इस तरह के सी. ई. टी. का आयोजन किया गया

केंद्रीकृत परामर्श या एकल खिड़की प्रणाली द्वारा प्रवेश को विनियमित करना

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v में संस्थानों के मौलिक अधिकारों पर कोई सेंध नहीं लगाती है।

संस्थान को चलाना। जबकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को एक 'अधिकार' है

शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में व्यवसाय के क्रम में, समान रूप से उनके पास मेधावी और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेदारी है।

उत्कृष्टता के साथ पेशेवरों को बाहर लाना। निजी शिक्षा के अधिकार

संस्थानों को समुदाय के व्यापक हित के लिए झुकना होगा।

49. सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करके और मेधावी की पहचान करके

उम्मीदवारों, राज्य केवल उम्मीदवारों की योग्यता सूची प्रदान कर रहा है

एक निष्पक्ष सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया। यदि जाँच

परीक्षण योग्यता के आधार पर आयोजित किया जाता है, निजी को कोई नुकसान नहीं होगा

शैक्षणिक संस्थान। प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है

संस्थानों के स्वीकृत प्रवेश में छात्र और न ही उनके अधिकार पर

छात्रों से शुल्क एकत्र करें। निजी शिक्षा की स्वतंत्रता

संस्थान स्थापित करना और चलाना, शिक्षा प्रदान करना, कर्मचारियों की भर्ती करना,

अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, छात्रों को प्रवेश दें, शुल्क निर्धारण में भाग लें

किसी भी तरह से विवादित कानून द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा रहा है; यह बरकरार है।

50. प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए,

न्यायालय को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा: किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता तय करने के लिए

या कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए

किसी भी मौलिक अधिकार का प्रयोग, अदालत को ध्यान में रखना होगा

अधिक से अधिक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक या सामाजिक हित। बॉम्बे और अन्र राज्य में। वी. एफ. एन. बलसारा

[1951] एस. सी. आर. 682, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि

मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता,

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। संविधान के भाग IV में, चुनौती की जांच करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के संदर्भ में कानून की संवैधानिक वैधता

संविधान। गुजरात राज्य में बनाम। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब

जमात और ओआरएस। (2005) 8 एस. सी. सी. 534, इस न्यायालय ने कहा कि वध पर प्रतिबंध

गाय की संतान पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह केवल एक उचित प्रतिबंध है। ए.

सात-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने पैरा (41) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

}

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 41. केशवानंद भारती का संदेश (1973) 4 एससीसी 225

या समग्र रूप से समुदाय। की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए
मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध

विचार केवल वे नहीं हैं जो अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 19 में बताए गए हैं।

संविधान का भाग III: भाग में बताए गए निर्देशक सिद्धांत

IV भी प्रासंगिक हैं। बदलती तथ्यात्मक परिस्थितियाँ और राज्य की नीति,

आक्षेपित अधिनियम में परिलक्षित एक को शामिल करते हुए, होना चाहिए

निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा विचार किया गया और उन्हें महत्व दिया गया

विधायी अधिनियमों की संवैधानिक वैधता। एक प्रतिबंध

सिद्धांतों को उचित माना जाएगा और इसलिए उन्हें अधिकार क्षेत्र के भीतर विषय
माना जाएगा। दो सीमाएँ: सबसे
पहले, कि यह स्पष्ट संघर्ष में नहीं चलता है

मौलिक अधिकार, और दूसरा, कि इसे इसके भीतर अधिनियमित किया गया है

भाग के तहत अधिनियमित करने वाले विधानमंडल की विधायी क्षमता

संविधान का 11 वाँ अध्याय I "।

51. संविधान के तहत यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि

प्रावधानों सहित अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्माण

बुनियादी उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य के आश्वासन के लिए

रहने और काम करने की स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 39 (ई), 39 (एफ) और 42 के तहत
स्वास्थ्य और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए संविधान, दायित्व राज्य पर डाल दिए गए हैं

श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं को; सुनिश्चित करें कि बच्चों को अवसर दिए जाएं और

स्वस्थ तरीके से विकसित करने और न्यायपूर्ण और मानवीय रूप से सुरक्षित करने के लिए
सुविधाएं क्रमशः काम की शर्तें और प्रसूति राहत के लिए। का अनुच्छेद 47

संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य बनाता है -

राज्य। हालाँकि, स्वास्थ्य का अधिकार अब एकमात्र क्षेत्र में नहीं है

संविधान का भाग IV। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम। कर्मचारियों का

राज्य बीमा निगम। (1996) 2 एस. सी. सी. 682, यह माना गया था कि

स्वास्थ्य श्रमिकों का एक मौलिक अधिकार है और स्वास्थ्य का रखरखाव सबसे अनिवार्य संवैधानिक लक्षय है जिसे प्राप्त करने के लिए बातचीत की आवश्यकता होती है। कई सामाजिक और आर्थिक कारक। राजस्थान प्रदेश में वैद्य

समिति, सरदारशहर और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य

(2010) 12 एस. सी. सी. 609, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस देश के नागरिकों के पास आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v है।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार जिसमें शामिल हैं -

जनता के स्वास्थ्य और जीवन को दुर्भावनापूर्ण चिकित्सा से बचाना और सुरक्षित रखना। उपचार। हाल ही में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन v.

भारत संघ (2013) 9 एस. सी. आर. 1103, फिर से इस न्यायालय ने मान्यता दी है

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है।

52. सार्वजनिक स्वास्थ्य का रखरखाव और सुधार और प्रदान करना

स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सेवाएँ संवैधानिक दायित्व है

राज्य। इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, राज्य के पास होना चाहिए पेशेवर उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता वाले डॉक्टर जो तैयार हैं

अपने संवैधानिक दायित्व का संतोषजनक निर्वहन तभी करें जब इच्छुक व्यक्ति छात्र योग्यता के आधार पर पेशे में प्रवेश करते हैं। इनमें से कोई भी ऊँचा नहीं

अच्छे और प्रतिबद्ध चिकित्सा के बिना आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है।

पेशेवरों।

53. निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के मौलिक अधिकार

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित और छात्रों के अधिकारों के प्रति झुकना चाहिए: सही है।

निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाना और गैर-मनमाना, गैर-मनमाने तरीके से प्रवेश प्राप्त करना।

भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया एक मौलिक अधिकार है - अनुच्छेद 14 के तहत छात्र। कोई भी कानून जो एक कृत्रिम कानून बनाता है

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों और अन्य संस्थानों के बीच वर्गीकरण

छात्र को किसी निजी संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान केवल इसलिए क्योंकि इस तरह के संस्थान का एक निरंकुश अधिकार है

वर्दी का पालन किए बिना और पारदर्शी तरीके से अपने छात्रों का चयन करना।

अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत छात्र। छात्रों का प्रवेश का अधिकार निजी गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में अवसर में समानता का अधिकार है।

कई मौकों पर इससे मौलिक अधिकारों के बीच टकराव हुआ है एक ओर निजी शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार और

दूसरी ओर छात्र और बड़े पैमाने पर जनता। हालाँकि, अब कानून तय हो गया है।

ऐसे मामलों में जहां मौलिक अधिकार के बीच संघर्ष है दो पक्षकार, यह न्यायालय शारदा बनाम में पैरा (59) में है। धर्मपाल (2003) 4

एस. सी. सी. 493 ने माना कि केवल वही अधिकार जो सार्वजनिक नैतिकता को आगे बढ़ाएगा।

या जनहित प्रबल होगा। कुरैशी कसाब मामले में पैरा (39) में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3 एस सी आर।

(ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब एक मौलिक अधिकार के साथ टकराव होता है

समाज के व्यापक हित के लिए, इसे समाज के हित को स्वीकार करना चाहिए। नागरिकों का हित

राष्ट्र की जनता का व्यापक रूप से और छात्रों का लाभ उठाने का अधिकार व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक में योग्यता आधारित प्रवेश का अवसर

संस्थान लोक हित को और इस तरह के अधिकारों को आगे बढ़ाएँगे

छात्र निजी गैर-सहायता प्राप्त के अधिकारों पर हावी होंगे व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान।

54. पुनः विवादः यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त

पेशेवर शैक्षणिक संस्थान तीन परीक्षणों में विफल रहे-निष्पक्षता, पारदर्शिता और गैर-शोषणकारीताः निर्णय के पैरा (137) में

पी. ए. इनामदार में, इस न्यायालय ने कहा है कि यदि प्रवेश प्रक्रिया निजी संस्थानों द्वारा अपनाया गया सभी या किसी भी ट्रिपल परीक्षण को संतुष्ट करने में विफल रहता है,

तब प्रवेश प्रक्रिया को राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है

अपनी प्रक्रिया और अन्यथा नहीं। अपीलार्थियों का तर्क है कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निजी शैक्षणिक संस्थान

एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी प्रवेश सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थे प्रक्रिया और यह कि राज्य को सशक्त बनाने वाला विवादित कानून या

सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए उसके द्वारा नामित एजेंसी उल्लंघन में है

इस न्यायालय के निर्देश। जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उन्होंने इस प्रकार देखा है:

" ..... हमारे समक्ष पर्याप्त सामग्री दाखिल की गई है

प्रत्यर्थियों को यह दिखाने के लिए कि अधिनियम 2007 के अधिनियमन से पहले,

इस न्यायालय के साथ-साथ आदेशों के अनुसार गठित समिति

इस्लामी शिक्षा अकादमी में सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर)

में प्रवेश में दुराचार की शिकायतों की जांच करनी पड़ी

निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान और खोजने के बाद
शिकायतें सही होने के लिए, संस्थानों को प्रवेश देने का निर्देश दिया

अगले शैक्षणिक सत्रों में पीड़ित छात्र और यह

यह दिखाएगा कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान

निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषण सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थे
अधिनियम, 2007 से पहले प्रवेश प्रक्रिया अधिनियमित की गई थी।

55. डी. एम. ए. टी. 2006 मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर v. के विज्ञापन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

मध्य प्रदेश के निजी कॉलेजों में एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो 16.07.2006 पर आयोजित किया जाना है और रिट की संख्या

डी. एम. ए. टी. 2006 से संबंधित छात्रों द्वारा दायर याचिकाएँ। यह प्रस्तुत किया गया था

कि डब्ल्यू. पी. में (ग) 2006 का सं. 1796, उच्च न्यायालय ने डी. एम. ए. टी. 2006 पर रोक लगा दी और

राज्य को इस्लामी अकादमी के अनुसार एक समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया

शिक्षा और डी. एम. ए. टी. का प्रबंधन करने वाली समिति ने डी. एम. ए. टी. 2006 को रद्द कर दिया।

शिकायतों और मुकदमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय

यह देखने में सही था कि इसके सामने पर्याप्त सामग्री रखी गई थी

यह दर्शाने के लिए कि अधिनियम 2007 के अधिनियमन से पहले, उच्च न्यायालय के साथ-साथ

समिति को कदाचार की शिकायतों की जांच करनी थी। में

प्रवेश। यह कोई सामग्री नहीं होने का मामला नहीं है, जहां राज्य नहीं होगा

प्रवेश प्रक्रिया को संभालने में न्यायसंगत।

56. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

राज्य सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ ए. एफ. आर. सी. के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई थीं।

निजी कॉलेजों और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

अनियमितताओं और दुराचारों का आरोप लगाना। हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है प्रिया गुप्ता बनाम में इस न्यायालय के आदेश का कथित उल्लंघन। की स्थिति

मध्य प्रदेश और श्री पुरुषेंद्र कौरव ने ए. ए. जी. की उपस्थिति सीखी। ए. एफ. आर. सी. के लिए-प्रस्तुत किया है कि अनुरोधों के बावजूद, निजी कॉलेज

जानबूझकर प्रत्येक के बाद राज्य कोटे के तहत खाली सीटों की सूचना नहीं दी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परामर्श का दौर

और इस संदर्भ में कई पत्रों पर भरोसा किया है (अनुलग्नक ए-14 से

आई. ए. 83/2015) ने चिकित्सा निदेशक द्वारा निजी कॉलेजों को संबोधित किया

शिक्षा, मध्य प्रदेश। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2013 में

2014 एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लगभग 300 अनियमित प्रवेश थे।

राज्य के कोटे पर और कथित उल्लंघन पर निजी मेडिकल कॉलेज,

ए. एफ. आर. सी. ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विभिन्न निजी कॉलेजों पर 13.10 करोड़।

[2016] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाद में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई (अनुबंध ए-17 से

आई. ए. 83/2015)। जुर्माने की पुष्टि करने वाला आदेश रिट का विषय है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाएँ और मैं इसमें जाने का प्रस्ताव नहीं करता

इस पहलू के गुण। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि प्रथम दृष्टया

यह इंगित करने के लिए सामग्री कि निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षिक

संस्थानों ने पी. ए. इनामदार में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया है। में।

इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह अनुचित नहीं लगता है

इसे आधारित सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करना निजी संस्थानों में प्रवेश।

57. क्या निर्धारण के संबंध में अधिनियम 2007 के प्रावधान

संस्थान: जैसा कि पहले कहा गया है, मध्य प्रदेश अधिनियम 2007 का उद्देश्य प्रवेश के विनियमन और शुल्क के निर्धारण के लिए प्रावधान करना है

मध्य प्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान और संबंधित व्यक्तियों को सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े लोगों के लिए व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं और मामले

उससे जुड़ा हुआ या उससे आनुषंगिक "। अधिनियम अधिकृत करता है कि

राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस तय करेगा,

प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और सुनिश्चित करने के बाद भी

निजी शैक्षणिक संस्थानों को सुनने का अवसर।

58. धारा 3 (ई) के अनुसार, 'शुल्क' का अर्थ है शिक्षण शुल्क सहित सभी शुल्क।

और विकास शुल्क। अधिनियम की धारा 4 संविधान से संबंधित है।

और समिति के कार्य। धारा 4 (1) के अनुसार समिति है -

प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए गठित और निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित करने के लिए।

धारा 9 उन कारकों से संबंधित है जिन पर विचार किया जाना चाहिए

शुल्क के निर्धारण के लिए समिति जो निजी द्वारा ली जा सकती है

शैक्षणिक संस्थान। धारा 9 निम्नानुसार है:

9. कारक - (1)
ध्यान में रखते हुए:

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v.

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

(i) निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक का स्थान

संस्था;

((ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

((ग) भूमि और भवन की लागत;

((iv) उपलब्ध आधारभूत संरचना, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और

उपकरण;

((v) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय;

(vi) विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष

पेशेवर संस्थान;

आर

((vii) कोई अन्य प्रासंगिक कारक,

समिति निर्धारित करेगी, निर्धारित तरीके से

निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षिक द्वारा लिया जाने वाला शुल्क संस्था।

(2) समिति संस्थान को एक अवसर देगी -

बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क नहीं, जो समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, यह शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर होगा।

59. धारा 9 में बताए गए विभिन्न कारक जिनमें उचित भी शामिल हैं

संस्थान और अन्य के विकास और विकास के लिए आवश्यक अधिशेष

शुल्क निर्धारित करने से पहले, समिति को एक अवसर देना चाहिए उन संस्थानों को सुना जा रहा है जो आवश्यक प्रदान कर सकते हैं

जानकारी दी। यह सुनिश्चित करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

शुल्क से संबंधित अपने वैध दावों को आगे बढ़ा सकते हैं जो होना है

इन संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शुल्क लिया जाता है। हालांकि अनुभाग

अधिनियम 2007 की धारा 4 (1), 4 (8) और धारा 9 के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रावधान "सार रूप में समिति को केवल संतुष्ट करने का अधिकार देते हैं

कि एक निजी पेशेवर शैक्षिक द्वारा प्रस्तावित शुल्क

संस्थान मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं थे

शिक्षा और धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित थी। अधिनियम 2007 का।

60. अपीलार्थियों का तर्क है कि धारा 4 (1), 4 (8) और

अधिनियम 2007 में शुल्क निर्धारण से संबंधित धारा 9 उनका उल्लंघन करती है।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत "व्यवसाय का अधिकार"

भारत का संविधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब ग्यारह की न्यायाधीश पीठ

टी. एम. ए. पाई में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया "। शुल्क के बारे में निर्णय

शुल्क अनिवार्य रूप से निजी शिक्षा पर छोड़ दिया जाना चाहिए

ऐसी संस्था जो किसी भी धन की तलाश नहीं करती है या उस पर निर्भर नहीं है

सरकार से "। , तब निजी संस्थानों के पास एक अक्षम्य है

अपनी खुद की शुल्क संरचना तय करने का अधिकार और इसके लिए कोई अवसर नहीं है सरकार को। समिति को सशक्त बनाने के लिए ऐसा कानून बनाना

प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करें।

61. टी. एम. ए. पाई के पैरा (39) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह भी है

यह तर्क दिया गया कि टी. एम. ए. पाई निजी के महत्व को पहचानते हैं

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी संख्या कितनी है सरकारी कॉलेज स्थिर रहे हैं जबकि निजी कॉलेजों की संख्या स्थिर रही है।

शैक्षणिक संस्थानों में वृद्धि हुई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि

आक्षेपित विधान द्वारा और इसलिए धारा 4 (1), 4 (8) और धारा 9 अधिनियम 2007 निरस्त किए जाने योग्य हैं।

62. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

समिति को निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने वाले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

शुल्क जो केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लिया गया शुल्क अत्यधिक नहीं है

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का व्यवसाय। यह था। प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने धारा 4 (1), 4 (8) और 9 को पढ़ा है

अधिनियम 2007 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समिति को केवल यह संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि

एक पेशेवर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क राशि नहीं थी आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v की धारा 9 में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाना।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

अधिनियम। विचार के लिए सवाल यह है कि क्या और क्या

जिस हद तक राज्य शुल्क संरचना पर प्रतिबंध लगा सकता है निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान।

63. संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि "राज्य,

अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान।

अनुच्छेद 41 किसी आयु वर्ग को निर्धारित नहीं करता है जिसके लिए यह अधिकार होना चाहिए। सुरक्षित किया गया। अनुच्छेद 41 में निर्धारित राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है -

यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान की जाए

और इसमें उत्कृष्टता सुनिश्चित करना। अधिनियम 2007 को आगे बढ़ाते हुए निर्देश के रूप में राज्य पर अधिरोपित संवैधानिक दायित्व

राज्य नीति के सिद्धांत।

64. शब्द "राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा।

क्षमता. "अनुच्छेद 41 में राज्य को निजी सेवाओं की अनुमति देने का अधिकार है।

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्वयं का प्रशासन करना। द.

कठिन वास्तविकता यह है कि निजी शैक्षणिक संस्थान एक आवश्यकता हैं

वर्तमान संदर्भ और टी. एम. ए. पाई ने पैरा (39) में इसे मान्यता दी है।

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का महत्व। पैरा (39) पढ़ता है

निम्नानुसार: - -

इस तथ्य से स्पष्ट है कि सरकार की संख्या-बनाए रखी गई
पेशेवर कॉलेज कमोबेश स्थिर रहे हैं, जबकि

अधिक निजी संस्थानों की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए,

कर्नाटक राज्य में 19 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से

केवल 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इसी तरह,

कर्नाटक के 14 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में से केवल एक ने

सरकार द्वारा स्थापित, जबकि उसी राज्य में, 51 में से

इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल 12 द्वारा स्थापित किए गए हैं

सरकार। उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण संकेत देते हैं -
निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका, दोनों अल्पसंख्यक

और गैर-अल्पसंख्यक, जो इच्छुक छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं
व्यावसायिक शिक्षा "।

65. यह देखते हुए कि [2016] 3 एस. सी. आर. में शिक्षा लंबे समय से एक व्यवसाय रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

मॉडर्न स्कूल वी। भारत संघ और ओआरएस। (2004) 5 एस. सी. सी. 583, पैरा (3) से (5) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 3. आधुनिक समय में, पूरी दुनिया में, शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय है।
18-6-1996 पर, प्रोफेसर जी. रॉबर्ट्स, समिति के अध्यक्ष

कुलपतियों और प्राचार्यों ने टिप्पणी की:

" उच्च शिक्षा क्षेत्र का वार्षिक कारोबार अब

भागीदारी जिसने इस आंकड़े को जन्म दिया है, और तैयारी करने की आवश्यकता है आगे की
वृद्धि के लिए, अब हम क्रांतिकारी बनाने की मांग करते हैं

अग्रिम, जिस तरह से हम संरचना करते हैं, प्रबंधन करते हैं और अधिक धन देते हैं
शिक्षा "।

4. उच्च शिक्षा कानून (द्वितीय संस्करण) नामक पुस्तक में

डेविड पाल्फ्रेमैन और डेविड वार्नर, यह कहा जाता है कि आधुनिक में

आज के समय में दुनिया भर में शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय है। इसकी वजह से

उपभोक्तावाद, दुनिया भर के छात्र बेचैन हैं। वे स्कूल
निजी क्षेत्र में जो शुल्क लेता है वह धर्मार्थ हो सकता है

वे लाभ कमाने वाले उद्यमों के रूप में नहीं चलाए जाते हैं। वह शैक्षिक दान

के बजाय जनता के लाभ के लिए स्थापित किया जाना चाहिए
व्यक्तियों का लाभ। कि जबकि व्यक्तियों को प्राप्त हो सकता है

एक शैक्षिक दान से लाभ, दान का मुख्य उद्देश्य

यह जनता के हित में होना चाहिए।

5. शुरुआत में, हम यह स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी करते हैं कि हालांकि हम इसमें हैं

ऊपर उद्धृत लेखकों के साथ समझौता, हम नहीं चाहते हैं

सामान्यीकरण और भारतीय संदर्भ में हम कह सकते हैं कि

अच्छे स्कूल जो आज भी प्रशंसनीय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं।

धर्मार्थ वस्तुएँ "।

66. इसके अलावा, टी. एम. ए. पाई के पैरा (61) में, यह न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ

यह विचार था कि मानकों को निजी शिक्षा द्वारा बनाए रखा जाता है।

संस्थान उच्चतर हैं और यह आम जनता के हित में है कि अधिक

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाते हैं और ऐसे शैक्षणिक संस्थान

संस्थानों को छात्रों के प्रवेश और शुल्क का अधिकार होगा

आरोप लगाया। हालांकि, टी. एम. ए. पाई के पैरा (69) ने निजी शिक्षा आयोजित की।

संस्थान कैपिटेशन शुल्क लेने के हकदार नहीं थे। पैरा (69) के रूप में पढ़ा जाता है इसके अंतर्गत:

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र v. मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

" 69. ऐसे व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में, प्रबंधन
योग्यता के अनुसार शिक्षकों का चयन करने का अधिकार होगा और

राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें

चयन की तर्कसंगत प्रक्रिया को अपनाना। एक तर्कसंगत शुल्क

प्रबंधन द्वारा संरचना को अपनाया जाना चाहिए, जो कैपिटेशन शुल्क लेने का हकदार नहीं होगा। उपयुक्त मशीनरी कर सकते हैं
राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाए कि कोई कैपिटेशन न हो

शुल्क लिया जाता है और यह कि कोई मुनाफाखोरी नहीं है, हालांकि एक उचित

शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अधिशेष की अनुमति है। शर्तें।
मान्यता या संबद्धता प्रदान करने में व्यापक रूप से शैक्षणिक और

छात्रों के कल्याण सहित शैक्षिक मामले और

शिक्षक "।

67. उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, इस्लामी अकादमी में

क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान उन्हें ठीक करने के हकदार हैं अपनी शुल्क संरचना। इस न्यायालय ने निजी याचिका को सुसंगत बनाने के लिए

शुल्क को मंजूरी देने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति संरचना या कुछ अन्य शुल्क का प्रस्ताव करें जो संस्थान द्वारा लिया जा सकता है।

इस्लामी शिक्षा अकादमी के पैरा (7) में इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि

इसके अंतर्गत:

" 7. ..... हम निर्देश देते हैं कि निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए

टी. एम. ए. पाई मामला संबंधित राज्य सरकारें/संबंधित

प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में एक समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा

उस राज्य का न्याय। समिति तब तय करेगी कि क्या
उस संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित हैं और नहीं हैं

मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क लेना। समिति में होगा

शुल्क संरचना को मंजूरी देने या किसी अन्य शुल्क का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता

जिसका शुल्क संस्थान द्वारा लिया जा सकता है। द्वारा निर्धारित शुल्क

समिति अंत में तीन साल की अवधि के लिए बाध्यकारी होगी।

संस्थान किस अवधि के लिए स्वतंत्र होगा? आवेदन करने के लिए

पुनरीक्षण। "सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 3

एस सी आर।

68. टी. एम. ए. पाई के पैरा (69) और (70) का उल्लेख करते हुए और दोहराते हुए

निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क इस प्रकार नहीं होना चाहिए -

पी. ए. इनामदार मामले में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

ऐसे स्थान जहाँ गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों को अधिक दिया जाना चाहिए प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना के निर्धारण में स्वायत्तता।

राज्य विनियमन न्यूनतम होना चाहिए और केवल बनाए रखने की दृष्टि से होना चाहिए

प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता और जांच करना अत्यधिक धन वसूलकर छात्रों का शोषण या

कैपिटेशन शुल्क।

139. एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना भी एक घटक है

पाई फाउंडेशन में। प्रत्येक संस्थान अपना शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र है। संरचना इस सीमा के अधीन है कि कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती

और कोई कैपिटेशन शुल्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जा सकता है, या

पाई का कोई भी रूप (पैरा 56 से 58 और 161 [प्रश्न 5 (ग) का उत्तर]

इस संबंध में फाउंडेशन प्रासंगिक हैं)।

कैपिटेशन शुल्क

140. कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और कोई सीट नहीं है।

कैपिटेशन शुल्क के भुगतान द्वारा विनियोजित किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। " "व्यवसाय" को "व्यवसाय" या केवल एक व्यवसाय से अलग करना होगा।

" पेशा "। व्यवसाय में रहते हुए, और कुछ हद तक

पेशा, एक लाभ उद्देश्य है, पेशा मुख्य रूप से एक सेवा है

जो कैपिटेशन शुल्क के भुगतान से पेशेवर डिग्री प्राप्त करता है, एक बार एक पेशेवर के रूप में योग्य, इसके बजाय कमाई पर अधिक लक्षय रखने की संभावना है

सेवा करने के बजाय यह समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। का प्रभार

गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा कैपिटेशन शुल्क

पेशेवर पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं है। इसी तरह, मुनाफाखोरी

शिक्षा के व्यावसायीकरण की कठिन वास्तविकताओं की ओर आंखें मूंद लें और बड़े आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अर्जित करने के लिए कई संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही बुरी प्रथाएँ।

मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.]

उनके निजी या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए राशि। यदि कैपिटेशन शुल्क और मुनाफाखोरी की जाँच की जानी है, प्रवेश का तरीका होना चाहिए

विनियमित किया जाता है ताकि प्रवेश योग्यता पर आधारित हों और

पारदर्शिता और छात्रों का शोषण नहीं किया जाता है। इसकी अनुमति है।

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करना।

बस कहा "।

69. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अभ्यास में

उनके "व्यवसाय के अधिकार" का, निजी संस्थान उल्लंघन नहीं कर सकते हैं

छात्रों के अधिकार। स्पष्ट रूप से, यह अधिनियम बेलगाम शक्ति नहीं देता है शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को। शुल्क का निर्धारण होना चाहिए

अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित कारकों के आधार पर। इसके अलावा, एक अधिनियम 2007 में पीड़ितों को अपील करने का अवसर भी प्रदान किया गया है।

महाविद्यालयों के अपने प्रशासन को चलाने के मौलिक अधिकारों में निर्धारण शामिल है

शुल्क से। हालांकि, इस तरह के अधिकार को बदले में अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए

छात्र, ताकि वे शोषण के अधीन न हों मुनाफाखोरी।

70. पूर्वगामी चर्चा के लिए, मेरा मानना है कि राज्य के पास है विवादित विधान-अधिनियम 2007 को लागू करने के लिए विधायी क्षमता व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंसंस्थान और शुल्क निर्धारित करने के लिए और उच्च न्यायालय ने

उचित रूप से बरकरार रखा है विवादित विधान की वैधता। नियम लागू करने की मांग की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश पर विवादित कानून द्वारा राज्य द्वारा संचालित और शुल्क का निर्धारण अनुपालन में हैं टी. एम. ए. पाई, इस्लामिक अकादमी में निर्देश और अवलोकनशिक्षा और पी. ए. इनामदार। प्रवेश प्रक्रिया पर नियम हैं -

व्यापक लोक हित और छात्र के कल्याण के लिए आवश्यक प्रवेश में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और योग्यता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। शुल्क निर्धारण पर विनियमन सुरक्षा के लिए है उच्च शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने में छात्रों के अधिकार मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन होना। के साथ

उपरोक्त तर्कों में, मैं वैधता को बनाए रखने में बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हूं।

विवादित विधान की और के योग्य निर्णय की पुष्टि करता है

उच्च न्यायालय।

* +

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।